



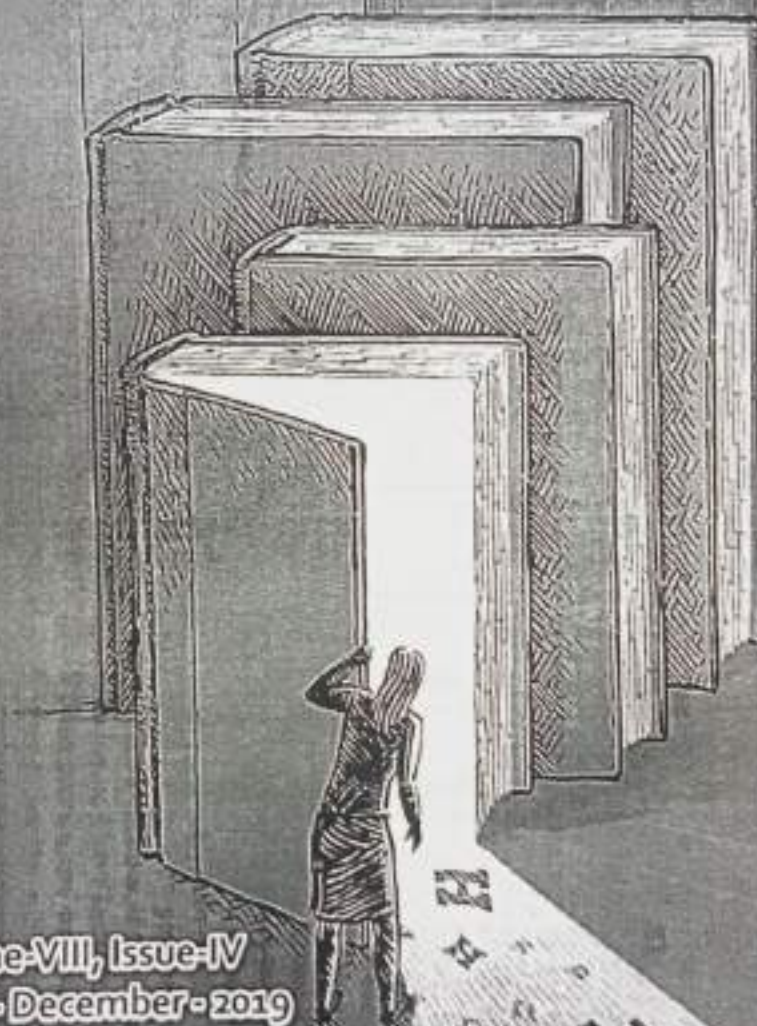
Peer Reviewed Referred
and UGC Listed Journal
(Journal No. 40776)



ISSN 2277 - 5730

AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY
QUARTERLY RESEARCH JOURNAL

AJANTA



Volume-VIII, Issue-IV
October - December - 2019
Part-I

Impact Factor / Indexing
2019 - 6.399
www.sjifactor.com

Ajanta Prakashan

CONTENTS OF PART - I

अ. क्र.	लेख आणि लेखकाचे नाव	पृष्ठ क्र.
१	विदर्भातील आदिवासी साहित्य डॉ. अजय पेत्रस बोरकर	१-३
२	वैदर्भीय कवी शंकर घोरसेंच्या 'वा स्वातंत्र्या' या काव्यसंग्रहातील समाजवास्तव डॉ. अशोक भक्ते	४-६
३	वैदर्भीय दलित - आंबेडकरी नाटककार व त्यांची नाटके प्रा. डॉ. विद्याधर बंसोड	१०-१५ ✓
४	पोवाडा : एक स्मृतिगान डॉ. चंद्रकुमार राहुले	१६-२१
५	वैदर्भीय आदिवासी साहित्यातील लोकगीते प्रा. डॉ. रामलाल रूपचंद चौधरी	२२-२७
६	वैदर्भीय ग्रामीण कथा डॉ. हेमचंद्र दुधगवळी	२८-३३
७	पूर्व विदर्भाची झाडी बोली प्रा. जगदिश र. भैसारे	३४-३९
८	पूर्व विदर्भातील नाट्य परंपरा : एक अवलोकन श्री जनबंधू भैश्राम	४०-४४
९	विदर्भातील ब्रह्मपुरी परिसरातील झालीबोली काव्याचे उन्मेष प्रा. डॉ. धनराज ल. खानोरकर	४५-५०
१०	विदर्भातील महानुभावांची साहित्य परंपरा प्रा. डॉ. किरण प्रभाकर वाघमारे	५१-५५
११	लोकगीतातील नमनगीते डॉ. न. ह. खोडे	५६-६२
१२	यवतमाळ जिल्ह्यातील आदिवासी आंधाच्या लोकगीतांतील नातेसंबंध प्रा. डॉ. राजेश धनजकर	६३-६७
१३	वैदर्भीय निवडक दलित आत्मकथने प्रा. डॉ. संजय के. लाटेलवार	६८-७४
१४	वैदर्भीय दलित काव्याचे उन्मेष डॉ. उज्ज्वला घंजारी	७५-८०

३. विदर्भातील - आंबेडकरी नाटककार व त्यांची नाटके

प्रा. डॉ. विद्याधर बनसोडे

मराठी विभागप्रमुख, सरदार पटेल महाविद्यालय, चंद्रपूर.

विदर्भातील नाटककार: विदर्भामध्ये नाटकांची फार जुनी परंपरा आहे. विदर्भातील आद्य नाटककार म्हणजे श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर. विदर्भात अनेक नामवंत नाटककार होऊन गेले. मोरोपंत जोशी, बीर वामनराव जोशी, ना. रा. वामनरावकर, पु. भा. भावे, विद्याधर गोखले, राम गणेश गडकरी, पुरुषोत्तम दारव्हेकर, महेश एलकुचवार, वि. रा. हंबर्डे, डॉ. मधुकर आष्टीकर, नानासाहेब दिगेकर, बाल नाटककार प्रभाकर पुराणिक, दिनकर देशपांडे, श्रीमती हिराबाई पेडणेकर, सौ. सुमतीदेवी धनवडे, सौ. प्रतिभा कुळकर्णी आणि असेच तोलामोलाचे अनेक नाटककार होऊन गेले. परंतु या नाटकांमधून दलित जीवनाला स्पर्शही झाला नव्हते. त्यात दलित व्यथा आणि वेदना असणे तर दूरच. स्वातंत्र्योत्तर शिकलेला दलित असा प्रश्न विचारायला लागला की ह्या नाटकांमध्ये आमचे जीवन कुठे आहे..?

विदर्भातील दलितांमधील पहिले नाटककार किसन फागू बनसोडे आहेत. जन्म १८७९ आणि मृत्यू १९४६. बनसोडेचा जन्म नागपूर जिल्ह्यातील मोहपा येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चळवळपूर्व काळात दलित चेतनेची जी मशाल गोपाळनाक विद्वत्लनाक बलंगकरांनी लावली होती त्याचा परिणाम म्हणजे किसन फागूजी बनसोडे. त्यांनी ९ ऑक्टोबर १९०३ ला सन्मार्गबोधक अस्मृश्य समाज संस्था काढली. त्यांनी स्वतःची प्रिंटींग प्रेस काढून चार नियतकालिके म्हणजे वृत्तपत्रे काढली. निराश्रित हिंदू नागरिक (१९१०), विटाळ विद्धसंक (१९१३), मजूर पत्रिका (१९१८), चोखामेळ (१९३१). त्यांचा प्रदीप हा कवितासंग्रह त्यांच्या नावावर आहे. त्यांची चोखामेळ आणि सत्यशोधक जलसा ही दोन नाटके प्रसिद्ध आहेत.^१ त्या काळात आपल्या प्रेसमध्ये छापून प्रसिद्ध करणारा दलितांमधील पहिला नाटककार होय. सनातनी हिंदूंना हे सहन झाले नाही म्हणून त्यांनी किसन फागू बनसोडे यांची प्रेस जाळली.

आंबेडकरी प्रेरणेचे नाटककार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांची प्रेरणा घेऊन विदर्भातील अनेक नाटककार साठोत्तरी मराठी साहित्यात दाखल झाले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रेरणेने प्राचार्य म. भी. धिटणीस यांनी युगयात्रा हे नाटक लिहिले.^२ व ते १४ ऑक्टोबर १९५६ च्या बौद्ध धम्म दीक्षा समारंभात लाखो लोकांच्या साक्षीने सादर झाले. १९५० ते १९५५ च्या दरम्यान नागपूरला दलित नाटकांची सुरुवात झाले. दलित रंगभूमीचा उदय तमाशा, दंडार, वग इत्यादी लोकनाटकातून झाला. दलितांचे संसार, समूहाचा आत्मेश, दलितांचा संवर्णांच्या विरुद्धचा क्रोध दलित नाटकातून अवतरू लागला. शिक्षणामुळे व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रेरणेने नाटक लिहू लागले. १९८२ साली सुप्रसिद्ध सिनेकलावंत निळू फुले ह्यांच्या साक्षीने पहिला दलित नाटक महोत्सव संपन्न झाला. दलित नाटकाविषयी डॉ. यशवंत मनोहर म्हणतात, दलित रंगभूमीने मराठी रंगभूमीवरील विद्रोहाची ही वाटचाल समाजक्रांतीच्या मैदानावर आणून उभी केली आहे. दलित रंगभूमीची

ISSN 2277 - 5730
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY
QUARTERLY RESEARCH JOURNAL

AJANTA

Volume - IX

Issue - II

APRIL - JUNE - 2020

HINDI PART - I

Peer Reviewed Referred
and UGC Listed Journal

Journal No. 40776



ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

IMPACT FACTOR / INDEXING

2019 - 6.399

www.sjifactor.com

❖ EDITOR ❖

Asst. Prof. Vinay Shankarrao Hatole

M.Sc (Maths), M.B.A. (Mktg.), M.B.A. (H.R.),
M Drama (Acting), M.Drama (Prod. & Dir.), M.Ed.

❖ PUBLISHED BY ❖



Ajanta Prakashan

Aurangabad. (M.S.)

हिंदी साहित्य और हाशिए का समाज (दलित नारी : एक दोहरा अभिशाप)

डॉ. सुनिता पं. वनसोड (भगत)

हिन्दी विभाग प्रमुख,
सरदार पटेल महाविद्यालय, चंद्रपुर

हिंदी दलित साहित्य चाहे ब उपन्यास, कहानियाँ, नाटक, निबंध, या काव्य ही क्यों न हो सभी में दलित जीवन का चित्र ब्यर्थ रूप में उभरकर सामने आया है। दलित साहित्यकारों ने अपनी लेखनी से इसे जीवित भी किया है। दलित साहित्य दलितों का विद्रोह एवं चेतना का विश्लेषण, उसकी पृष्ठभूमि व्याख्यायित करता हुआ क्रांति को जन्म देता है। स्वातंत्र्योत्तर काल में लोगों की जाति विषयक घोर छुवा-छुत की मानसिकता का बीज समूल नष्ट करने के लिए आंबेडकर बाद जो दलित साहित्य में दिखाई देता है उसका सहारा लिया गया है।

१९८० के बाद की दलित आत्मकथाओं के माध्यम से समकालीन संघर्ष, सत्ता द्वारा प्रतिपादित सांस्कृतिक मूल्यों पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। इन मूल्यों को पुनः परिभाषित करते हुए स्त्री मुक्ति का संबंध स्त्रियों की परंपरागत सोच की मुक्ति के साथ जोड़कर स्त्री की नई छवि का निर्माण करना चाहता है। "दोहरा अभिशाप" आत्मकथा दर्द से निकली स्त्री जीवन को झोड़कर रख देती है।

दलित साहित्य नारी में इन मूल्यों को खींचने का काम करता है जो पुराने सड़े-गले विचारों, अंधविश्वासों, रुढ़ी-परंपराओं, जाति की कट्टरता आदि संस्कारों से मुक्ति पाने की बात कहता है। सबसे पहले दलित स्त्री यह सोचें की वह एक नारी है इस बात है और जब हम उसे सजीव मानेंगे तभी हम नारी के साथ मानवता का बर्ताव कर सकेंगे। यह तभी संभव है जब स्वयं नारी अपने सामर्थ्य को समझे, अपनी योग्यता के बलबुते पर अपने स्वाभिमान की रक्षा करें। दलित साहित्य नारी जीवन की छवि को बदलकर नयी ध्येयवादी, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर पढ़ी-लिखी, आत्मविश्वास से परिपूर्ण नारी जो हिंदू कोड बिल का सहारा लेकर इन गुणों से परिपूर्ण होना चाहती है।

भारतीय दलित नारी दोहरे अभिशाप का लेकर चलती है। एक उसका स्वयं नारी होना। तथा दूसरा उसका दलित नारी होना। माना जाता है कि स्त्री सांसारिक जीवन रूपी रथ के दो पहिए हैं उसमें से नारी रूपी पहिया अगर पिछड़ता है या वह अग्राधार से ग्रसित है तो भला वह कैसे एकरूप हो सकेगी। ऐसा समाज, ऐसा राष्ट्र कभी प्रगति नहीं कर सकता है। दलित आत्मकथा में जो नारी दिखाई पड़ती है वह परंपरागत स्त्री नहीं है बल्कि समाजिक, धार्मिक, आर्थिक रूप की चेतना से परिपूर्ण उसकी छवि हमें दिखाई देती है।

हमारी प्राचीन भारतीय नारी समाज केवल एक कठपुतली की भांति था। जिसकी डोर समाज के पुरुषों के हाथ में थी। वह उसे जैसा चाहे वैसा नचा सकता था। पुरुषों की बताई व्यवस्था में ही उसे जीना होता। चौखट के भीतर का जीवन उसका जीवन कहलाता था। पर दलित साहित्य ने इस बात को नकारा दलित कहानियों में नारी एक योद्धा स्त्री है, जो परंपरागत हिंदू स्त्री की भांति अपने जीवन को नष्ट नहीं करती बल्कि समाजिक परंपराओं के प्रति विद्रोह कर स्वावलंबी बन समाज के सम्मुख एक नया आदर्श उपस्थित करती है।

यह दलित नारी परिवर्तन के साथ चाहे यह परिवर्तन विचारों में, रहन सहन में हो या सामाजिक, पारिवारिक ही क्यों न हों हमें उनमें दिखाई पड़ता है और महसूस होता है कि स्वतंत्रता के पहले का दलित

नारीयों का जीवन और स्वतंत्रता के बाद विशेषतः पर हिन्दू कोड बिल आने के बाद का जीवन इनमें हमें जमीन आसमान का अंतर स्पष्ट होता है। यह दलित स्त्री केवल अन्याय न सहने वाली, विवेक व तर्क की क्षमता रखनेवाली, घर-परिवार का निर्णय लेने में समर्थ, आत्मनिर्भर, संयमी, अधिकारों के प्रति सजग दिखाई देती है।

प्रस्तावना

भारतीय साहित्य में स्त्रियों द्वारा लिखित आत्मवृत्त का घोर अभाव है। यद्यपि सीमॉन जैसी कुछ रचनाएँ मिल जाती हैं। किंतु ऐसी गुमनाम लेखिकाओं का पता लगा पाना कठिन काम है। सावित्रीबाई फुले के स्त्री-स्कूल से शिक्षित होकर उनके साथ काम करनेवाली दलित महिलाओं में फातिमा शेख, मुक्ताबाई माळी नाम लिया जाता है किंतु उनकी भी रचनाएँ उपलब्ध नहीं होती।

आज की मध्यम वर्गीय दलित स्त्रियों के तेवर दूसरे हैं। आधुनिक दलित स्त्रियों ने पुरुष वादी मानसिकता के विरुद्ध स्त्री सवाल को भी उठाया है। जो दलित पुरुषों के विरुद्ध भी जाता है। इस दिशा में कुछ मराठी स्त्रियों ने प्रशंसनीय प्रयास किया है। जैसे तो मनु भंडारी, मैत्रिय पुष्पा, और रमणीका गुमा का नाम लिया जा सकता है। जिनकी आत्मकथाएँ आई हैं। किंतु दलित आलोचक उन्हें दलित नहीं मानते इसलिए बात दलित स्त्री साहित्यकारों से ही जोड़नी पड़ेगी इस क्षेत्र में सर्व प्रथम एक ही दलित स्त्री कौशल्या बसंत्री की आत्मकथा 'दोहरा अभिशाप' का नाम लिया जा रहा है। सुशिला टाकभोर की आत्मकथा भी वर्तमान समय में चर्चा में है। परंतु दोहरा अभिशाप किसी दलित स्त्री की पहली आत्मकथा है जो हिन्दी में आई है।

'दोहरा अभिशाप' जैसा की नाम से ही स्पष्ट है कि दोहरी पिड़ा की कथा। 'दोहरा अभिशाप' किसका? जाहिर है कि, एक कामकाजी स्त्री का दायित्व बोध पुरुष से अधिक हो जाता है। एक घर का दूसरा बाहर का उसी के अनुपात में उसका दुःख और संघर्ष भी बढ़ जाता है। किंतु स्त्री जब दलित हो तो उसका संघर्ष पुरुष से कई गुणा अधिक हो जाता है। सामाजिक दृष्टि से उसे दो-दो मोर्चों पर लड़ना पड़ता है। एक पुरुषवादी वर्चस्व से, दूसरा जातिवादी व्यवस्था से। कौशल्या बसंत्री का यह दोहरा अभिशाप किसी एक दलित स्त्री का अभिशाप नहीं है। बल्कि पूरी दलित स्त्री का अभिशाप है। भारतीय संदर्भ में स्त्रियों पुरुषों द्वारा सताई जाती है। उनका शोषण पुरुष वादी मानसिकता का परिणाम है। किंतु दलित स्त्रियाँ इस मानसिकता से अपने पुरुषों द्वारा तो शोषित होती ही हैं उन्हें संपूर्ण समाज द्वारा

दलित होने का दंड भी झेलना पड़ता है।

'दोहरा अभिशाप' शोषण की इसी दोहरी चक्की में पिसती एक दलित स्त्री की नियती-प्रकृति की कथा है। जिसे कौशल्या वसंत्री ने अपने जीवन यथार्थ के बहाने प्रस्तुत किया है। यह कुछ आप विती है तो कुछ जग बीती भी है। इस एक स्त्री के दलित बोध की पिड़ा स्त्री होने की पिड़ा के साथ मिलकर और बड़ी हो जाती है। स्त्रीयों के मामले में सर्वर्ण पुरुषों की सोच और दलित पुरुषों की सोच में अंतर नहीं है। नायिका का जीवन इस बात का प्रमाण है कि उनके व्यक्तित्व निर्माण में सर्वाधिक बाधाएँ उनकी बिरादरी के पुरुषों ने ही खड़ी की। उन्होंने बेबाक शब्दों में कह दिया की बाबासाहब के निकट सहयोगीय ने भी उसके साथ जबरन बौनाचार करना चाहा। उनकी बस्ती के लोगों ने ही उनका जिना मुश्कील कर दिशा। इसलिए कथा नायिका के लिए न तो दलित पुरुष अपने हैं न सर्वर्ण पुरुष। उसे भरोसा है तो केवल अपने आप पर। वह अपना सहाय स्वयं बनाना चाहती है। इसलिए वह कहती है 'आज के अनुभव से हमने सीख लिया है कि हम स्वाभिमानी से अपनी उन्नति करना चाहते हैं। अब हमें अपने पाव पर खड़ा होकर अपने पर भरोसा रखकर आगे बढ़ना होगा।' इस आत्मकथा में दलित जीवन की संपूर्ण दलित अशिक्षा और अज्ञानता, अपविश्वास, शोषण और तिरस्कार का विस्तार से वर्णन है।

कथा के आरंभ में ही लेखिका कहती है "मैं लेखिका नहीं हूँ न साहित्यकार लेकिन अस्पृश्य समाज में पैदा होने से जातियता के नाम पर जो मानसिक यातनाएँ सहन करनी पड़ी इसका मेरे संवेदनशील मन पर असर पड़ा।" दोहरा अभिशाप की कथा प्लेश बँक से शुरू होती है। स्मृतियों में अपने माता-पिता के संघर्ष और दुख भरे जीवन से लेखिका कहानी कहती है। लेखिका की 'आजी' अपने पति से बिना किसी वजह के होते हुए भी मार खाती थी। माँ भी दिन भर जी तोड़ मेहनत करती थी। किंतु समाज के लोगों द्वारा वह समुचित सम्मान नहीं पाती। इस प्रकार दोहरा अभिशाप केवल लेखिका के संदर्भ में भी घटित नहीं होता बल्कि उसकी नानी, दादी और माँ के संदर्भ में भी यही परंपरा चली आ रही होती है। लेखिका ने आजी के संघर्ष को बताते हुये उसके साहस की दाद दी है। पति के असहयोग के बावजूद वह अपने बच्चे-बच्चियों का पालन-पोषण करती है।

उसी प्रकार माँ का भी जीवन संघर्ष है दिन भर दूसरों के यहाँ काम करके परिवार की परवरिश करना माँ कि दिनचर्या है। दुःख सहकर भी माता-पिता बच्चे को पालते हैं।

इस प्रकार दोहरा अभिशाप के नारी पात्र जीवन कि चक्की के दोहरे पाठों के बीच पीस रही है। एक ओर वे अपने परिवार और समाज से लड़ना पड़ता है। तो दूसरी ओर अपनी अस्मीता, मान-सम्मान और जीवन की अन्य आवश्यकताओं के लिए सर्वर्ण समाज से लोहा लेना पड़ता है। लेखिका ने इस आत्मकथा में दलित जीवन के विभिन्न अनुभव को परत दर परत खोलते हुए स्त्री जीवन की विडंबनाओं और संवेदनाओं को चित्रित किया है।

लेखिका एक घटना का वर्णन करती है जिसमें एक सुंदर दलित औरत दिहाड़ी पर मजदूरी का काम करती है वह मिस्री को सिमेंट ढो-ढोकर पहुंचाती है मिस्री एक दिन उसके स्तन के भाग पर मजाक में गिले सिमेंट का गोला फेंक देता है। इस पर सभी मजदूर हँस पड़ते हैं, वह अपमानित होकर इसकी शिकायत अपने पति से करती है। किंतु दलित पति परमेश्वर उलटा उसी पर कुलटा होने का आरोप लगाकर उसे घर से निकाल देता है और उसे गधे पर बिठाकर घुमाया जाता है वह शर्म के मारे झाड़ियों में छिपी रहती है बसुकी उसके पास तन ढकने के लिए कपड़े नहीं होते हैं। दूसरे दिन उसकी लाश कुएँ में मिलती है वह आत्महत्या कर लेती है। पति तो पति उसके माँ-बाप भी आकर उसी पर आरोप लगाते हैं। अच्छा हुआ कुलटा थी मर गई। बाद में उसके दो बच्चों के साथ उसका पति दूसरी शादी रचा लेता है दोहरा अभिशाप। कथा में एक दलित स्त्री के तार-तार होते जीवन को बखुबी चित्रित किया गया है। उसका दोहरा शोषण होता है।

संदर्भ सूची :

1. दोहरा अभिशाप - कौशल्या वसंत्री
2. दूसरी दुनिया का यथार्थ - संपा. रमणिका गुप्ता
3. दलित आत्मकथाएँ अनुभव एवं चिंतन - सुभाष चंद्र/ शरणकुमार लिवाले
4. भारतीय दलित साहित्य : परिप्रेक्ष्य - संपा. पुनीतिह, कमला प्रसाद, राजेंद्र शर्मा
5. दलित आत्मकथाएँ - सुभाष चंद्र
6. दलित साहित्य में प्रमुख विधाएँ - संपा. माता प्रसाद



OUR HERITAGE (UGC Care Journal)

ISSN: 0474-9030 Vol-68, Special Issue-14

National Seminar on "The Importance of Sports, Physical Education and Psychology for Personality development At Present Scenario"

Sponsored by ICSSR

Held on (01 February 2020, Saturday)

Organized by: Department of Psychology, Sports and Physical Education
Shivaji College, Hingoli-431513 (Maharashtra)



Study of Psychological Hardiness among players of various games

Prof. Kuldeep R. Gond

Director of Physical Education

Sardar Patel Mahavidyalaya, Chandrapur

email: kuldeep.spm83@gmail.com

Prof. Santosh Kumar Sharma

Assistant Professor, Department of Physical Education

Chintamani College of Science

Pombhurna, Chandrapur

email: santosh@chintamani.edu.in

Abstract

The purpose of the study was to compare the psychological hardiness among players of various games. For this purposes researcher has selected 40 players (20 kabaddi players and 20 kho-kho players) who has participated in inter-collegiate tournaments as well as in state tournaments from Sardar Patel Mahavidyalaya and Chintamani College of Science, Chandrapur, Maharashtra. Players were selected by purposive sampling method. There age limit of the subjects were 20 to 25 years. Psychological hardiness was measured with the help of questionnaire constructed by Prof. Arun Kumar Singh. To compare the psychological hardiness among players of kabaddi and kho-kho game t-test was applied as statistically and the level of significance was kept at 0.05 levels. Result shows that on the basis of mean different there was difference between mean of kabaddi players and kho-kho players. To see this difference is significant or not at 0.05 level of significance. Researcher further calculated 't' test & result shows that there is significant difference between kabaddi players and kho-kho players in reference to Commitment disposition as the calculated t-value 2.301 is greater than the tabulated t-value 2.024. Whereas the two disposition Control and Challenge shows insignificant as the calculated t-value 1.521 & 0.236 is lesser than the tabulated t-value 2.024. In conclusion it revealed that mean of kabaddi and kho-kho players shows difference in reference to psychological hardiness components i.e. Commitment, Control and Challenge. To see this difference is significant or not researcher further calculated 't' test & result shows that there is significant difference between kabaddi players and kho-kho players in reference to Commitment disposition whereas the two disposition Control and Challenge



OUR HERITAGE (UGC Care Journal)

ISSN: 0474-9030 Vol-68, Special Issue-14

National Seminar on "The Importance of Sports, Physical Education and Psychology for Personality development At Present Scenario"

Sponsored by ICSSR

Held on (01 February 2020, Saturday)

Organized by: Department of Psychology, Sports and Physical Education
Shivaji College, Hingoli-431513 (Maharashtra)



found to be insignificant. It may be attributed that every players is unique to each as individual, allowing them to engage themselves in different situation while playing. Kabaddi players shows better level of commitment as it, not solely in terms of individual, also refers to the sense of community and individual place in that arena and able to cope with stressful situations because of the understanding regarding the individuals place within the group cohesion. Both the players shows insignificant in reference to level of control and challenge, it may be attributed that both game players have the same level of responsibility and level of difficulties.

Introduction

Psychological hardiness was usually characterized as a personality structure comprising the three related general miens of commitment, control and challenges that experience as a resistance resource in encounters with stressful conditions at the time of early era. The commitment disposition was characterized as a tendency to involve oneself in activities in life and as having a genuine interest in and curiosity about the surrounding i.e. (activities, things, and other people). The control disposition was characterized as a tendency to believe and act as if one can influence the events taking place around oneself through one's own efforts. Lastly, the challenge disposition was characterized as the belief that changes, rather than stability, is the normal mode of life and constitutes motivating opportunities for self-awareness rather than threats to security.

Psychological hardiness can be expressed as a tendency that enables a characteristic to accept the experiences and variations in life with good humor and flexibility, which in turn influences behavior that prevents illness. The way to psychological hardiness is not luck as well as is not genetic, but is a learned approach to stress. The learning includes understanding or observing stressful events in a versatile manner. Psychological hardiness is a multi-component structure that is possessed by all individual to varying degrees and includes three components: commitment, control, and challenge. Researchers have understood the meaning, value, importance, and purpose of themselves, their job, their family, and their life in general. They give more confidence to effort and action than chance and believe they can manipulate life occasions and activities. They possess an internal asset and consider the positive and negative events life as the consequence of their actions.

Psychological hardiness can be expressed as a mental skill that can play a significant role in the performance of players. The effects of psychological hardiness and its various components on competitive anxiety and self-confidence of players were mostly seen. Psychological hardiness protects the individual against the unremitting effects of stress, especially in highly stressful situations. Hardiness is a better predictor of mental health than



OUR HERITAGE (UGC Care Journal)

ISSN: 0474-9030 Vol-68, Special Issue-14

National Seminar on "The Importance of Sports, Physical Education and Psychology for Personality development At Present Scenario"

Sponsored by ICSSR

Held on (01 February 2020, Saturday)

Organized by: Department of Psychology, Sports and Physical Education
Shivaji College, Hingoli-431513 (Maharashtra)



physical health. Hence the researcher has taken the study Psychological Hardiness among players of various games.

Methodology

The purpose of the study was to compare the psychological hardiness among players of various games. For this purposes researcher has selected 40 players (20 kabaddi players and 20 kho-kho players) who has participated in inter-collegiate tournaments as well as in state tournaments from Sardar Patel Mahavidyalaya and Chintamani College of Science, Chandrapur, Maharashtra. Players were selected by purposive sampling method. There age limit of the subjects were 20 to 25 years.

Psychological hardiness was measured with the help of questionnaire constructed by Prof. Arun Kumar Singh. The psychological hardiness questionnaire was consisting of three separate components – commitment, control and challenge. The test consist of 30 questions, the total questionnaire had three factors- Commitment, Control and Challenge. Each question in this test has five possible answers. Players have to tick mark against appropriate answer to each question. All the point value against the answered totaled. There were 30 items. Maximum point score for each question was 5; so for each factor which consists of 10 questions, 50 marks were maximum possible score.

Statistical Analysis

To compare the psychological hardiness among players of kabaddi and kho-kho game t-test was applied as statistically and the level of significance was kept at 0.05 levels.

TABLE

Comparison of Psychological Hardiness Components among Kabaddi and Kho-Kho Players

Psychological Hardiness	Players	Mean	S.D.	M.D	S.E	D.F	O.T.	T.T.
Commitment	Kabaddi Players	38.14	5.73	3.87	1.68	38	2.301*	2.024
	Kho-Kho Players	34.27	4.87					
Control	Kabaddi Players	37.45	4.89	2.24	1.47		1.521	
	Kho-Kho Players	35.21	4.41					
Challenge	Kabaddi Players	36.43	4.53	0.33	1.39		0.236	
	Kho-Kho Players	36.76	4.28					

*significant at 0.05 level



OUR HERITAGE (UGC Care Journal)

ISSN: 0474-9030 Vol-68, Special Issue-14

National Seminar on "The Importance of Sports, Physical Education and Psychology for Personality development At Present Scenario"

Sponsored by ICSSR

Held on (01 February 2020, Saturday)

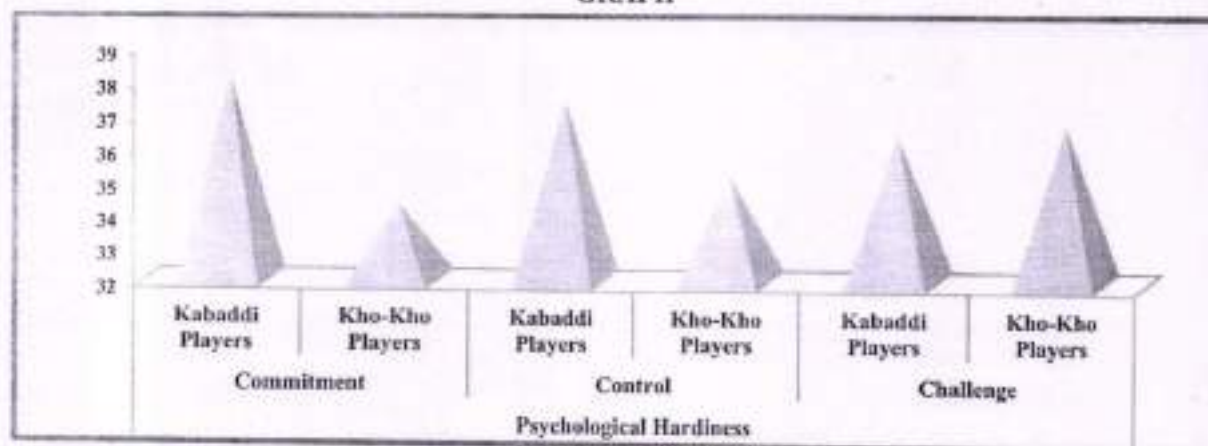
Organized by: Department of Psychology, Sports and Physical Education

Shivaji College, Hingoli-431513 (Maharashtra)



Above table shows that on the basis of mean different there was difference between mean of kabaddi players and kho-kho players. To see this difference is significant or not at 0.05 level of significance. Researcher further calculated 't' test & result shows that there is significant difference between kabaddi players and kho-kho players in reference to Commitment disposition as the calculated t-value 2.301 is greater than the tabulated t-value 2.024. Whereas the two disposition Control and Challenge shows insignificant as the calculated t-value 1.521 & 0.236 is lesser than the tabulated t-value 2.024.

GRAPH



Comparison of Psychological Hardiness Components among Kabaddi and Kho-Kho Players

Conclusion

In conclusion it revealed that mean of kabaddi and kho-kho players shows difference in reference to psychological hardiness components i.e. Commitment, Control and Challenge. To see this difference is significant or not researcher further calculated 't' test & result shows that there is significant difference between kabaddi players and kho-kho players in reference to Commitment disposition whereas the two disposition Control and Challenge found to be insignificant. It may be attributed that every players is unique to each as individual, allowing them to engage themselves in different situation while playing. Kabaddi players shows better level of commitment as it, not solely in terms of individual, also refers to the sense of community and individual place in that arena and able to cope with stressful situations because of the understanding regarding the individuals place within the group cohesion. Both the players shows insignificant in reference to level of control and challenge, it may be attributed that both game players have the same level of responsibility and level of difficulties.



OUR HERITAGE (UGC Care Journal)

ISSN: 0474-9030 Vol-68, Special Issue-14

National Seminar on "The Importance of Sports, Physical Education and Psychology for Personality development At Present Scenario"

Sponsored by ICSSR

Held on (01 February 2020, Saturday)

Organized by: Department of Psychology, Sports and Physical Education
Shivaji College, Hingoli-431513 (Maharashtra)



Reference

- Allport, G.W. (1927). Personality and psychological interpretation. New York: Henry Holt & CO. pp 132-140.
- Bhatia, H. R. (1977). Educational Psychology, New Delhi; Surjeet Publications p. 389.
- Cattell, R. B. (1970). Theories of personality 2nd edition. John Wiley and Sons. P. 386.
- Hull, J. G., Van Treuren, R. R., & Prossom, P. M. (1988). Attributional style and the components of hardiness. Personality and Social Psychology bulletin, 14(3), 505-513.
- Kobasa, S. C., Maddi, S. R., and Kahn, S. (1982). Hardiness and health: A prospective study. Journal of Personality and Social Psychology, 42(1), 168-177.
- Mathis, M, and Lecci, L. (1999). Hardiness and college adjustment: Identifying students in need of services. Research in Brief, 40(3), 305-309.

INTERNATIONAL RESEARCH FELLOWS ASSOCIATION'S

RESEARCH JOURNEYMultidisciplinary International E-Research Journal

PEER REFREED & INDEXED JOURNAL

September-2019 Special Issue - 197 (A)

**Emerging Innovative Trends in Higher Education
An Interdisciplinary Approach**

Guest Editor :

Dr. M. N. Gaikwad

Principal

Gopikabai Sitaram Gawande Mahavidyalaya, Umarkhed

Dist. Yavatmal (M.S) India

Executive Editor -

Dr. K. B. Shirse

Head, Dept. of History,

Gopikabai Sitaram Gawande Mahavidyalaya, Umarkhed

Dist. Yavatmal (M.S) India

Associate Editors -

Prof. A. S. Joshi

Dr. V. R. Jiwatode

Dr. U. N. Patil

Dr. V. S. Ingle

Dr. K. D. Bompliar

Prof. S. S. Pachkudke

Chief Editor -

Dr. Dhanraj T. Dhangar (Yeola)



This Journal is indexed in :

- Scientific Journal Impact Factor (SJIF)
- Cosmoc Impact Factor (CIF)
- Global Impact Factor (GIF)
- International Impact Factor Services (IIFS)



29	Role of Higher Education in Social Unity and Nation Building	Prof. Ashvinkumar Kshirsagar	115
30	An Economic Analysis of MGNREGA	Dr. Pooja D. Rangwani	119
31	Educational Strategy and Required Social Development	Dr. Nilima Dawane	123
32	Tagore's Concern for Human Values as Reflected in the Novel <i>Farewell my Friend</i>	Dr. Mahendra S. Chhangani	127
33	Farmers' Suicides in India: A Qualitative Exploration of Their Cause's Special Reference with Marathwada Region of Maharashtra, India	Keshav Ubale	131
34	Denial of Human Rights in Mahasweta Devi's <i>Aajir</i>	Dr. Anita Warwatkar	136
35	Agricultural Sector : it's Role in Indian Economy	Rupeshkumar Raut & Dr. Sharyu Potnurwar	140 ✓
36	Emerging Innovative Trends in Pharmacy Education	Desale Praneta, Rakesh Salunkhe	1496
37	Importance and to Sector-wise Contribution of GDP	Sushen N. Maind	149
38	Role of Literature in Disseminating Human Values	S. S. Deshmukh	153
39	Importance of English Language	Dr. B. W. Somatkar	156
40	Role of English Literature in Disseminating Human Values	Nitesh Telhande	159
41	A Study of Environment Awareness in Higher Education	Jayshree P. Morey	163
42	Indian Agriculture - Status, Importance and Role in Indian Economy	Ku. Vrukshali Mamedwar	168
43	Higher Education & Library Science	Indrasing P. Pawar	172
44	Role of Education in Good Governance	Dr. Jyoti Mishra & Prof. Manisha Shedge	176
45	E-Learning and M-Learning : Now Education is for All	Dr. Sarla Nimbhorkar	180
46	Emerging Trends in English Language and Literature	Prof. Rupesh Wankhade	185
47	Recent Issues in Development of Agriculture Sector in India	Dr. Jivan Biradar & Prof. Ashish Kathale	188
48	Farmers Suicides in India Causes and Remedies	Dr. Vasant Pawale	194
49	Use of Innovative Technology in Teaching Learning Process	Digambar D. Wankhede	196
50	Farmer Suicide in India Reasons and Responses	Dr. M. R. Shinde	198
51	Important Function of Role and Reference Grammar in the Language	Ganesh Khanderao	201
52	Agrarian Distress And Farmers Suicides in Vidharba: Reasons and Responses	Prof. Dr. Siddharth Gangale	205
53	Higher Education for Improving Environmental Health and Mankind	Dr. Bhaskar Sawarkar	209
54	Breaking Down the Indian GDP : A Case Study to Analyse the Effects of External Events on GDP.	Sunay N. Pistulkar & Prof. N. A. Pistulkar	213
55	Agriculture Role in Indian Economy	Prof. Shishakant Bichkunde	220
56	Agricultural Role on India Economy	Dr. P.N.Ladhe	222
57	Farmers Suicide in India: Reasons and Responses	Dr.P.B.Karche	227
58	Importance of Education in Society, Governance & Democracy	Dr. V. S. Ingle & Prof. J. P. Jukare	231
59	Study of Reasons and Government Responses to the Farmers' Suicide in India: with Special Reference Maharashtra State	Dr. S. B. Adkine & Mr. Atmaram Jadhav	234
60	English Literature 20 th and 21 st Century Emerging Trends	Savita Jogdande	238



Agricultural Sector : It's Role in Indian Economy

Rupeshkumar Raut

Assistant District Planning Officer,
District Planning Committee, Chandrapur, Maharashtra, India

Dr. Sharyu Potnurwar

Assistant Professor and HoD (Economics),
Sardar Patel Mahavidyalaya, Chandrapur, Maharashtra, India

Abstract:

Although, contribution of Agriculture's Gross Value Added (GVA) to overall GVA has been declining (14.4 per cent in 2018-19) it is still a crucial sector, as a large proportion of the population (approximately 50%) engage in agriculture. The department of Agriculture and cooperation under the Ministry of Agriculture is the nodal organization responsible for the development of the agriculture sector in India. In 2016, agriculture and allied sectors like animal husbandry, forestry and fisheries accounted for 15.4% of the GDP (gross domestic product) with about 31% of the workforce in 2014. India ranks 74 out of 113 major countries in terms of food security index. India's agricultural economy is undergoing structural changes. Between 1970 and 2011, the GDP share of agriculture has fallen from 43% to 16%. This isn't because of reduced importance of agriculture or a consequence of agricultural policy. This is largely because of the rapid economic growth in services, industrial output, and non-agricultural sectors in India between 2000 and 2010. To attain the Sustainable Development Goals (SDGs) of ending poverty and bringing in inclusive growth, activities related to agriculture need to be closely integrated with the SDG targets. The study highlights role of agriculture in Indian economy.

Keywords: Agricultural Sector, GVA, GDP, SDG

Introduction:

Agriculture and allied sectors are critical in terms of employment and livelihoods for the small and marginal farmers, who dominate the agriculture ecosystem in India. With decline in the size of landholdings in agriculture, India has to focus on resource efficiency in smallholder farming to meet the SDG targets and also to attain sustainability in agriculture.

India is the world's largest producer of milk, pulses and jute, and ranks as the second largest producer of rice, wheat, sugarcane, groundnut, vegetables, fruit and cotton. It is also one of the leading producers of spices, fish, poultry, livestock and plantation crops.

Agriculture, with its allied sectors, is the largest source of livelihoods in India. 70 percent of its rural households still depend primarily on agriculture for their livelihood, with 82 percent of farmers being small and marginal. In 2017-18, total food grain production was estimated at 275 million tonnes (MT). India is the largest producer (25% of global production), consumer (27% of world consumption) and importer (14%) of pulses in the world. India's annual milk production was 165 MT (2017-18), making India the largest producer of milk, jute and pulses, and with world's second-largest cattle population 190 million in 2012. It is the second-largest producer of rice, wheat, sugarcane, cotton and groundnuts, as well as the second-largest fruit and vegetable producer, accounting for 10.9% and 8.6% of the world fruit and vegetable production, respectively.

Objectives of the study:

1. To know current status of agricultural sector in India
2. To know various initiatives taken by government for the development of agricultural sector



in India

3. To study role of agricultural sector in Indian economy

Research Methodology:

The present study based on secondary data available in books, various reports, magazines etc.

Current status of agricultural sector in India:

Market Size:

During 2017-18 crop year, food grain production is estimated at record 284.83 million tonnes. In 2018-19, Government of India is targeted food grain production of 285.2 million tonnes. As of September 2018, total area sown with kharif crops in India reached 105.78 million hectares.

India is the second largest fruit producer in the world. Production of horticulture crops is estimated at record 314.7 million tonnes (mt) in 2018-19 as per third advance estimates. Total agricultural exports from India grew at a CAGR of 16.45 per cent over FY10-18 to reach US\$ 38.21 billion in FY18. In FY2019 agriculture exports were US\$ 38.54 billion. Spice exports from India reached US\$ 3.1 billion in 2017-18. Tea exports from India reached a 36 year high of 240.68 million kgs in CY 2017 while coffee exports reached record 395,000 tonnes in 2017-18. Food & Grocery retail market in India was worth US\$ 380 billion in 2017.

Gross Value Added in Agriculture:

The Gross Value Added (GVA) in agriculture improved from a negative 0.2 per cent in 2014-15 to 6.3 per cent in 2016-17 only to decelerate to 2.9 per cent in 2018-19. While the crops, livestock and forestry sector showed fluctuating growth rates over the period from 2014-15 to 2017-18, the fisheries sector has shown a rapid growth from 4.9 per cent in 2012-13 to 11.9 per cent in 2017-18. (Table 1 and Figure 1).

Table 1 : Growth of GVA in Agriculture & Allied Sectors at 2011-12 prices

Item	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16* (3RE)	2016-17 (2RE)#	2017-18 (IRE)@	2018-19 PE**
Total GVA at basic prices	5.4	6.1	7.2	8.0	7.9	6.9	6.6
Agriculture, forestry & fishing	1.5	5.6	-0.2	0.6	6.3	5.0	2.9
Crops	0.2	5.4	-3.7	-2.9	5.0	3.8	na
Livestock	5.2	5.6	7.4	7.5	9.9	7.0	na
Forestry & logging	0.2	5.9	1.9	1.7	1.4	2.1	na
Fishing & aquaculture	4.9	7.2	7.5	9.7	10.0	11.9	na

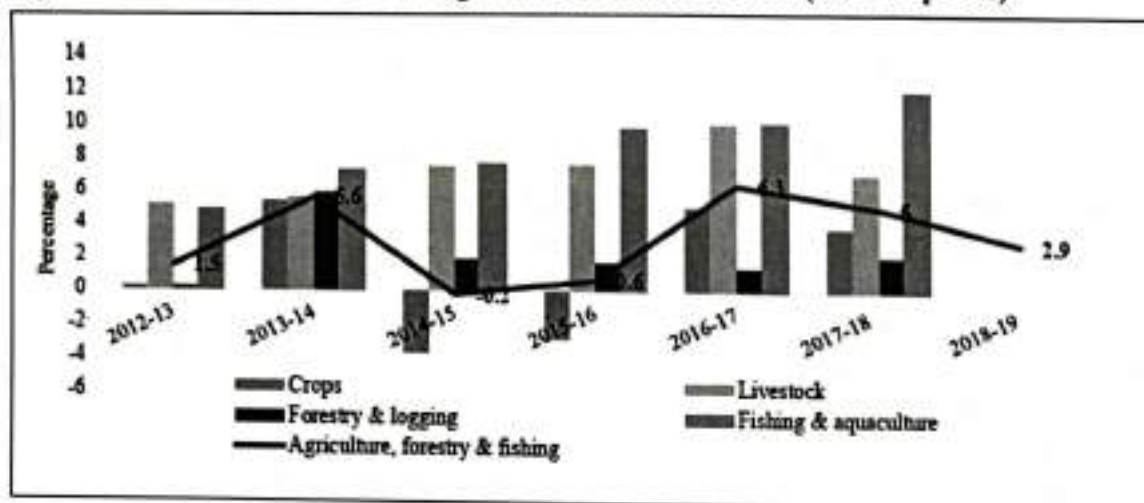
Source: Central Statistics Office, Ministry of Statistics & Programme Implementation (MoSPI)

Note-* Third Revised Estimate, # Second Revised Estimate, @ First Revised Estimate

**As per the press note on Provisional Estimates of Annual National Income 2018-19 and Quarterly Estimates of Gross Domestic Product for the Fourth Quarter (Q4) of 2018-19 released by CSO on 31st May 2019



Figure 1: Growth Rate of GVA in Agriculture & Allied Sectors (2011-12 prices)



Source: Central Statistics Office, Ministry of Statistics & Programme Implementation (MoSPI)

Share of Agriculture Sector in GVA

The share of agriculture, forestry & fishing sector in GVA has seen a steady decrease over the years from 15.4 per cent in 2015-16 to 14.4 per cent in 2018-19. The decline was mainly due to decline in the share of crops in GVA from 9.2 per cent in 2015-16 to 8.7 per cent in 2017-18. The share of the fisheries in GVA has increased by 0.1 per cent points during the three years from 0.8 per cent in 2014-15 to 0.9 per cent in 2017-18. The share of the livestock in GVA has remained around 4 per cent from 2012-13 to 2017-18. The share of forestry & logging was 1.2 per cent in 2017-18. (Table 2)

Table 2: Share of Agriculture, Forestry & Fishing at 2011-12 Prices (in per cent)

Item	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16*	2016-17	2017-18 @	2018-19 **
Agriculture, forestry & fishing	17.8	17.8	16.5	15.4	15.2	14.9	14.4
Crops	11.5	11.4	10.3	9.2	9.0	8.7	NA
Livestock	4.0	4.0	4.0	4.0	4.1	4.1	NA
Forestry & logging	1.5	1.5	1.4	1.3	1.2	1.2	NA
Fishing & aquaculture	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	na

Source: Central Statistics Office, Ministry of Statistics & Programme Implementation (MoSPI).

Note-* Third Revised Estimate, # Second Revised Estimate, @ First Revised Estimate

**As per the press note on Provisional Estimates of Annual National Income 2018-19 and Quarterly Estimates of Gross Domestic Product for the Fourth Quarter (Q4) of 2018-19 released by CSO on 31st May 2019

Investments:

Some major investments and developments in agriculture are as follows:

- Investments worth Rs 8,500 crore (US\$ 1.19 billion) have been announced in India for ethanol production.
- By early 2019, India started exporting sugar to China.
- The first mega food park in Rajasthan was inaugurated in March 2018.



- Agrifood start-ups in India received funding of US\$ 1.66 billion between 2013-17 in 558 deals.
- In 2017, agriculture sector in India witnessed 18 M&A deals worth US\$ 251 million.

Government Initiatives:

Some of the recent major government initiatives in the sector are as follows:

- Prime Minister of India, launched the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana (PM-Kisan) and transferred Rs 2,021 crore (US\$ 284.48 million) to the bank accounts of more than 10 million beneficiaries on February 24, 2019.
- The Agriculture Export Policy, 2018 was approved by Government of India in December 2018. The new policy aims to increase India's agricultural exports to US\$ 60 billion by 2022 and US\$ 100 billion in the next few years with a stable trade policy regime.
- In September 2018, the Government of India announced Rs 15,053 crore (US\$ 2.25 billion) procurement policy named 'Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshana Abhiyan' (PM-AASHA), under which states can decide the compensation scheme and can also partner with private agencies to ensure fair prices for farmers in the country.
- In September 2018, the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) approved a Rs 5,500 crore (US\$ 820.41 million) assistance package for the sugar industry in India.
- The Government of India is going to provide Rs 2,000 crore (US\$ 306.29 million) for computerisation of Primary Agricultural Credit Society (PACS) to ensure cooperatives are benefitted through digital technology.
- With an aim to boost innovation and entrepreneurship in agriculture, the Government of India is introducing a new AGRI-UDAAN programme to mentor start-ups and to enable them to connect with potential investors.
- The Government of India has launched the Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (PMKSY) with an investment of Rs 50,000 crore (US\$ 7.7 billion) aimed at development of irrigation sources for providing a permanent solution from drought.
- The Government of India plans to triple the capacity of food processing sector in India from the current 10 per cent of agriculture produce and has also committed Rs 6,000 crore (US\$ 936.38 billion) as investments for mega food parks in the country, as a part of the Scheme for Agro-Marine Processing and Development of Agro-Processing Clusters (SAMPADA).
- The Government of India has allowed 100 per cent FDI in marketing of food products and in food product e-commerce under the automatic route.

Role of agricultural sector in Indian economy:

The following facts highlights the role of agricultural sector in Indian economy

1. Contribution to national Income:

The percentage share of agricultural sector in national income was 57.7 during 1950-51. This share has declined to 24.6 percent during early 2000s. The 2001 census data indicates that agriculture workers account for 58.4 percent of workforce of India. The Economic Survey 2017-18 had key implications for agriculture sector which employs more than 50 per cent of the total workforce in India and contributes around 17-18 percent to the country's GDP.

2. Source of Livelihood:

According to decennial census reports the percentage distribution of workers engaged in agriculture to total workers was 72 per cent in 1951. In 1961 this percentage was 69.5 in 1971 it was 69.7 per cent and in 1981 this percentage was 60.5 (excluding Assam). Women play a significant and



crucial role in agriculture including crop production, livestock production, horticulture, postharvest operations, agro/social forestry, fisheries, etc.

Employment in agriculture (% of total employment) in India was reported at 42.74 % in 2017, according to the World Bank collection of development indicators, compiled from officially recognized sources.

3. Source of Food and Fodder:

Implementation of the National Food Security Mission (NFSM) during the 11th Plan period helped in achieving record levels of foodgrain production. The livestock sector in India contributes to nearly 32% of total agricultural output. India with 2.3% share of global geographical area supports nearly 20% of the livestock population of the World, notably among them are cattle (16%), buffalo (55%), goat (20%) and sheep (5%).

With an estimated production of 146.3 million tonnes in 2014-15, India continues to be the largest producer of milk in the world. Per capita availability of milk has reached 322 grams per day during the year 2014-15, which is more than the world average of 294 grams per day. Similarly, in the case of meat, egg, wool and fish production, substantial progress has been achieved.

Having only 4% of total cropping area under fodder cultivation has resulted in a severe deficit of green fodder (36%), dry fodder (40%) and concentrates (57%). The need of the hour is, therefore, to fulfil this shortfall in demand for fodder (which is over 55%) from crop residues and agricultural bi-products. There is need for an Inclusive Fodder Development Programme.

4. Role of Agriculture in Industrial Development:

There is a close Interdependence between agriculture and industry. In 1964-65 out of total agricultural production, about 12.5 per cent went from agriculture to agriculture while nearly 23 per cent was utilised by the industries. The farm sector has to supply the raw material for growing industries. For instance, nearly one third of India's industrial output till recently depended upon the supply of agricultural commodities such as raw cotton, jute, oil seeds and rice. The manufacturing sector has to supply agricultural inputs and tools such as chemical fertilizers, pump sets, tractors, harvesting, sowing and threshing machines to farm sector. About 50 per cent of income generated in the manufacturing sector comes from all these agro-based industries in India.

On account of surplus labour in the agricultural sector in India, man-power for manufacture sector can be drawn easily from agriculture.

5. Role of Agriculture in International Trade:

Agriculture plays an important role in our international trade. . Nearly one-seventh of the country's total export earnings accrue from the agricultural sector. The main agricultural commodities which are exported are tea, oilcakes, fruits and vegetables, spices, tobacco, animal hair, and vegetable oils. There is a huge scope of international trade.

The share of agricultural exports, which constituted more than 30% of the total exports from the country during 1970-71 and 1980-81, have of late been declining consistently, more so in recent years. The declining trend is more noticeable in the post liberalization and post WTO periods. In 1990-91 agricultural exports constituted about 18 % of the total exports which in 2000-01 went down to 14 %. In 2003-04 agricultural exports constituted only 12.4 % of all exports . The share of agriculture sector in the country's total exports, during the last three years, is given below:

Year	2016-17	2017-18	2018-19
Share of agriculture sector in total exports	12.07%	12.66%	11.76%

Source: DGCIS



6. Role of Agricultural sector in Transport:

For distribution of agriculture produce, road transport has vital role because it is the major means of transporting agricultural produce from the farms to the markets as well as to various urban communities. It is the only means by which food produced at farm location is transported to different homes as well as markets. Transport creates market for agricultural produce, improves interaction among geographical and economic regions and opens up new areas to economic focus.

Conclusion:

Agriculture continues to be the backbone of Indian economy by providing livelihood for more than half of her total population. The primary sector of the economy also acts as a significant contributor to GDP and foreign exchange. Historical experiences of most of the developed countries like England, U.S.A., U.S.S.R., Canada, Japan etc., reveal the importance of agriculture in the process of the country's economic development at the outset of industrial revolution. For over-all growth of an economy, proper balance between agriculture and industry is essential as these two industries are interdependent.

The variations in agricultural growth lead to inter-regional and intraregional inequalities in income levels within the country. Therefore, to sustain higher agricultural growth, the productivity variations should be minimised and prepare all the states, regions and districts, as equal partners in the overall growth of a country.

Globalization of Indian agriculture offers both opportunities and challenges to policy makers. Opportunities exist for deriving large benefits through substantial increase in the agricultural exports, especially, high value labor-intensive agricultural products. The challenges lie in modernizing small scale agriculture and making it efficient and competitive

References:

1. Directorate of Economic and Statistics, Ministry of Agriculture
2. Economic Survey (2018-19), p 172-176
3. https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/61922/1/11_chapter%203.pdf, p 57
4. https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/64532/9/09_chapter%202.pdf, p 52-53
5. <https://www.ibef.org>
6. <http://www.fao.org/india/fao-in-india>
7. <http://agricoop.nic.in>
8. Rahul Wagh, Dr. Anil P. Dongre, 2016 "Agriculture Sector: Status, Challenges and its role in Indian Economy" Journal of Commerce and Management thought, Vol 7-2, 2016, pp 209-218
9. Himani, "An Analysis of Agriculture Sector in Indian Economy" IOSR Journal of Humanities And Social Science (IOSR – JHSS), Volume 19, Issue 1, Ver. X (Feb. 2014), PP 47-54



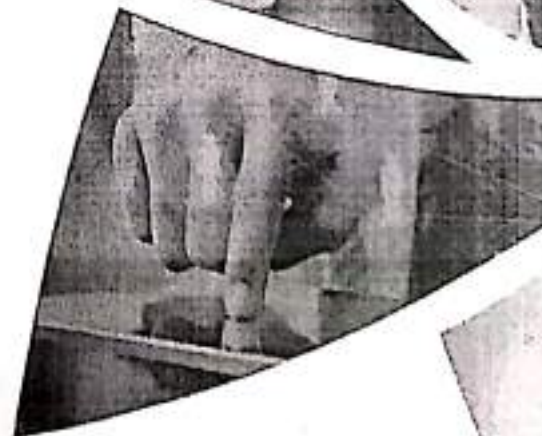
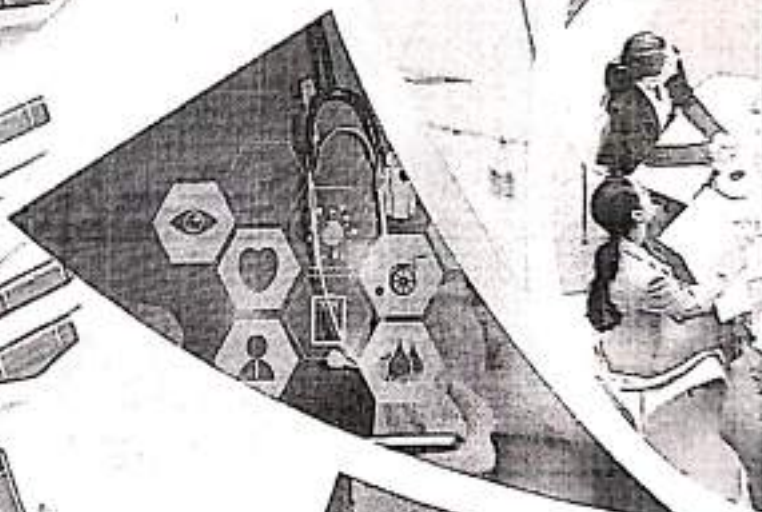
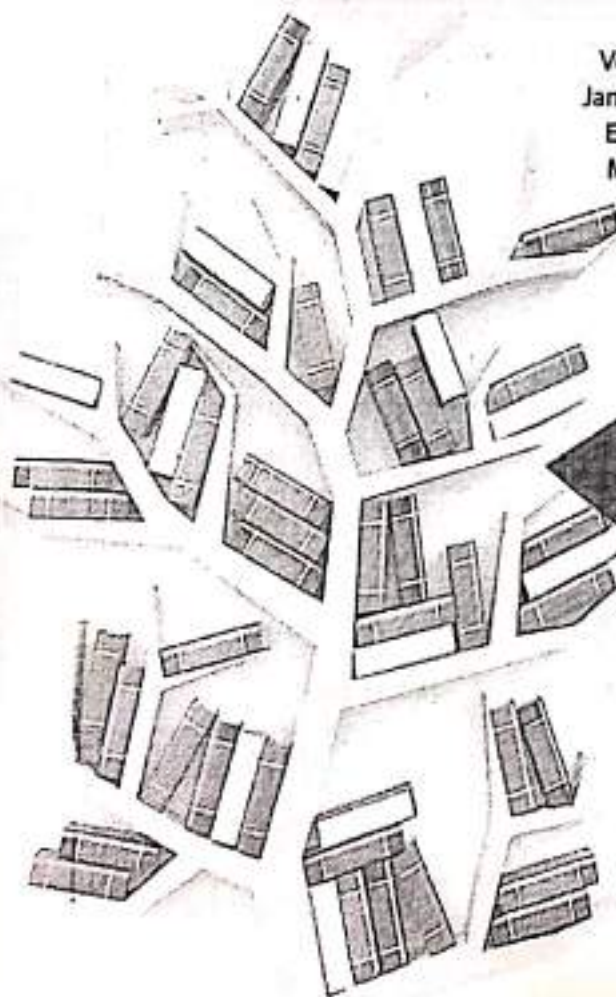
Peer Reviewed Referred and
UGC Listed Journal
(Journal No. 40776)



ISSN 2277 - 5730
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY
QUARTERLY RESEARCH JOURNAL

AJANTA

Volume-VIII, Issue-I
January - March - 2019
English Part - VIII /
Marathi Part - VI /
Hindi Part - III



Ajanta Prakashan

IMPACT FACTOR / INDEXING

2018 - 5.5

www.sjifactor.com

8. Indianness in the Novels of V.S. Naipaul

Mr. Ashish R. Bahale

Research Scholar, Shri Sai Polytechnic, Chandrapur.

Dr. A. V. Dhote

Research Supervisor, Head, Department of English, Sardar Patel Mahavidyalaya, Chhatrapati

Abstract

The term Indianness is related to a practices of a person whether they live in India or abroad. We belongs to our parents, family, town or city and our country. We belong to India, we feel quite at home in India. This feeling is inborn and natural. We have certain feeling of affection for our country and family. We share the common religions and cultural things. We love the members of our family, we care for them, we understand the code language of our family members, and we feel the restlessness if we go away from them. It happens not because we go away form them. It happens not because we are born in India but because we are aware of what has been happening in India for thousand of years and followed the ritual and customs reflected all in your behavior, language, religion, clothes, food and tradition. This is Indianness. An element of Indianness is always seen in the novels of V. S. Naipaul. It is a sense of belonging being deep rooted indianness. The some of his novels are structured around Indian notions as the four stages of an ordered life, student, marriage and house-owner.

Key words : Indianness, rooted, tradition, restlessness religion.

Introduction

The reflection of Indianness or Indian sense is always depicted by the characters in Naipaul's novels. In his novel there is always a great sense of Indianness reflected in his following tradition, in observation of custom and rituals, in superstitions belief, in name, sex, in names and education language and in food habits. In all the novels of Naipaul we can be seen an Indianness to a large extent in the use of language and names. Questions of identity and selfhood are centered to any discursive formation of a nation. The individual in a postcolonial situation is continuously looking for a bounded, linear and ideological space wherein he can safely place his idea of nationhood. In a special issue brought out to mark fifty years of independence, one of the questions explored by *India Today* was:



Peer Reviewed Referred and UGC
Listed Journal (Journal No. 40776)

ISSN 2277 - 5730

AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY
QUARTERLY RESEARCH JOURNAL



AJANTA

Volume-VIII, Issue-I
January - March - 2019
English Part-III

IMPACT FACTOR / INDEXING
2018 - 5.5
www.sjifactor.com



Ajanta Press

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

24. Treatment of Communal Violence in Manju Kapur's 'Difficult Daughters'

Dr. Akshay V. Dhote

Head, Dept. of English, Sardar Patel Mahavidyalaya, Chandrapur.

Prof. Amrapali S. Devgade

Sardar Patel Mahavidyalaya, Chandrapur.

Abstract

Religious intolerance is the root cause for communal violence in the world. The whole world is in trouble and at war due to this intolerance. In the small history of three thousand years of human civilization the world has witnessed around fifteen thousand wars, which means five wars per year. And ironically these wars were fought for peace and harmony. Human being has not seen the era of peace and harmony because the time between two wars was always engaged for preparation for the next war. During these periods man has either fought the war or prepared for war. In present time though the efforts are going on to decrease the communalism in the society yet it has not shown any substantial result. Many Historians, authors, critics etc. have dealt with the themes like terror, communalism, violence and religious intolerance in their works with sincerity and fervor. They have tried to bring peace and harmony through their works by painting the trauma and sufferings of the victims of violence and creating awareness among the people.

Key Words: Communal, Violence, Intolerance, War, Peace.

Introduction

This research paper deals with Manju Kapur's 'Difficult Daughters' which is set in the background of religious and communal violence in India-violence at the time of partition and violence at the time of Babri Mosque demolition respectively. The novel reveals the protagonists' different responses to the trauma. It also suggests how the communal violence subsumes class, gender, national identity and religious identity. Women are often portrayed as victims of violence as evidenced in most of the works of feminist theorists like Ritu Menon and Kamla Bhasin. However, the female protagonists in Manju Kapur's novels are not directly affected by the communal violence and trauma but indirectly through other men in their lives. *Virmati and*



Golden Jubilee Year 2019-20 of
Department of Political Science

&

Shivaji University Political Science Association

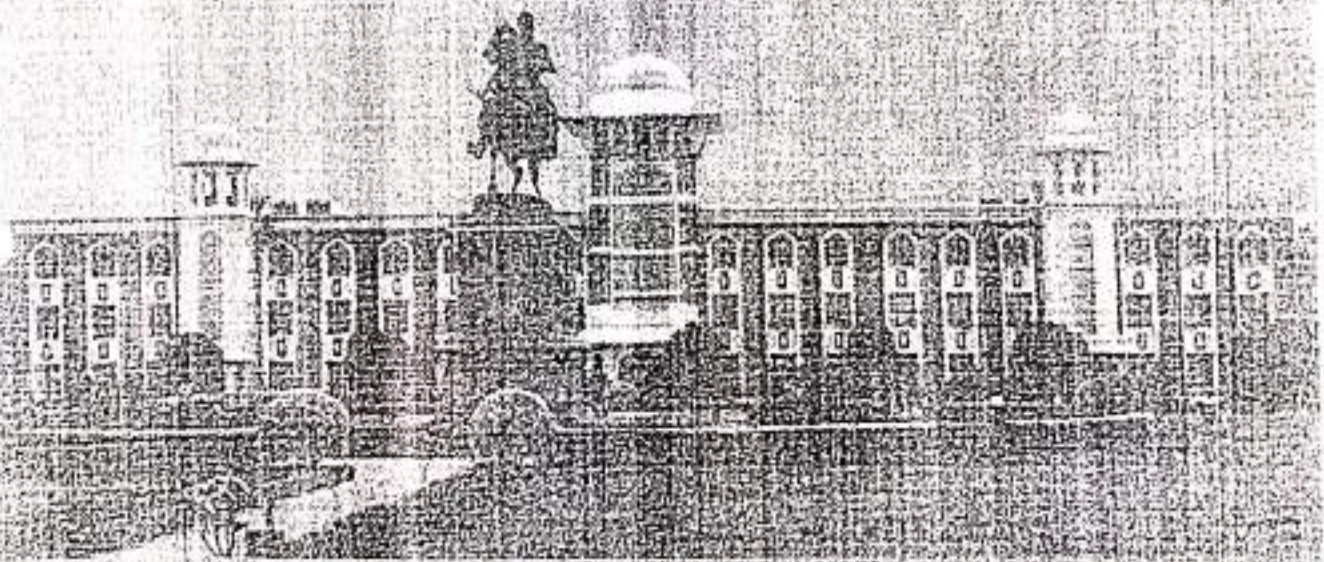
Conference Prociding of Two Days National Seminar

&

37th Maharashtra Political Science & Public Administration Conference

"Contemporary Issues in Political Science"

10th & 11th January 2020



Navijot

ISSN - 2277 - 8063

International Interdisciplinary research Journal

(Humanities, Social Sciences, languages, Commerce & Management)

Department of Political Science
Head of Department
(7th October 1970 to 11th January 2020)



Prof. N.D. Sakharikar
 (Oct 1970 to April 1981)



Prof. (Dr.) K.K. Kavlekar
 (May 1981 to Oct 1995)
 (1 Nov 2001 to Oct 2004)



Prof. (Dr.) L.R. Tarodi
 (1 Nov 1995 to 31 Oct 2001)
 (1 Nov 2007 to 31 Oct 2008)



Prof. (Dr.) Ashok Chosalkar
 (1 Nov 2004 to 31 Oct 2007)



Prof. (Dr.) Vasanti Rasam
 (1 April 2010 to 31 March 2013)



Prof. (Dr.) Bharati patil
 (1 April 2013 to 31 March 2016)



Prof. (Dr.) Prakash Pawar
 (1 April 2016 to 31 March 2019)



Prof. (Dr.) Ravindra Bhanage
 (1 April 2019 to till)



**Golden Jubilee Year 2019-20 of
Department of Political Science
&
Shivaji University Political Science Association
Conference Proceeding of Two Days National Seminar
&
37th Maharashtra Political Science & Public Administration Conference
“Contemporary Issues in Political Science”
10th & 11th January 2020**

**Editor
Prof. (Dr.) Ravindra Bhanage
Head of Department,
Political Science, Shivaji University, Kolhapur**



ISSN - 2277 - 8063

**International Interdisciplinary research Journal
(Humanities, Social Sciences, languages, Commerce & Management)**

गांधी आणि उत्तर गांधी विचारांची प्रासंगिकता

प्रा. डॉ. प्रमोद सुर्यभान शंभरकर

सहयोगी प्राध्यापक सरदार पटेल महा विद्यापीठ

पश्चिमात्य विचारवंत आणि म. गांधी यांनी मांडलेल्या विचारांतील भीमत्वाचा हा आहे की, पश्चिमात्य विचारवंत हे तैथील उपलब्ध परिस्थितीतून आपला दृष्टीकोन तयार करून विचारांची मांडणी करतात आणि त्यांच्यावर पश्चिमात्य वातावरणाच्या प्रभाव दिसतो. त्यांचे सर्व दृष्टिकोन हे राष्ट्रकेंद्रीत वाटतात. म. गांधींच्या वावरील तसे मात्र निमित्त नाही. भारतीय समस्यांच्या केवळ राजकीय अंगालाच त्यांनी हात मावला नाही तर भारतातील सर्वच सामाजिक समस्यांना स्पर्श करून अद्वितीयक सत्याचे प्रयोग राबविताना त्यांच्या विचारविश्वात सम्यक मानवतावादाची रेलचेल दिसते. गांधींनी आपल्या व्यक्तीगत जीवनात जे काही अनुभवले ते स्वतः सत्याच्या कसांटीवर पारखून व्यक्तिगत पध्दतीने त्यांनी वैचारीक चिंतनमाला लोकांपुढे ठेवलेली आहे. ते त्याचे व्यक्तिगत मत असूनदेखील व्यक्ति, समाज, राष्ट्रीय तसेच वैश्विक जीवनातही अत्यंत उपयुक्त ठरणारे आहे.

महत्त्वपूर्ण म्हणून मानल्या जाणाऱ्या १९ व्या शतकात गांधीवादाचा उदय झाल्या जगाला दिशा निर्देश करणारी एक वेगळी विचारसरणी व सात्विक दृष्टिकोन म्हणून गांधीवाद जगासमोर आला. ज्याची दखल आज संपूर्ण मानव जातीला घेणे भाग पडत आहे. मुख्यतः महात्मा गांधीने स्वताच्या जीवनपध्दतीला कोणत्याही वादाचे स्वरूप दिले नव्हते. ते म्हणतात " जगाला शिकविण्याइतके माझ्याकडे काहीही नाही. सत्य व अहिंसा हे सर्व प्राचीन पर्वताप्रमाणे अधिक प्राचीन आहेत, मी फक्त या तत्वांचा उपयोग माझ्या पध्दतीने व स्थितीनुसार आचरणात आणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे." गांधीजी स्वतःच्या जीवन पध्दतीला कोणत्याही वादाचे स्वरूप दिले नसले तरी त्यांची निश्चित अशी जीवनपध्दती होती. राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय समस्यांच्या निराकरणसाठी त्यांची एक विशिष्ट योजना, एक नवा दृष्टीकोन व नवपध्दती होती.

विशेष म्हणजे गांधींनी मांडलेले विचार हे भारतीय लोकांना नवे व काही वेगळ्या स्वरूपाचे नव्हते. बौद्ध व जैन धर्मात व्यक्ती जीवनात आचरणासाठी जे नियम प्रतिपादन केल्या गेले आहेत त्या नियमांनाच वा विचारांनाच गांधींनी सामुहिक जीवनात प्रयोग करून एक वेगळा आयाम देण्याचा प्रयत्न केला. व्यक्तीच्या कल्याणासाठी ज्या विचारांची गरज विविध धर्मांच्याद्वारे सांगण्यात आलेली आहे तेच विचार गांधींनी स्वतः संपूर्ण समाजाने कल्याणार्थ प्रतिपादन केले. त्यामुळे संपूर्ण समाजाचे कल्याण हा गांधींच्या आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक राजकीय इ. विचारांचा केंद्रबिंदू आहे. लोकांची सामाजिक शक्ती जागृत करण्यावर त्यांचा विशेष भर होता. सामुहिक अस्तित्वाची भावना मूळपासून गळकट्ट करणे हा त्यांच्या रचनात्मक कार्यक्रमाचा मुख्य हेतू होता. त्यामुळेच गांधीजींची कामगोरी आणि त्यांचा ऐतिहासिक व प्रेरणादायी प्रभाव या सर्वांचा विचार केल्या असता 'गांधी' हे एखाद्या उतुंग शिखराप्रमाणे भासतात. कारण जगाच्या इतिहासात जे शतक सर्वात अधिक हिंसाग्रस्त म्हणून गणल्या जाते त्या शतकात त्यांनी सर्वात मोठ्या व बलशाली साम्राज्याशी केवळ लढाच दिला नाही तर त्या लढ्यातून भारतीयांना स्वातंत्र्य मिळवून दिले.

म. गांधी यांच्या विकास विचारांचा केंद्रबिंदू म्हणून सर्वप्रथम व्यक्तीला मानून व्यक्ती या घटकाला प्राधान्य दिलेले आपणाने प्रत्यक्ष येते. संपूर्ण मानवीय हिताच्या मार्गातील मुख्य घटक म्हणून सर्वप्रथम व्यक्ती या घटकाकडे पाहिले जाते. व्यक्ती विकासातून कुटुंब विकास, कुटुंब विकासातून समाज, राज्य राष्ट्र व अखील मानव जातीच्या विकासाचा विचार त्यांच्या गांधीवादाने सारतत्व असलेले आपणाने दिसून येते. परंतु या गांधीवादाच्या भारतत्वाचा आधार सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, श्रमप्रतिष्ठा, स्वावलंबन आदींना त्यांनी प्राधान्य दिलेले आपणाला विसरून चालणार नाही. याने तत्वांचा आधार घेवून गांधींनी संपूर्ण जगाला आदर्श ठरतील अशा आदर्शवादी तत्वांना व्यवहारात आणून

वर्तमान तसेच भविष्यकालीन निर्माण होणाऱ्या समस्यांच्या निवारणाचा उत्तम मार्ग त्यांनी जगाच्या दाखविला आहे. या संदर्भात अल्बर्ट आइनस्टाईनच्या वक्तव्याचा प्रामाण्य नेणे संयुक्तरीत्या उघडेल, ते म्हणतात, " वक्तव्या गांधीजीसारखा माणूस खरोखरच या भूवल्बलचा वावरत असलेला वावर भावीकाळातील पीढ्या कल्पित विश्वास ठेवणारा जाहीर.

शिक्षण, धर्म, निती, राजकारण, अर्थकारण, वायदा, लग्नउद्योग, शेती, अस्वस्थता, दारूबंदी, आरोग्य या सारख्या सर्व क्षेत्रांत स्पर्श करणारा सर्वस्पर्शी विचार गांधींनी जगासमोर प्रस्तुत केला आहे. माणुसकीची शिक्षण देतानाच मानव जातीच्या कल्याणाच्या क्षेत्रात पंगीत होऊन त्यांनी आपले विचार मांडले. या विचारात नेतृकतेसाठी महत्त्वपूर्ण स्थान आहे. गांधी म्हणतात, " माणसाची नैतिक शक्ती हेच त्याचे खरे साधन आहे. माणूस अन्न, वस्त्र, निवास या सारख्या भौतिक गरजा भ्रामविण्यावर संतुष्ट महत्त्व नाही. कारण त्याच्या वक्त्री नैतिक गरजाही आहेत व त्या पूर्ण होणे देखील आवश्यक आहेत. त्यामुळे समाजाची रचना आणि उभारणी नैतिक पायावरच केली जावीजे " म्हणून त्यांनी अन्याय आणि जुलमाविरुद्ध लढण्यासाठी अहिंसा, सत्याग्रह, सविनय कायदेभंग, उपवास यासारखे नैतिक मार्ग उपयोगान आणले. अन्य विचारवंतांपेक्षा असलेले गांधींचे वेगळेपण त्यांच्या विचारांमध्ये असणारी प्रभावशक्ती इत्यादी कारणामुळे गांधी विचारांचे अवलोकन करून त्या विचारांची प्रासंगिकता जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.

महिला सबलिकरण :-

महिला सर्वाधिकारणात महात्मा गांधींनी मांडलेले विचार आणि त्या विचारातून दिलेली प्रत्यक्ष कृतीची जोड अत्यंत महत्त्वाची आहे. गांधींनी स्त्रीयांना नेहमीच पुरुषासमान मानले व तींचा आदर केला. अगदी स्वातंत्र्य लढ्यातही स्त्रीयांना सहभागी करून घेतले. त्यामुळे स्वातंत्र्यलढ्यात अनेक स्त्रीयांनी विविध चळवळीत सहभाग नोंदविला दिसतो. घरात कोडलेल्या अरंड्याची स्त्री जातीला मोकळ्या वातावरणात आणून त्यांना स्वातंत्र्य संग्रामात गुंतविले. त्यांच्या या सहभागामुळे स्त्रीयांच्या जीवनाकडे वचण्याचा दृष्टिकोन बदलला. गांधींनी महिलांमध्ये सन्मानाची भावना जागृत केली. हिंदू समाजातील अनेक जाचक रूढी व परंपरेचा गांधींनी कडाडून विरोध केला.

स्त्रीयांना आपल्या आत्मसन्मानाची जाणीव व्हावी, त्यांच्यातील माणुसपणाचे भान जागृत व्हावे यासाठी स्त्री शिक्षणाचा जोरदार पुरस्कार त्यांनी केला. त्यांना आत्मसन्मान मिळविण्याकरिता शिक्षणाशिवाय दुसरा कोणताही प्रभावी पर्याय नाही असे गांधींचे मत होते. म्हणूनच गांधींनी मुलांच्या शिक्षणापेक्षा मुलींच्या शिक्षणावर अधिक भर दिला आहे. शिक्षणाशिवाय स्त्रीयांनी उन्नती अशक्य आहे. स्त्रीयांनी आत्मसंरक्षणासाठी शिक्षण घेतले पाहिजे व आपला विकास साधला पाहिजे असे त्यांना वाटे. गांधींच्या मते "अहिंसा व स्वार्थत्याग यांचे मूर्तमंत स्वरूप म्हणजे स्त्री होय". म्हणून गांधींनी स्त्रीयांची आत्मीक शक्ती जागृत करून त्यांना राजकारणात व समाजकारणात सहभागी करून घेण्यावर भर दिला. स्त्रीयांचे परावलंबीत्व नाहीसे करून त्यांच्या स्वातंत्र्यासाठी, त्यांची प्रतिष्ठा वाढविण्यासाठी सर्व आधुनिक सुधारणांना पाठींबा दिला.

आजही २१ व्या शतकात अनेक पुरुष मंडळी सभा संमेलन व विविध परिणामांमध्ये स्त्री व स्त्रीजातीवर होणाऱ्या अन्याया विरुद्ध बोलते. स्त्रीच्या स्वातंत्र्याविषयी उदारता दाखवून तिच्या कार्याचे कौतुक करतात. मात्र घरच्या स्त्रीला ती स्वातंत्र्य नाकारत असतो. ऐवढेच नव्हे तर तीला अधिकार नाकारून तीचा आवाज दडपल्या जातो. मात्र १० वर्षांपूर्वीच या महात्म्याने अहिंसा स्त्री-शिक्षण, स्त्री -पुरुष समान दर्जा, विभवा विवाहाचा पुरस्कार इ. पुरोगामी विचारातून स्त्रीयांच्या उन्नतीचा, तींच्या सबलीकरणाचा मार्ग प्रशस्त केलेला दिसतो. त्यामुळेच गांधींचे स्त्रीविषयक व तींच्या सशक्तीकरणसंबंधात मांडलेले विचार हे आजही तितकेच प्रासंगिक किंबहुना महत्त्वाचे ठरतात.

पर्यावरणात्मक दृष्टिकोन :-

पर्यावरणासारख्या महत्त्वपूर्ण विषयावरसुद्धा गांधींनी आपले विचार मांडले. तसेच त्या विचारांना आपल्या कृतीची जोड देत सामुहिक शेती, सैद्धीय शेती, स्वच्छता, सफाई इ.

च्या माध्यमातून गांधींनी पर्यावरणाच्या रक्षणार्थ आवाहनही केले. पर्यावरणाच्या दृष्टीने गांधींनी मांडलेले विचार महत्त्वाचे आहे. आज तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने व तंत्रवेगळ्या कारणामुळे उत्पादनात जी वाढ झालेली आहे. त्यामुळे पर्यावरणाची हानी होत आहे. वास्तव येण्यात येणारी पीके, रासायनिक खतांचा अतिरेकी वापर यामुळे जमिनीची गुणवत्ता कमी होऊन बंजर जमिनीचे क्षेत्र वाढत चालले आहे. हवा, पाणी, अन्न दूषित होत असून जमीन, वन यांना वेगाने न्हास होत असल्याचा गंभीर इशारा विविध संस्थांकडून व पर्यावरण अभ्यासकांनी आपल्या संशोधन अहवालातून दिलेला आहे.

गांधींनी आपल्या १९०९ च्या हिंद स्वराज्य मध्ये लिहिलेल्या एका लेखात पर्यावरणाविषयी गंभीर तितकेंच मार्गदर्शी पद्धतीने चिंता व्यक्त करताना औद्योगिक व्यवस्थेने त्यांनी रीतांनी संस्कृती असे वर्णन केले. तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीचे पुढचे टप्पे धुकट होण्यापूर्वी त्यांच्या अमानवीय व हिंस्र परिणामांचा गांधीजींनी अचूकपणे अंदाज घेतलेला आहे. गांधी लिहतात, "वर्तमानातील अराजकता त्यात निर्माण होणारी अंधाधुन आणि उद्भवलेले शोषण यांना मोठी यंत्रे जबाबदार आहेत. विज्ञानाच्या शोधातून वास्तव्य, मानवी कल्याण व त्याचे शाश्वत जीवन समृद्ध व्हायला पाहिजे होते परंतु नेमके उलट यामुळे घडलेले आहे." खर म्हणजे गांधींचा यांत्रिकीकरणाला विरोध नव्हता किंवा त्यावर त्यांनी कधीही टोकाची भूमिकाही घेतली नाही. तर यंत्राच्या माध्यमातून होणाऱ्या विनाशावर गांधींनी चिंता व्यक्त केली आहे.

गांधींनी आपल्या विविध लेख तसेच भाषणातून पर्यावरणाच्या संरक्षणाविषयी प्रस्तुत केलेल्या विचारात कमीत-कमी वस्तूंचा उपयोग, पाण्याचा संग्रह, वृक्ष लाववड, पर्यावरण पुरक जीवजंतुची हिंसा न करणे, रासायनिक खतांचा वापर टाळणे व मानवी गरजा भर्यादीत ठेवण्यासाठी प्रत्यनशील राहणे इ. रचनात्मक बाबींचा समावेश केलेला दिसतो. गांधींचे हे विचार आजही मानवी जीवनात विकासाचे विविध टप्पे गाठत असतांना पदोपदी दिशा निर्देश करणारे असेच आहेत. विशेषतः केदारनाथ येथील जलप्रलय व अलिप्तकडेन राजधानी दिल्लीतील प्रदुषणाने गाठलेली धोक्याची पातळी इ. घटना व निसर्ग रचनेची हानी पाहता आजच्या वर्तमान परिस्थितीत गांधींचे विचार उपयुक्त ठरतात.

आर्थिक विचारधारा :-

गांधीजी हे काही विशेष अर्थशास्त्रज्ञ नव्हते तसेच त्यांनी कोणताही अर्थशास्त्रीय सिध्दांतही मांडला नव्हता. असे असले तरी गांधींनी वेळेवेळी व्यक्त केलेल्या आर्थिक विचारावर जेवढी चर्चा झाली व जेवढे लिखाण झाले तेवढे आधुनिक काळातील कोणत्याही भारतीय तज्ञांच्या आर्थिक विचारांच्या बाबतीत झालेली दिभून येत नाही. मानवी मुल्यांची जोपासना, साधे राहणीमान, विकेंद्रीत अर्थव्यवस्था, ग्रामोद्योग, विकेंद्रीकरण, लोकसंख्या नियंत्रण तसेच कृषीविषयक साधक बाधक विचारांची मांडणी इ. रचनात्मक विचारातून गांधींनी आपल्या आर्थिक विचारांची मांडणी केलेली आहे.

गांधींचे अर्थशास्त्र हे नितीशास्त्राशी संबंधीत आहे. याबाबतीत गांधीजी म्हणतात की, "जे अर्थशास्त्र नैतिक व भावनात्मक मुल्यांकडे लक्ष देत नाही, ते अर्थशास्त्र ज्यात जीवन असूनही सजीव जीवनाचा अभाव असतो. अशा एका मधमाश्याच्या पोळ्याप्रमाणे आहे." ज्याप्रमाणे गांधींनी राजकारणात नैतिकतेला स्थान दिले आहे. त्याचप्रमाणे आर्थिक व्यवहार व त्यांच्या आर्थिक विचारातही नितीशास्त्राशी सांगड घातली गेल्याचे दिसते. अर्थशास्त्राची नैतिकशास्त्राशी फारकत करावयास ते तयार नाहीत. कारण मानवी कल्याणाचा विचार न करणारे अर्थशास्त्र त्यांना अमान्य होते. गांधींनी पैसा व भौतिक संपत्तीपेक्षा नैतिक व मानवी मुल्यांवर आपल्या अर्थशास्त्रीय विचारात भर दिला.

गांधी देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या बळकटीकरणावरही आपले मत व्यक्त करतात. मोठ्या यंत्रप्रधान उद्योगगंधाऐवजी लहान उद्योगांचे निर्माण, उद्योगांचे विकेंद्रीकरण लहान उद्योगांच्या विकासाने दारिद्र्य व बेकारीची समस्या दूर होऊ शकेल. यामुळे संपत्तीच्या केंद्रीकरणालाही आडा बसेल संपूर्ण भारताच्या विकासासाठी उद्योगधंद्याचे विकेंद्रीकरण होणे गरजेचे आहे असे त्यांचे मत होते. त्याचप्रमाणे बेकारीवर पलट करण्याकरिता गांधी उपाय

Dec-2019 ISSUE- IV, VOLUME-VIII

Published Quarterly issue

With ISSN 2394-8426 International Impact Factor 6.222

Peer Reviewed Journal



Published On Date 31.12.2019

Issue Online Available At : <http://gurukuljournal.com/>

Organized &
Published By

Chief Editor,
Gurukul International Multidisciplinary Research Journal
Mo. +919273759904 Email: chiefeditor@gurukuljournal.com
Website : <http://gurukuljournal.com/>



INDEX

Paper No.	Title	Author Name	Page No.
1	A Study Of Tendu Leaves Collection Business In Bhandara District	Dr. Aniruddha Sunil Gachake	1-3
2	Biochemical Changes In Hematological And Liver Function Parameters In Male Albino Rats Treated With Genetically Modified Cotton Seed	Prachi S. Dandge, Dr. Varsha V. Andhare	4-9
3	Cause & Prevention Of Injuries In Sports	Rajesh Kailabag&Dr. O. P. Aneja	10-12
4	The Effectiveness Of Language Games On Yemeni Students' Learning English In Secondary Schools	Yahya Ahmed Ahmed Qellah&Dr. Shobhana V. Joshi	13-21
5	India And Central Asia Relations	Sabavath Ravi	22-26
6	Cause, Symptoms, Treatment And Prevention Of Injuries In Sports	Rajesh Kailabag& Dr. O. P. Aneja	27-31
7	KURMAGHAR: The barrier in access to healthy life and freedom for Madia-Gond Tribes	Dr. Dilip Keshawrao Barsagade	32-34
8	Water Resources Development In Maharashtra	S.A.Nagre&S. T. Sangle	35-41
9	Tourism Development in Markanda Temple at Chamorshitahsil, Gadchiroli District	Dr. Rajendrakumar K. Dange	42-46
10	Translation Pedagogy in Teaching English as a Second Language: Some Issues	Amol J. Kutemate	47-49
11	Indo-Myanmar Border Trade and Manipuri Society: Long Term Implications on India's Look/Act East Policy	Padmabati Khundrakpam	50-59
12	Right to Information Act, 2005 – Formal Introduction	Ku. Madhuri J. Rakhunde&Dr. R. P. Ingole	60-61
13	जनजातीय विकासमें शिक्षा की भूमिका (छत्तीसगढ़ राज्य के दन्तेवाड़ा जिले के गोंड जनजातीय के विशेषसंदर्भ में)	अशोक कुमार नाग	62-68
14	महात्मा गाँधी के विचारों के फलस्वरूप सामाजिक ढाँचेमें हुए सुधार के विविध आयामों का एक विवेचात्मक अध्ययन	Rakesh Kumar saini	69-72
15	अम्लीय व मादकपदार्थों के युवा शर्मावर होणारे दुष्परिणाम व उपाय	प्रा. डॉ. जयदेव पी. देवमुख	73-77
16	सामाजिकरणाच्या प्रक्रियेत शिक्षणाची भूमिका	प्रा. डॉ. आर. बी. माटे	78-80
17	पाली साहित्यातील पर्यावरण संवर्धन	डॉ. प्रतिभा बी. पखिडे	81-83
18	राष्ट्रसंत तुकडोजीचे तत्वज्ञान व आजची सामाजिक परिस्थिती	प्रा. धनराज डी. मुरकुटे	84-87
19	ग्रामीण विकास : सामाजिक व आर्थिक अडथळे (Rural Development : Social and Economic Obstacles)	Prof. Dr. J. P. Deshmukh	88-92
20	पर्यावरण आणि जनजाती : काळाची गरज	डॉ. एम. एफ. गऊंगडे	93-95



Translation Pedagogy in Teaching English as a Second Language: Some Issues

Amol J. Kutemate

Assistant Professor

Deptt. Of English

Saradr Patel Mahavidyalaya, Chandrapur

amolkutemate111@gmail.com

Abstract

Employment of translation as a method in teaching English as a second or foreign language has always been a controversial issue among teachers, administrators and policy makers. It had been deprecated until the advent of new language theories and approaches. With the emergence of post-modern theories like constructivism, localism, relativism etc., translation studies have received new insights in the field of English language teaching. In the context of multilingualism and multiculturalism, there is a need to rethink about the use of translation pedagogy in the domain of English language teaching. This paper attempts to throw light on some of the vital issues of translation pedagogies in the context of teaching English language as a second language.

Key words: Translation, Pedagogy, Teaching English as a Second Language (TESOL), English Language Teaching (ELT), First language (L1), Second language (L2)

Introduction

Translation is the communication of meaning from one language (the source) to another language (the target). Translation refers to written information. It is different from interpretation, which refers to spoken information. The purpose of translation is to convey the original tone and intent of a message, taking into account cultural and regional differences between source and target languages. The word pedagogy has been adopted from the field of education. It is simply defined as a method or practice of teaching. But in the present sense, it is an educational process of imparting specific skill or knowledge to the new learner. Pedagogy should be shaped by teacher's personal experiences. It must take into consideration the context in which learning takes place. While thinking about translation as a pedagogy, it should be considered as a strategy leading to the achievement of meaningful cognitive learning.

Barrier or booster

In the field of English language teaching, translation is often associated with Grammar- Translation method. This is still a popular method among teachers and students in non- English medium schools, where English is taught as a second or foreign language. "Grammar translation is a way of studying a language that approaches the language first through the detailed analysis of its grammar rules, followed by application of this knowledge to the task of translating sentences and texts into and out of the target language" (Richards and Rodgers 2001: 5). Translation is considered to be a barrier in learning English. Some of the major objection against it are: Teacher centric method, no place for listening and speaking skills, focus on mother tongue and ignorance of the target language, emphasis on grammar rules etc. These



objections are true to large extent as per as the present application of the method is concerned. To overcome these challenges, there is need to dissociate the linking of grammar and translation. Comprehension and expression should be the key features of the translation pedagogy. Translation could prove to be an effective pedagogy in teaching English as a second language. In the post- method era, when the prescribed western methods are outdated, translation could be a booster in English language teaching.

Bilingualism and Multilingualism

In a multilingual country like India, "English does not stand alone. The aim of English teaching is the creation of multilinguals who can enrich all our languages; this has been an abiding national vision. English needs to find its place along with other Indian languages in different states..." (NCF: 2005). Translation pedagogy can play a great role in dealing with the bilingual or multilingual environment in the classroom. There is a natural tendency in a bilingual learner towards translation while learning a second or foreign language. In a study on translation and multilingualism by European Union, translation has been recognised as a fifth skill along with listening, speaking, reading and writing. It considers a fundamental skill to the bilingual mind.

Bridging the gap

Lack of self-motivation in English learning is a great challenge before the teachers and learners, especially in rural areas. Students lack basic proficiency in applying language skills especially reading and writing inside and outside the classroom. As per Right to Education Act (2009), students are naturally promoted up to 8th standard and there is no proper assessment of their language skills. The result is that most of the students lack basic language skills required in higher grade classes. It creates a huge gap between the existing skills and the required skills. Translation pedagogy can bridge this gap especially in reading and writing skills. If students are equipped to comprehend and express the content from source language to target language or vice versa, they feel confident at least in reading and writing. A little progress in these skills could make them self-motivated.

Design and practice

Translation has been criticised not only because of the drawbacks of Grammar- translation method but also the way it has been practiced in the classroom. It has been used extensively for the convenience of the teachers rather than the students. Actually, Translation pedagogy could be an effective tool for teachers and students in learning English. Rural students, who are not competent enough in applying basic language skills, give much importance to reading and writing skills. These are required for passing the examinations. Listening and speaking skills are ignored by students because these skills are not tested in the examinations and not required in their routine life. Though teachers should have integrated approach towards all the skills, reading and writing need to be focussed in regional language medium schools. Learners in these schools do not have much exposure to English except prescribed English textbook. Teachers and the textbooks are the major resources of learning English for rural students. In this context, use of first language (L1) could be helpful in teaching English (L2).



Designing translation pedagogy becomes a great challenge in non- English medium schools. Most of the time, while teaching complex concept or content in L2, judicious use of L1 is important. Balanced use of L1 and L2 is imperative in practicing the translation pedagogy.

Conclusion

In India, there are twofold goals for English language teaching: first the attainment of a basic proficiency such as is acquired in natural language learning, and the second is the development of language into an instrument for abstract thought and knowledge acquisition. For the basic proficiency in and reading and writing at the primary level, translation pedagogy is one of the effective tools, especially in non- English medium schools. It is also helpful in bridging the skill gap at the secondary and higher secondary school level. Use of L1 makes students comfortable in learning a foreign or second language. Even slight progress in making translation could boost their confidence in learning English. Though translation has not been given due importance by policy makers in the past, it has been gaining importance in the bilingual and multilingual contexts. Designing and practising student- centric translation pedagogy requires training and support to teachers. Material design and assessment need attention in relation to translation pedagogy. So, Translation pedagogy could become an outcome-based pedagogy, if L1 and L2 are judiciously used in the second language classroom.

References:

- Richards Jack and Rodgers Theodore. *Approaches and Methods in Language Teaching*. Cambridge UP, 2001.
Susan Bassnett, *Translation Studies*, Routledge, 2005.
European Union, *Studies on translation and multilingualism*, 2013.
<https://www.gala-global.org/industry/intro-language-industry/what-translation>
http://www.ncert.nic.in/new_ncert/ncert/rightside/links/pdf/focus_group/english.pdf
<http://www.ncert.nic.in/rightside/links/pdf/framework/english/nf2005.pdf>

Assessment of Nutrient Status of Soil from Korpana Tehsil of Chandrapur District, Maharashtra, India

M. K. Mandal¹, S. B. Rewatkar², R. P. Dhankar³, G. D. Satpute⁴

¹Raje Dharmrao College of Science, Ahori, Gadchiroli District, Maharashtra, India-442705

²Dean, Faculty of Science and Technology, Gondwana University, Gadchiroli, Maharashtra, India-442605

³Sardar Patel College, Chandrapur, Maharashtra, India-442402

⁴Shri. Govindrao Munghate Arts and Science College, Kurkheda, Gadchiroli District, Maharashtra, India-441209

⁵Corresponding author- sbrewatkar@gmail.com

ABSTRACT:

Soil is important source of nutrients for crops. Soil provides support for plant growth in various ways. The crop yields depend upon the quality of soil and quality is decided by nutritional enrichment of that soil. In present investigation nutritional survey of soil samples from selected sites of Korpana tehsil was carried out. Standard protocols were used for the estimation of chemical parameters such as pH, Electrical Conductivity (EC), Organic Carbon (OC) and micronutrients (NPK). From the results it is concluded that all the soil samples shows good fertility status.

KEY WORDS: Micronutrients, Organic Carbon, pH, EC, Fertility Status

INTRODUCTION:

The cotton crop is generally grown in medium to deep black clay soil, it also grown in sandy and sandy loam soil through supplemental irrigation by farmers. The soils with an excellent water holding capacity is the quality soil for cotton crop. The fertility of soil is related with the organic carbon present in the soil. Thus, it is necessary to evaluate organic carbon of the soil time to time to enhance crop yield year by year. The loss in crop productivity has been related with the loss of soil organic matter and stored nutrients that results from cultivation (Juo *et al* 1996). India is the third largest producer of cotton, producing 15% of the worldwide production (Roberson 2000).

Soil is the habitat of a diverse array of organism which includes both micro flora and fauna. Soil micro-organisms play a vital role in soil fertility not only because of their ability to carry out biochemical transformation but due to their importance as a source and sink of mineral nutrients.

Cotton has been used as a fabric in India from time immemorial. It has been cultivated in the Indus valley more than 5000 years. Due to the high production of cotton in Chandrapur district, present investigation focused on study of organic carbon in Cotton based cropping system.

Literature on soil organic carbon and the role of microorganism in the rice and cotton based cropping system studied by number of researches. But the study on nutritional survey and physicochemical parameter of Korpana tehsil soil of Chandrapur district was not investigated. So the present investigation will focus on evaluation and estimation of chemical parameters such as pH, EC, OC and micronutrients (NPK).

METHODS AND MATERIALS:

Ten soil samples were collected from various villages of Korpana tehsil of Chandrapur district in the polythene bag. The samples were dried and passed through 2 mm sieve and stored in polythene bags. The soil pH and EC determined by water extract method. Organic carbon was estimated by Walkley and Black method. The available Nitrogen (N), Available Phosphorous (P) and available Potassium (K) were estimated by standard methods, Alkaline Permanganate method, Olsen's method and Flame photometry method respectively.

EXPERIMENTAL:

Table 1- Soil fertility parameter of the soil from selected area of Korpana tehsil.

Sr. No	Name of Farmer	Villages	Survey No.	OC (%)	pH	EC (dS/m)	N (Kg/ha)	P (Kg/ha)	K (Kg/ha)
1	Keshao A. Mahale	Uparwahi	35/1	0.71	8.08	0.12	185.6	15.3	209.5
2	Prabhakar M. Karekar	Katalbodi	6/1,32	0.58	7.39	0.13	186.2	21.4	258.4
3	Ramu S. Rathod	Kusula	26/2	0.68	8.05	0.15	304.5	14.2	442.2
4	Vinod M. Malekar	Jewara	158	0.67	7.86	0.10	294.6	16.9	201.5
5	Tulshiram R. Sidam	Chopar	73	0.63	7.85	0.13	302.4	22.8	389.4
6	Mangesh N. Padave	Kanalgaon	130	0.70	7.92	0.13	205.6	17.1	284.6
7	Shyam D. Randive	Korpana	4	0.73	8.33	0.13	281.3	28.6	256.1
8	Dodaji K. Mohurle	Akodi	123/13 7	0.63	7.72	0.14	254.6	22.5	305.4
9	Anita K. Kinnake	Khataki	42	0.62	7.34	0.12	294.6	18.8	415.9
10	Keshao V. Virutkar	Talodhi	202/2	0.52	7.34	0.12	338.9	23.7	402.6

RESULTS AND DISCUSSION:

1. Organic Carbon:

Organic matter plays vital role in agricultural soil, which supply plant nutrient, improve the soil structure, water infiltration and retention, feed soil micro flora and fauna (Johnston, 2007). The data (table 1) revealed that OC status of all soil samples ranged between medium to slightly high i.e. 0.52% to 0.73%. These are the reliable range of OC in the soil.

II. Soil pH:

Soil pH indicates an acidic and an alkaline status of soil the fact is that, most of the mineral and nutrients are soluble in acidic soil than in neutral or slightly alkaline soil. A pH range of approximately 6 to 7 promotes the most ready availability of plants nutrients (Gobinder Singh *et al.*, 2016). The data (table 1) indicated that, the variation of pH ranges from 7.34 to 8.33 which are neutral to alkaline in nature. It has been suggested, an application of elemental sulphur for reduction of pH (Zhao *et al.*, 2015).

III. Electrical Conductivity:

The electrical conductivity (EC) is the measure of the soluble salts present in the soil. Excess amount of dissolved salt in the soil solution causes hindrance in normal nutrients uptake process either by imbalance of ion uptake, antagonistic effect between the nutrients or excessive osmotic potentials of soil solution or a combination of the three effects (Rahman *et al.*, 2010). The data (table 1), the variation of EC ranges from 0.12 to 0.15 ds/m, which are safe level to soil nutrients.

IV. Available NPK: -

Nitrogen is essential for plants nutrient. It should be present in the soil in appropriate proportion for the plant growth (Deshmukh K., 2012). Available nitrogen status varied from 185.6 to 338.9 Kg/ha. which are low to medium in ranges. Phosphorus has been called as "Master key to agricultural". It is essential to plant growth, cell division, root growth, fruit development and early ripening of the crop. The data (table 1) revealed that means value of available P were 14.2 to 28.6 Kg/ha. Similar results were reported by Pathak (2010) who concluded that, available P ranges from medium to high category. The potassium (K) is the important for plant because it participates in the activation of large number of enzyme which is involved in physiological process of plants. It controls the water economy and provides the resistance against the number of pests, disease and environmental stress. The high status of available potassium was found in Korpana tehsil. The value of K, variation from 201.5 to 442.2 Kg/ha.

CONCLUSION:

The chemical properties of soil was analyzed for 10 villages from Karpurk sub-district of Choudhary district. The parameter such as OC, pH, EC and available micronutrient(DPK) were studied. Data of organic carbon revealed low to medium range. The pH and Electrical conductivity of the study area is fairly to good for agricultural. Nitrogen value is low to medium, phosphorus value found in medium to high category similarly potassium value is high in all the soil samples. The overall nutrient status is good for cotton crop, based on the base line data prepared in research work.

REFERENCES:

- Dindanishi E. K. (2011). Evaluation of soil fertility status from categorised area, Ahmednagar district, Maharashtra, India. *Ravon Journal* 5 (3): 396-400.

Ecosystem and Environment 58: 49-60

- Gokuldas Singh, Manoj Sharma, Jatin Das Mann and Chiranjit Singh (2016). Assessment of soil fertility status under Different Cropping sequences in district Kapurthala. *Journal of Krishi Vigyan* 5(1): 1-9.
- Johnston A. E. (2007) Soil organic matter, effect on soil and crop. *Soil use and management* 21(1): 97-105.
- Jha ABR, Mann A. (1996). Chemical dynamics in slash and Burn agriculture.
- Pathak H (2010). Trends of fertility status of Indian soil. *Current Advances in Agricultural Sciences* 2(1): 10-12.
- Rahman O, Ahmad B and Afral S (2010). Soil fertility and salinity status of Amrit district. *Journal of Agricultural Research* 48 (4): 505-516.
- Robinson, R. R. (2000). Major World Cotton Producers for 1999-2000. Beltwide Cotton Conference.
- Zhao C., Degryse F, Gupta V, McLaughlin M. J. (2015). Elemental sulphur isolation in Australian cropping soil Sci. SOC. Am. J. 79: 89.



‘महाराष्ट्रातील प्रादेशिक वनक्षेत्र व सामाजिक वनीकरण — एक भौगोलिक अध्ययन’

डॉ. वनश्री एन. लाखे
भूगोल विभागप्रमुख,
सरदार पटेल महाविद्यालय, चंद्रपूर

मनुष्याच्या अनेकविध गरजा प्राचीन काळापासून भागविण्याचे सामर्थ्य वनात आहे. जंगल ही राष्ट्राची संपत्ती असते. वनसंपत्तीचा विकास व राष्ट्राचा आर्थिक विकास यांचा निकटचा संबंध असतो. त्यादृष्टीने सन १९५० मध्ये श्री के.एम. मुन्शी यांनी वन महोत्सवाला सुरुवात केली. वनधोरणानुसार नैसर्गिक समतोल राखण्यासाठी एकूण जमिनीचा ३३ टक्के भाग वनाखाली केली. वनधोरणानुसार नैसर्गिक वनस्पती ही नैसर्गिक संपत्तीचा महत्वाचा घटक आहे. संरक्षण, असावयास पाहिजे. नैसर्गिक वनस्पती ही नैसर्गिक संपत्तीचा महत्वाचा घटक आहे. संरक्षण, उत्पादन, सामाजिक आणि जैव सौंदर्याची कार्ये वने करतात. महाराष्ट्र राज्यात असलेल्या वनांच्याद्वारे प्रादेशिक विषमता आणि त्यावर वाढत असलेला जैविक ताण यामुळे वनक्षेत्र पडित होण्याची भीती आहे प्रस्तुत शोध निबंधात महाराष्ट्रातील वनाविषयी व सामाजिक वनीकरण कार्यप्रणालीचा अभ्यास करण्यात आलेला आहे. सन १९९२ पासून महाराष्ट्रात खाजगी पडित जमिनीवर वृक्ष लागवड व कृषि विकास योजना अंमलात आणलेली आहे. सामाजिक वनीकरणामुळे पर्यावरण संतुलन व ग्रामीण भागात रोजगार मिळण्यास मदत होईल पर्यावरणाचा समतोल राखण्यामध्ये सामाजिक वनीकरण विभागाची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे.

बीज शब्द :- वनमहोत्सव, जैव सौंदर्य, वनक्षेत्र

प्रस्तावना :-

महाराष्ट्राचे भूमी उपयोजनात कृषीनंतर वानिकी विभागाचा दुसरा क्रमांक आहे. महाराष्ट्रामध्ये सामाजिक वनीकरण कार्यक्रम वर्ष १९८७ पासून सुरू करण्यात आला. ग्रामीण जनतेची वैरणाची गरज भागविण्यामध्ये सामाजिक वनीकरण विभागाची महत्वाची भूमिका आहे.

भारतातील २९ घटक राज्यांपैकी महाराष्ट्र हे एक राज्य आहे महाराष्ट्राचे भौगोलिक स्थान १५° ४८' उत्तर अक्षवृत्त ते २२° ६' उत्तर अक्षवृत्त असून रेखांश विस्तार ७२° ३६' पूर्व रेखावृत्त ते ८०° ५४' पूर्व रेखावृत्त आहे. महाराष्ट्राची पश्चिम पूर्व लांबी सुमारे ८०० किमी. असून दक्षिणोत्तर रुंदी सुमारे ७२० किमी आहे. महाराष्ट्राचे क्षेत्रफळ ३०७७१३ चौ.कि.मी. आहे महाराष्ट्र उष्ण कटिबंधीय वर्षारण्य निम्न शुष्क हवामान प्रदेश व मान्सून सॅव्हाना हवामान विभागात मोडतो

संदर्भ :- महाराष्ट्राचा भूगोल ए. बी. सक्दी सर

अभ्यास क्षेत्र :-

भारताच्या साधारण मध्यवर्ती भागात महाराष्ट्र असून उत्तर भारत व दक्षिण भारताला एकत्रित आणणारी विशाल भूमी आहे. भारतीय द्वीपकल्पाचा एक भाग महाराष्ट्र पटार आहे. देशाचा पश्चिम व मध्य भाग व्यापलेल्या महाराष्ट्र राज्यास पश्चिमेकडील सहयाद्री पर्वताच्या रांगा उत्तरेकडे सातपुडा पर्वताच्या रांगा पूर्वेस भामरागड चिरोली गायखुरी या झोणरांगा राज्याच्या नैसर्गिक सीमा आहे महाराष्ट्रातील प्राकृतीक रचना, हवामान, वनस्पती व



अरण्याच्या प्रकारातील विविधता यामुळे वन्य पशु-पक्ष्यांची संमृद्धी जोपासण्यास योग्य आहे या राज्यात ८५ जातीचे सस्तन वन्य पशु व ४६० जातीचे पक्षी आहेत. याशिवाय जमिनीवर सरपटणारे जल व स्थलात राहणारे अनेक जातीचे प्राणी व किटक वनांमध्ये आहेत. महाराष्ट्रातील ५२.०१ लाख हेक्टर जमीन वनांखाली आहे.

प्रस्तुत शोध निबंधात महाराष्ट्रातील वनक्षेत्र व सामाजिक वनीकरणाचा अभ्यास खालील उद्दिष्टांना अनुसरून केला आहे.

उद्दिष्टे :-

१. महाराष्ट्रातील प्रादेशिक विभागानुसार वनक्षेत्र व वन्यविभाग अभ्यासणे.
२. वन्यजीव व जैवविविधता संवर्धन महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय उद्यानाच्या संदर्भात अभ्यासणे.
३. महाराष्ट्रातील वनविभागाचे वर्गीकरण वनप्रकारानुसार पाहणे.

सांख्यिकी माहिती व संशोधन पद्धती :-

सदर शोध निबंधासाठी प्राथमिक व दुय्यम माहितीचा उपयोग केलेला आहे याशिवाय निरीक्षण तंत्राचा अवलंब करण्यात आला आहे. प्रस्तुत शोध निबंधात दुय्यम आकडेवारी प्राप्त करून त्याचे विश्लेषण करण्यात आले त्या आधारे विविध नकाशा शास्त्रीय पद्धतीचा वापर केलेला आहे महाराष्ट्रशासन महसुल व वनविभागा अंतर्गत महाराष्ट्र राज्याचे वनक्षेत्र २००८ यातून माहिती घेण्यात आली याशिवाय संदर्भ पुस्तके, विविध लेख, नियतकालिके यावर आधारित लेख इत्यादींचा संदर्भ साहित्य म्हणून वापर केलेला आहे. संकलित माहितीच्या आधारे तक्ते तयार करून विश्लेषण करण्यात आलेले आहे.

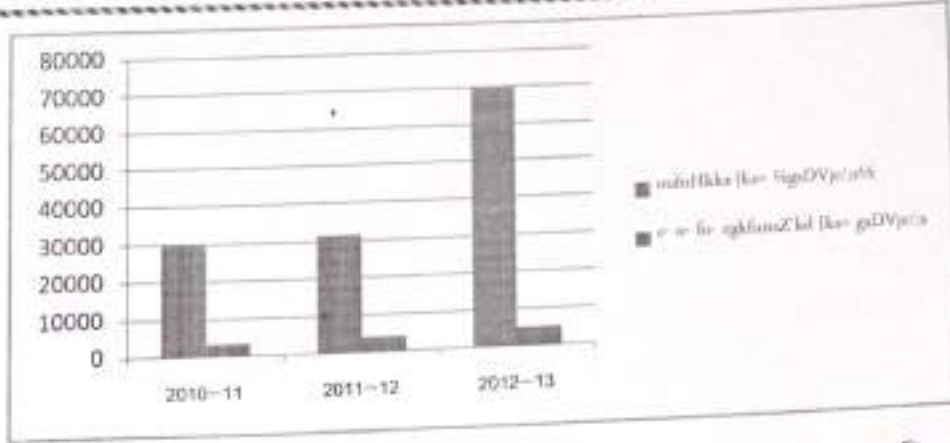
महाराष्ट्रातील वृक्षारोपण :-

वृक्षारोपण हा २० कलमी कार्यक्रमाचा एक भाग असून याची अंमलबजावणी मुख्यतः महाराष्ट्र वन विभाग महानिर्देशक व सामाजिक वनीकरण संचालनालयामार्फत करण्यात येते. महाराष्ट्र शासनातर्फे ३३ करोड वृक्षारोपणाचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले होते आणि या उद्दिष्टाला पूर्ण करून ३३.१२ करोड वृक्षारोपण करण्यात १२.३२ लाख लोकांनी सहभाग दिला असून याकरिता २.७८ लाख site चा सहभाग होता.

महाराष्ट्रातील वृक्षारोपणांतर्गत क्षेत्र

वर्ष	वनविभाग क्षेत्र (हेक्टरमध्ये)	म. व. वि. महानिर्देशक क्षेत्र हेक्टरमध्ये
२०१०-११	३०१९०	३२२३
२०११-१२	३१३६९	४०११
२०१२-१३	७०१५३	४८४७

(आधार - सामाजिक वर्गीकरण संचालनालय महाराष्ट्र शासन)

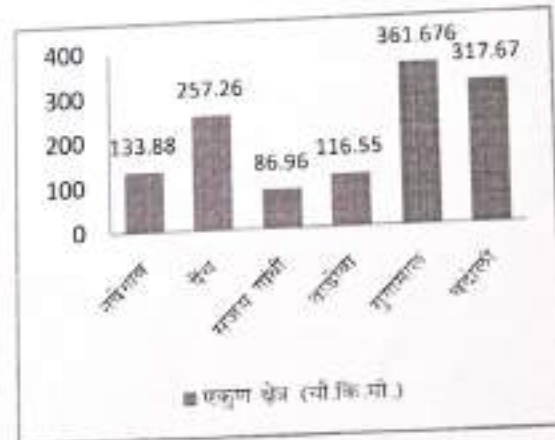


वरील तक्त्यावरून हे निदर्शनास येते की, २०१०-२०११ या वर्षात वनविभाग अंतर्गत ३०१९० हेक्टर क्षेत्र होते तर २०१२-१३ मध्ये ७०१५३ हेक्टर एवढी वाढ झालेली दिसून येते. महाराष्ट्रातील वनक्षेत्र व जैवविविधता :-

महाराष्ट्रातील वनविभागाचे मुख्य कार्यालय नागपूर येथे आहे. या व्यतिरिक्त अकरा वनवृत्त विभागाचे कार्यालय असून अमरावती, औरंगाबाद, चंद्रपूर, धुळे, गडचिरोली, कोल्हापूर, नागपूर, नाशिक, पुणे व यवतमाळ येथे आहे तसेच तीन वन्यजीव विभाग म्हणजे बोरीवली, नागपूर व नाशिक येथे आहे.

महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय उद्याने व क्षेत्र

राष्ट्रीय उद्याने	एकुण क्षेत्र (चौ.कि.मी.)
नवगाव	१३३.८८
पेंच	२५७.२६
संजय गांधी	८६.९६
ताडोबा	११६.५५
गुणामाल	३६१.६७६
चंदोली	३१७.६७०



महाराष्ट्रात राष्ट्रीय उद्याने जैवविविधतेत प्रथम क्रमांकात असून ताडोबा व भामरागड क्षेत्र विशेष आहे. संरक्षित व राखीव क्षेत्राबाहेरील वन्यजीवांचे महाराष्ट्र संरक्षण व व्यवस्थापन संदर्भात जैवविविधता संवर्धनात विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे जीवशास्त्र सर्वेक्षणानुसार १०६५ जाती वनस्पतीच्या व ६४२ (इतर), जातीमध्ये येतात. पश्चिम घाट परिस्थितीकी जैवविविधतेत मुख्यतः महत्त्वाचा आहे. सध्याच्या सर्वेक्षणानुसार २१ नवीन प्राण्याच्या जातीचा शोध लागलेला दिसून येतो, या व्यतिरिक्त ५०० नवीन जाती वनस्पती व प्राण्याच्या आहे. महाराष्ट्रात १७ वन्यजीव अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्याने आहेत. त्यात फुलांच्या व वनस्पतीच्या असंख्य जाती आहेत. राष्ट्रीय उद्यानाचे एकूण क्षेत्रफळ १२७६.०५५ चौ.कि.मी. असून अभयारण्याचे क्षेत्रफळ



७७१८.९७८ चौ.कि.मी. आहे. महाराष्ट्रातील अभयारण्ये व राष्ट्रीय उद्यानांचे एकूण क्षेत्रफळ ८९९५.०३३ चौ.कि.मी. आहे

महाराष्ट्रातील प्रादेशिक विभागानुसार वनक्षेत्र :-

विदर्भात २०११-१२ नुसार सर्वात जास्त वनक्षेत्र ३३१९८ चौ.कि.मी. आहे. महाराष्ट्राच्या एकूण वनक्षेत्राशी विदर्भाची वन टक्केवारी ५४.११ आहे. तर महाराष्ट्राच्या भौगोलिक क्षेत्राशी याचे प्रमाण १०.७९ टक्के आहे मराठवाड्यात वनक्षेत्र सर्वात कमी असून ते २८८३ चौ.कि.मी. आहे. महाराष्ट्राच्या एकूण वनक्षेत्राशी मराठवाडा वन टक्केवारी फक्त ४.७ आहे तर महाराष्ट्राच्या भौगोलिक क्षेत्राशी याचे प्रमाण फक्त ०.९४ टक्के आहे पश्चिम विभागात या भागाचे वनक्षेत्र प्रशासकीय विभागानुसार सर्वात जास्त वनक्षेत्र नागपूर विभागात २७५५९ चौ. कि. मी. आहे. तर सर्वात कमी वनक्षेत्र औरंगाबाद विभागात २९१३ चौ. कि. मी. आहे. नाशिक, अमरावती, पुणे विभागात अनुक्रमे ११८२१, ९७२२, ६२३७ चौ.कि.मी वनक्षेत्र आहे. जिल्ह्याचा विचार करता राज्यात सर्वात जास्त वनक्षेत्र गडचिरोली जिल्ह्यात १३००० चौ. कि. मी. आहे.

महाराष्ट्रातील जिल्हानिहाय भौगोलिक कक्षानुसार घनदाट खुले क्षेत्र

जिल्हा	भौगोलिक क्षेत्र	घनदाट क्षेत्र	खुले क्षेत्र	एकूण	मॅग्नोक्		काटेरी
					घनदाट	खुले	
अहमदनगर	१७०४८	१९४	११९	३१३	३७९
अकोला	५३९०	२०४	१५७	३६१	३९
अमरावती	१२२१०	२१९३	९४४	३१३७	१३६
औरंगाबाद	१०१०७	१४८	३४१	४८९	३७१
भंडारा	३५८८	६८६	२४१	९२७	२९
बोड	१०६९३	२०६	५५	२६१	३८९
मुंबई शहर	१५७	००	०१	०२	००	०१	००
मुंबई	४४६	५३	२९	८२	१५	११	०३
बुलढाणा	९६६१	२३३	३८६	६१९	७७
चंद्रपूर	११४४३	२७५५	११९२	३९४७	८४
धुळे	७१८९	९६	३९७	४९३	१५१
गडचिरोली	१४४१२	७८५२	२२०४	१००५६	५४
गोंदिया	५७३३	१६३६	५३८	२१७४	४३
हिंगोली	४६८६	४८	६९	११७	७४
जळगाव	११७६५	४५१	७९१	१२४२	१०६
जालना	७७१८	८५	१७	१०२	६०
रायगड	७१५२	१२१४	१०७४	२२८८	३१	०३	३७५
कोल्हापूर	७६८५	११४५	६६९	१८१४	१३१

आधार - (Maharashtra Forest Department, Government of Maharashtra)

प्रस्तुत शोध निबंधात वरिल सारणीचा अभ्यास करतांना महाराष्ट्रात सर्वात जास्त भौगोलिक क्षेत्राचे प्रमाण अहमदनगर जिल्ह्याचे असून घनदाट वन व खुले वनाचे प्रमाण कमी आहे पण गडचिरोली जिल्ह्याचे भौगोलिक क्षेत्र १४४१२ चौ.कि.मी असून घनदाट व खुले वनाचे प्रमाण १००५६ चौ.कि.मी. आहे. त्याखालोखाल महाराष्ट्र राज्यात चंद्रपूर जिल्ह्यात



वनाखालील क्षेत्र ३९४७ चौ.कि.मी आहे या व्यतिरिक्त काटेरी खुरटी वनस्पती अहमदनगर रायगड जिल्ह्यात दिसून येते.

महाराष्ट्र राज्य भौगोलिक वनक्षेत्रानुसार वनाचे प्रकार



आधार — (Maharashtra Forest Department, Government of Maharashtra)

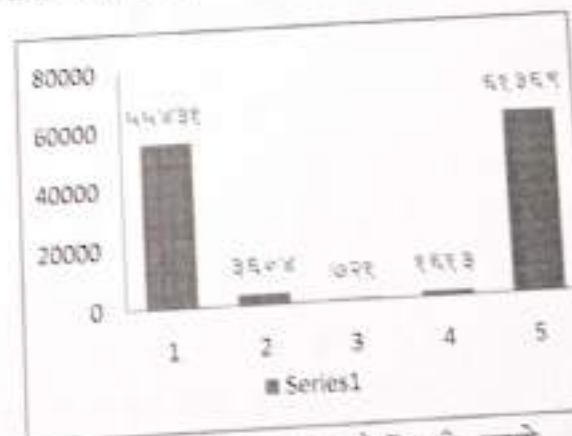
महाराष्ट्र राज्यातील वनक्षेत्रात कमालीची घट :-

राज्यातील वनक्षेत्र सातत्याने कमी होत आहे. गेल्या तीन वर्षात राज्यातील ६३३ चौ. कि. मी. इतके वनक्षेत्र कमी झाले वनखाते व Forest Department, Corporation of Maharashtra यांच्या निर्देशनास आले आहे.

आर्थिक अहवाल २०१७ आणि २०१८ नुसार राज्यातील एकुण वनक्षेत्र ६१३६९ चौ. कि. मी. इतके आहे हे क्षेत्र राज्याच्या एकुण क्षेत्रफळाच्या १९.९ टक्के इतके भरते.

वनविभागांतर्गत क्षेत्र

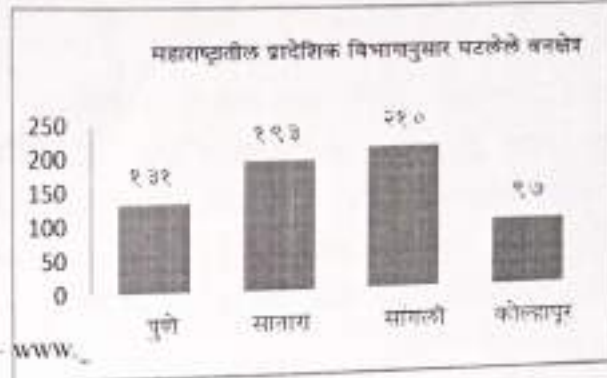
१.	वनखात्यांतर्गत	५५४३१ चौ.कि.मी.
२.	फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र	३६०४ चौ.कि.मी.
३.	खाजगी वने	७२१ चौ.कि.मी.
४.	महसुल खात्याच्या अखत्यारीत	१६१३ चौ.कि.मी.
	एकूण	६१३६९ चौ.कि.मी.



सन २००९-१० व २०१७-१८ च्या आर्थिक अहवालानुसार राज्यातील ५८१ चौ.कि.मी. इतके जंगलक्षेत्र कमी झाले. इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट २०११ (केंद्रसरकारच्या अहवाल) या वर्षी एकुण वनक्षेत्र ६०९४५ चौ.कि.मी. होते तर १९८४-८५ मध्ये जंगलाखालील क्षेत्र ६२९७१ चौ. कि.मी. होते. तीन दशकात राज्यातील १६०२ चौ.कि.मी. इतके जंगलक्षेत्र कमी झाले. १९८५ नुसार एकुण क्षेत्रफळाच्या ३३ टक्के क्षेत्र वनाखाली असणे आवश्यक आहे पण आता मात्र कमी झाले आहे.

महाराष्ट्रातील प्रादेशिक विभागानुसार घटलेले वनक्षेत्र

१.	पुणे	१३१ चौ.कि.मी.
२.	सतारा	१९३ चौ.कि.मी.
३.	सांगली	२१० चौ.कि.मी.
४.	कोल्हापूर	९७ चौ.कि.मी.



(स्रोत - WWW_)

महाराष्ट्र राज्य वनधोरण - २००८ कार्यप्रणाली

महाराष्ट्रराज्य वन धोरणांतर्गत राज्यातील ३३ टक्के भौगोलिक क्षेत्र वृक्षांच्या व्याप्तीखाली आणण्याचा प्रयत्न राज्य शासनातर्फे केला जाईल. जे राष्ट्रीय वन धोरण १९८८ च्या उद्दीष्टानुसार असेल ३३ टक्के वृक्ष व्याप्तीचे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी जिल्हावार योजना बनविल्या जातील.

१. वन आणि वनोत्तर पडीक जमीनीवर तसेच क्षार व पाणी यामुळे दुष्प्रभावीत झालेल्या अनुत्पादक शेतजमिनी वृक्षाच्छादनाखाली आणल्या जातील.
२. रेल्वे, राज्य व राष्ट्रीय महामार्ग तसेच कालव्या लगतच्या जमिनी आणि राज्य सरकार किंवा खाजगी मालकीच्या वापरात नसलेल्या इत्यादी सर्व जमीनीवर वृक्षारोपण करण्यास उत्तेजन दिले जाईल.
३. शहरी व औद्योगिक क्षेत्रात निर्माण होणारे कार्बन शोषून घेण्यासाठी योग्य त्या वृक्षाचे 'हरीतपट्टे' निर्माण करून होणाऱ्या पर्यावरण प्रदूषणावर आळा घालण्यात येईल.
४. नैसर्गिक/मानवनिर्मित वनांचे संरक्षण व व्यवस्थापन करणे.
५. पाणलोट क्षेत्राचे व्यवस्थापन आणि मृदा संधारण करणे.
६. वन्यजीव आणि जैवविविधता संवर्धन करणे.
७. वनसंशोधन, वनविषयक प्रसिध्दी आणि विस्तार करणे.

निष्कर्ष :-

१. महाराष्ट्रातील वनक्षेत्रांतर्गत गुंगामाल राष्ट्रीय उद्यानाचे एकुल क्षेत्र ३६१.६७६ चौ. कि. मी. असून सर्वात कमी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे एकुल क्षेत्र ८६.९६ चौ.कि.मी आहे.
२. राष्ट्रीय उद्यानातील जैवविविधतेत प्रथम क्रमांक ताडोबा व भामरागड क्षेत्राचा लागतो.
३. संरक्षित व राखीव क्षेत्राबाहेरील वन्यजीव संरक्षण व व्यवस्थापन संदर्भात १०६५ वनस्पतीच्या जाती व ६४२ इतर जाती आढळतात.
४. पश्चिम घाट परिस्थितीकी जैवविविधतेत मुख्य असून सध्याच्या सर्वेनुसार २१ नवीन प्राण्यांच्या जातीचा व ५०० नवीन वनस्पती व प्राण्यांच्या जाती आहेत.



५. महाराष्ट्रातील प्रादेशिक विभागानुसार विदर्भात २०११-१२ नुसार ३३१९८ चौ.कि.मी. वनक्षेत्र असून एकुण वनक्षेत्राच्या टक्केवारीत ५४.११ आहे सर्वात जास्त वनक्षेत्र औरंगाबाद विभागात २९१३ चौ.कि. मी आहे.
६. राज्यातील वनक्षेत्रात कमालीची घट देखिल दिसून येत आहे. आर्थिक अहवालानुसार २००९-२०१०च्या तुलनेत २०१७-१८ मध्ये ५८१ चौ.कि. मी क्षेत्र कमी झाले तसेच इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट केंद्रसरकारचा अहवालानुसार १९८४-८५ मध्ये जंगलाखालील क्षेत्र ६२९७५ चौ.कि.मी. होते सन २०११ मध्ये एकुण वनक्षेत्र ६०९४५ चौ.कि.मी. राहिले
७. गेल्या तीन दशकात राज्यातील १६०२ चौ.कि.मी वनक्षेत्र कमी झाले आहे.

उपाययोजना :-

- महाराष्ट्र राज्याच्या वनधोरणाच्या उद्दिष्टाच्या आधारावर खालील उपाययोजना करण्यात याव्यात
१. नैसर्गिक आणि मानव निर्मित वनांचे पुरेशा शास्त्रशुद्ध व्यवस्थापन नविन तंत्रज्ञानाचा वापर करून करण्यात यावे.
 २. सर्व पडीक निष्कृष्ट आणि अनुत्पादक जमीनीचे जल व मृदा संधारण होण्यासाठी पाणलोट क्षेत्र निहाय पुनर्वनीकरण करण्यात यावे.
 ३. वनजमिनीची व वनांतील वृक्षांची उत्पादन क्षमता वाढविण्यात यावी.
 ४. ग्रामीण क्षेत्रातील गरीबांची आणि आदिवासींच्या जळावू लाकडाबाबत, चान्याबाबत असलेल्या या मुलभूत गरजा भागविण्यासाठी या वनोपजांच्या मागणी आणि पुरवठ्यामधील तुट कमी करण्यात यावी.
 ५. जिल्ह्याच्या ठिकाणी दहा हेक्टर क्षेत्रात स्मृती वनांची निर्मिती करण्यात यावी.
 ६. जल व मृदा संधारण कामांद्वारे जलाशयाच्या पाणलोट क्षेत्राची होणारी जमिनीची धुप थांबविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावे.

संदर्भ साहित्य :-

१. सवदी, ए. बी. (२०१४) : महाराष्ट्राचा भूगोल.
२. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (मध्यक्षेत्र) २००८ : जिला संसाधन मानचित्र.
३. महाराष्ट्र शासन, महसून व वन विभाग (२००८) : महाराष्ट्र राज्याचे वनधोरण.
४. डॉ. मोरे, दि. मा. 'सिंचन साधने' : महाराष्ट्र सिंचन सहयोग.
५. www.maharashtra.madash.gov.in

Impact Factor - 6.625

ISSN - 2348-7143

INTERNATIONAL RESEARCH FELLOWS ASSOCIATION'S

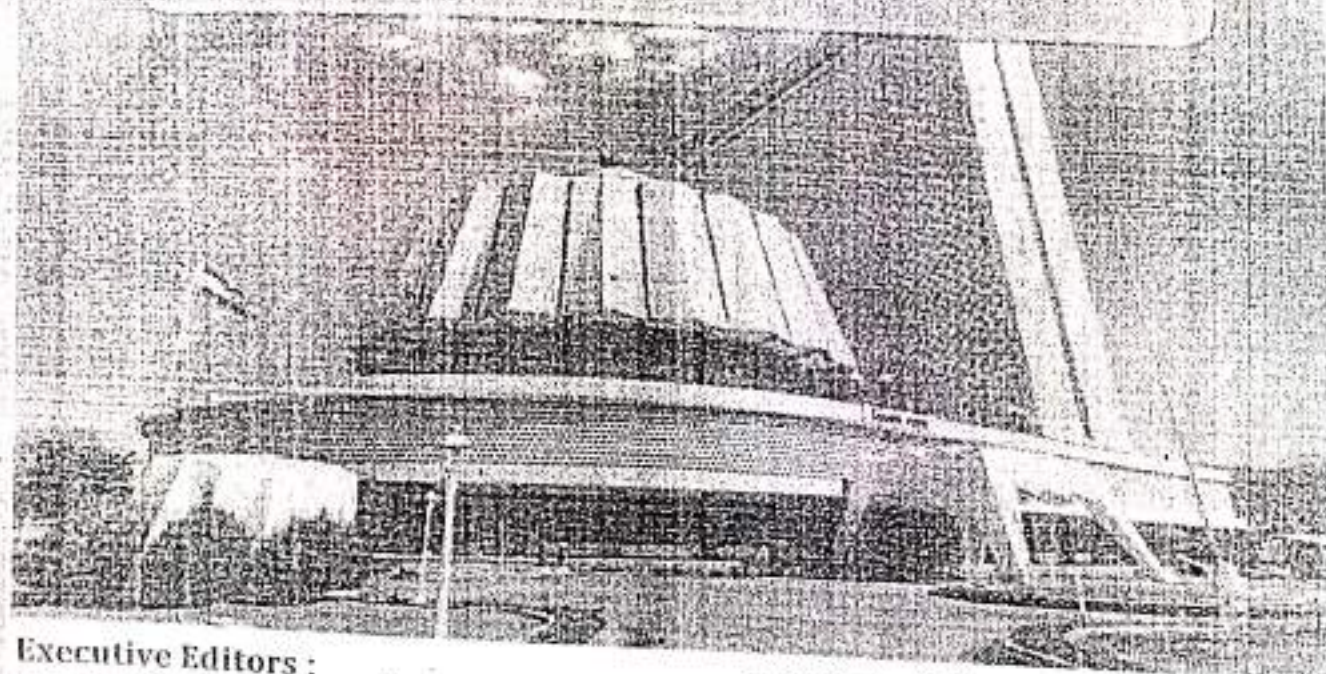
RESEARCH JOURNEY

International Multidisciplinary E-Research Journal

Peer Reviewed-Referred & Indexed Journal

February - 2020 Special Issue - 240 (C)

Analysis of Maharashtra State Legislative Assembly Election 2019



Executive Editors :

Dr. Sandip Tundurwar
(HoD, PG Dept. of Political Science)
Shri. Binzani City College, Nagpur

Dr. Vakil Shaikh
(HoD, Dept. of Political Science)
Taywade College, Mahadula-Koradi, Dist.-Nagpur

Chief Editor :
Dr. Dhauraj T. Dhangar (Yeola)

Associate Editors :

Dr. Sanjay Nakade
(HoD, Dept. of Political Science)
Dnyanesh Mahavidyalaya, Nawargaur

Dr. Balasaheb Jogdand
(PG Dept. of Political Science)
Sitabai Arts & Commerce College, Akola

Dr. Amar Bondre
(Dept. of Political Science)
VMV Com. JMT Arts & JJP Sci. College, Nagpur

Dr. Dinkar Chaudhari
(HoD, Dept. of Political Science)
Arts & Commerce College, Dhule



This journal is indexed in
Scientific Journal Impact Factor (SJIF)
Cosmos Impact Factor (CIF)
Global Impact Factor (GIF)
International Impact Factor Services (IIFS)

For Details Visit To www.researchjourney.in

Impact Factor - 6.625

ISSN - 2348-7143

INTERNATIONAL RESEARCH FELLOWS ASSOCIATION'S

RESEARCH JOURNEY

International Multidisciplinary E-Research Journal

PEER REFREED & INDEXED JOURNAL

February -2020 Special Issue - 240 (C)

Analysis of Maharashtra State Legislative Assembly Election 2019

Executive Editors :

Dr. Sandip Tundurwar
(HoD, PG Dept. of Political Science)
Shri. Birzani City College, Nagpur

Dr. Vakil Shaikh
(HoD, Dept. of Political Science)
Taywade College, Mahadula-Koradi, Dist.-Nagpur

Chief Editor :
Dr. Dhanraj T. Dhangar (Yeola)

Associate Editors :

Dr. Sanjay Nakade
(HoD, Dept. of Political Science)
Dnyanesh Mahavidyalaya, Nawargaon
Dr. Balasaheb Jogdand
(PG Dept. of Political Science)
Sitabai Arts & Commerce College, Akola
Dr. Amar Bondre
(Dept. of Political Science)
VMV Com. JMT Arts & JJP Sci. College, Nagp
Dr. Dinkar Chaudhari
(HoD, Dept. of Political Science)
Arts & Commerce College, Bhisi

SWATIDHAN INTERNATIONAL PUBLICATIONS

For Details Visit To : www.researchjourney.net

© All rights reserved with the authors & publisher

Price : Rs. 800/-

Editorial Board**Chief Editor -**

Dr. Dhauraj T. Dhangar,

Assist. Prof. (Marathi)

SPH Mahila Mahavidyalaya,

Malegaon, Dist - Nashik [M.S.] INDIA

Executive Editors :

Prof. Tejesh Beldar, Nashikroad (English)

Dr. Gajanan Wankhede, Kinwat (Hindi)

Mrs. Bharati Sonawane-Nile, Bhusawal (Marathi)

Dr. Rajay Pawar, Goa (Konkani)

Co-Editors -

- ❖ Prof. Mohan S. - Dean faculty of Arts, Delhi University, Delhi, India
- ❖ Prof. Milena Brotaeva - Head, Classical East Department, Sofia University, Sofia, Bulgaria
- ❖ Dr. R. S. Sarraju - Center for Translation Studies, University of Hyderabad, Hyderabad, India
- ❖ Mr. Tufail Ahmed Shaikh - King Abdul Aziz City for Science & Technology, Riyadh, Saudi Arabia
- ❖ Dr. Anil Dongre - Head, Deptt. of Management, North Maharashtra University, Jalgaon [M.S.] India
- ❖ Dr. Shailendra Lende - R.T.M. Nagpur University, Nagpur [M.S.] India
- ❖ Dr. Dilip Pawar - BoS Member (SPPU), Dept. of Marathi, KTHM College, Nashik. [M.S.] India
- ❖ Dr. R. R. Kazi - North Maharashtra University, Jalgaon [M.S.] India
- ❖ Prof. Vinay Madgaonkar - Dept. of Marathi, Goa University, Goa, India
- ❖ Prof. Sushant Naik - Dept. of Konkani, Govt. College, Kepe, Goa, India
- ❖ Dr. G. Hareesh - Associate Professor, CSIBER, Kolhapur [M.S.] India
- ❖ Dr. Munaf Shaikh - N. M. University, Jalgaon & Visiting Faculty M. J. C. Jalgaon [M.S.] India
- ❖ Dr. Sanjay Kamble - BoS Member Hindi (Ch.SU, Kolhapur), T.K. Kolekar College, Nexari [M.S.]
- ❖ Prof. Vijay Shirsath - Nanasahel Y. N. Chavhan College, Chalisgaon [M.S.] India
- ❖ Dr. P. K. Shewale - Vice Principal, Arts, Science, Commerce College, Harsul [M.S.] India
- ❖ Dr. Ganesh Patil - M.V.P.'s, SSSM, ASC College, Saikheda, Dist. Nashik [M.S.] India
- ❖ Dr. Hitesh Brijwasi - Librarian, K.A.K.P. Com. & Sci. College, Jalgaon [M.S.] India
- ❖ Dr. Sandip Mali - Sant Muktabai Arts & Commerce College, Muktainagar [M.S.] India
- ❖ Prof. Dipak Patil - S.S.V.P.S.'s Arts, Sci. and Com. College, Shindkheda [M.S.] India

Advisory Board -

- ❖ Dr. Marianna Kosic - Scientific-Cultural Institute, Mandala, Trieste, Italy.
- ❖ Dr. M.S. Pagare - Director, School of Languages Studies, North Maharashtra University, Jalgaon
- ❖ Dr. R. P. Singh - HoD, English & European Languages, University of Lucknow [U.P.] India
- ❖ Dr. S. M. Tadkodkar - Rtd. Professor & Head, Dept. of Marathi, Goa University, Goa, India.
- ❖ Dr. Pruthwiraj Taur - Chairman, BoS., Marathi, S.R.T. University, Nanded.
- ❖ Dr. N. V. Jayaraman - Director at SNS group of Technical Institutions, Coimbatore
- ❖ Dr. Bajarang Korde - Savitribai Phule Pune University Pune, [M.S.] India
- ❖ Dr. Leena Pandhare - Principal, NSPM's LBRD Arts & Commerce Mahila Mahavidyalaya, Nashik Road
- ❖ Dr. B. V. Game - Act. Principal, MGVS Arts and Commerce College, Yeola, Dist. Nashik.

Review Committee -

- ❖ Dr. J. S. More - BoS Member (SPPU), Dept. of Hindi, K.J. Somaiyya College, Kopergaon
- ❖ Dr. S. B. Bhambar, BoS Member Ch.SU, Kolhapur, T.K. Kolekar College, Nexari
- ❖ Dr. Uttam V. Nile - BoS Member (NMU, Jalgaon) P.S.G.V.P. Mandals ACS College, Shohada
- ❖ Dr. K.T. Khairnar - BoS Member (SPPU), Dept. of Commerce, L.V.H. College, Panchavati
- ❖ Dr. Vandana Chaudhari KCE's College of Education, Jalgaon
- ❖ Dr. Sayyed Zakir Ali, HoD, Urdu & Arabic Languages, H. J. Thim College, Jalgaon
- ❖ Dr. Sanjay Dhondare - Dept. of Hindi, Abhay Womens College, Dhule
- ❖ Dr. Amol Katgaonkar - M.V.P.S.'s G.M.D. Arts, B.W. Commerce & Science College, Simar.

Published by -

© Mrs. Swati Dhauraj Sonawane, Director, Swatidhan International Publication, Yeola, Nashik
 Email : swatidhanrajs@gmail.com Website : www.researchjourney.net Mobile : 9665398258

अनुक्रमणिका

अ.क्र.	लेखाचे शीर्षक	लेखक/लेखिका	पृ. क्र.
1	महाराष्ट्राची १४ वी विधानसभा निवडणूक विश्लेषण	प्रा.चंद्रमणी थोवते	6
2	विविध राजकीय पक्षांची निवडणूकविषयक कामगिरी	डॉ.अजय बोरकर	10
3	महाराष्ट्र राज्य मासिक विधानसभा निवडणूक २०१९ मधील महिला नेतृत्वाचे अध्ययन	प्रा.सचिन धुर्वे	15
4	महाराष्ट्रातील सत्तारूढ : विधानसभा २०१९	डॉ.भूपेंद्र घरत	19
5	निवडणूक रणनीती आणि डावपेच	डॉ.विकास जूनगरी	23
6	निवडणूकीतील रणनीती आणि डावपेचाचे राजकारण	डॉ.विठ्ठल मंडुलवार	26
7	महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक विश्लेषण २०१९ :विदर्भाचे विशेष संदर्भात	डॉ.प्रमोद शंभरकर	30
8	भारतीय राजकारणात महिलांचा सहभाग	डॉ.बविता येवले	33
9	Performance of Women in Election	Dr.Ravi S.Dharpawar	39
10	Election Strategy and Tactics	Dr. Madhao D. kandangire	42

Our Editors have reviewed papers with experts' committee, and they have checked the papers on their level best to stop furtive literature. Except it, the respective authors of the papers are responsible for originality of the papers and intensive thoughts in the papers. Nobody can republish these papers without pre-permission of the publisher.

- Chief & Executive Editor

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक विश्लेषण 2019 : विदर्भाचे विशेष संदर्भात

डॉ. प्रमोद शंभरकर

राज्यशास्त्र विभाग, प्रमुख व संशोधक मार्गदर्शक

सरदार पटेल महाविद्यालय, चंद्रपूर

जि. चंद्रपूर

सारांश

विदर्भाच्या निकालाने सर्व एक्जिट पोल खोटे ठरविल्याचे दिसून आले. निवडणूकीपूर्वी वाटत नसले तरी शासनाविषयीच्या नाराजीचा सुर विदर्भात निकालाअंती दिसून आला. या निवडणूकीत राज्याचा विचार करता भाजपा 103, शिवसेना 56, काँग्रेस 50, राष्ट्रवादी 54, मनसे 01, वंचित 00, एमआयएम 02 आणि इतर पक्षांना 24 जागा प्राप्त झाल्या आहेत. 2014च्या निवडणूकीच्या तुलनेत भाजपा-सेनेची घसरण झाली आहे. तर या उलट काँग्रेस-राष्ट्रवादीला संजिवनी प्राप्त झाली आहे. विदर्भात भाजपाच्या गडाला हादरा बसला असून काँग्रेस राष्ट्रवादीने मुसंडी मारली आहे. भाजपा वाढविण्याच्या अनेक नेत्यांना घरी बसवून ज्या कार्यकर्त्यांनी पक्षासाठी सतरंज्या उचलल्या त्यांना बाजूला सारून काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना जवळ करण्याची वृत्ती भाजपाच्या अंगलट आली आहे. विदर्भात एकुण 82 जागांपैकी भाजपा 21, शिवसेना 04, काँग्रेस 15, राष्ट्रवादी 06 मनसे 00 तर इतर 04 जागा प्राप्त केल्या आहेत.

भाजपाने यावेळी प्रादेशिक विकासाच्या मुद्द्यांना बगल देवून मतदारांची नाराजी ओढवून घेतली. भाजपा, सेनेत मोठ्या प्रमाणात झालेली बंडखोरी युतीला नडली. आघाडीला त्यामानाने बंडाचा फटका कमी बसला. राष्ट्रवादीला कधी नव्हे एवढे यश यावेळी मिळाले. ऐन निवडणूकीच्या तोंडावर पवारांना त्यांचे स्वकीय सोडून गेले. त्यापायी मिळालेली सहानुभूती यावेळी राष्ट्रवादीच्या कामी आली. स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दा यावेळीही बाजूला पडला. वंचित आणि मनसे यांना यावेळीही मतदारांनी वंचितच ठेवले. याउलट अपक्षांचा आकडा वाढला अर्थात यात बंडखोरांनी हातभार लावला. या निवडणूकीत विदर्भात केवळ दोनच महिला (03 टक्के) निवडून आल्या. अनेक दिग्गज काही मंत्र्यांनाही पराभव पत्करावा लागला. यावेळी युती, आघाडीतील रूसवे फुगवे चव्हाट्यावर आले.

विधानसभा निवडणूकीचे विदर्भातील जिल्हावार विश्लेषण :

नागपूरचा बालेकिल्ला राखताना भाजपाची मोठी दमछाक झाली आहे. गेल्या वर्षी 12 पैकी 11 जागा जिंकणाऱ्या भाजपाला यावेळी हादरा बसला. मतदारांनी देवेद्र फडणविस यांना पाचपांचा विधानसभेत पोहोचविले खरे मात्र पक्षाची घसरण झाली आहे. नागपूर पश्चिम, नागपूर उत्तर, काटोल उमरेड रामटेक या पाच जागा भाजपाने गमाविल्या. शिवसेनेने जागा कायम राखत आपली प्रतिष्ठा राखली आहे. य काटोलमध्ये राष्ट्रवादीचे अनिल देशमुख यांनी एकहाती विजय पटकाविला तर रामटेकमध्ये शिवसेनेचे बंडखोर आशिष जयरवाल यांनी भाजपाचे पानिपत केले आहे. अमरावती जिल्ह्यामध्ये अपक्षांना कौल प्राप्त झाला आहे. जिल्ह्यातील आठ विधानसभा मतदार संघांतील भाजपाने एकमेव जागेवर विजय मिळविला. काँग्रेसने तिन जागा पटकाविल्या. शिवसेनेला खाते खोलता आले नाही. महाआघाडीतील अपक्षाने एक जागा जिंकली तर उर्वरीत तिन जागांवर अपक्षांनी बाजी मारली आहे. अश्याप्रकारे एकूण चार जागा घेवून अमरावती जिल्ह्याच्या विधानसभा मतदार संघात आपला प्रभाव पाडला आहे. राष्ट्रवादी महाआघाडीतील अपक्ष रवि राणा यांनी शिवसेनेने उमेदवार प्रिती बंड यांचा पराभव केला. या निवडणूकीत सुलभा खोडके, यशोमती ठाकूर यांनी

अडसाड वळवंत वानखेडे देवेंद्र भूयार बच्चू कडू राजकुमार पटेल यांना विजय प्राप्त झाला तर कृषी मंत्री रमेश मावरकर, अनिरुद्ध देशमुख, सुनिल देशमुख, राजेश वानखेडे, विरेंद्र जगताप, रमेश बुंदिले इत्यादी माजी मंत्री आणि माजी आमदारांचा पराभव झालेला आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात भाजपाने चांगली मुरांडी मारली असून आपल्या जुन्या पाचही जागा कायम ठेवल्या आहेत. एका जागेवर शिवसेना व एका जागेवर राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराने विजय मिळविला. मागील निवडणुकीतील यवतमाळ, राळेगाव, वणी, आर्णी, उमरखेड या पाचही जागी भाजपचे उमेदवार विजयी झाले भाजपाच्या दृष्टीने जुनीच स्थिती कायम राहिली. तर दिग्रसमध्ये शिवसेना तर पुसदमध्ये राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराला विजयाची संधी प्राप्त झाली. गोंदिया जिल्ह्यात भाजपाचे चांगलेच पाणिपत झाले असून एकुण चार जागांपैकी भाजपाच्या वाटयाला एकच जागा प्राप्त झाली आहे. तर उर्वरीत तीन जागांवर काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि अपक्ष उमेदवार विजयी झाले आहेत. या निकालाने भाजपाला जिल्ह्याच्या राजकारणामध्ये विचारमंथन करावयाला लागले आहेत. गोंदिया विधानसभा मतदार संघातून अपक्ष उमेदवार विनोद अग्रवाल यांनी भाजपाचे गोपालदास अग्रवाल यांचा 20666 मतांनी पराभव करून अपक्ष म्हणून निवडून येण्याचा इतिहास रचला आहे. तर अर्जुनी मोरगाव मतदार संघातून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मनोहर चंद्रिकापूरे यांनी भाजपाचे राजकुमार बडोले यांचा 718 मतांनी पराभव करीत त्यांची विजयाची हॅट्रिक रोखली आहे. बर्धा जिल्ह्यात 03 जागांवर कमल फुलले असून देवळीत पाचव्यांदा काँग्रेसचे रणजीत कांबळे विजयी झालेत. आर्वी मध्ये काँग्रेसचे अमर काळे यांना 12000 मतांनी पराभूत व्हावे लागले. तर हिंगणघाट मतदार संघात भाजपाचे आमदार समिर कुणावत 50000 च्या वर मतांनी विजयी झालेले आहेत. सदर मतदार संघात काँग्रेसला पाहिजे त्या प्रमाणामध्ये संजिवनी मिळाली नाही. मात्र भाजपाने आपला गड राखण्यात यश मिळविले आहे.

भंडारा-यामध्ये महाआघाडीला दोन जागा प्राप्त झाल्या असून मंत्री फुके यांना पराभव पत्करावा लागला. तर भंडारा मतदार संघात अपक्ष उमेदवार नरेंद्र भोंडेकर यांनी विजय संपादित करून इतिहास रचला आहे. डॉ. परिणय फुके यांना काँग्रेसचे नाना पटोले यांनी शेवटच्या टप्प्यात आघाडी घेवून विजय प्राप्त केला आहे. भाजपाच्या ताब्यातील तिनही जागांवर ताबा मिळविण्यात महाआघाडी आणि अपक्षाला यश प्राप्त झाले आहे. येथे मोठ्या प्रमाणात भाजपाची घसरण झाल्याचे दिसून येते. चंद्रपूर जिल्ह्यात काँग्रेसला अखेरीस आले असून भाजपाला फटका बसला आहे. भाजपा नेते सुधीर मुनगंटीवार यांच्यावर जनतेने सलग सहाव्यांदा विश्वास टाकला असला तरी भाजपाने पूर्वीच्या चार जागांपैकी दोन जागा गमाविल्या आहेत. तर काँग्रेसने पूर्वीच्या एका जागेवरून तिन जागांवर मजल मारली आहे. येथे विजय वडेटीवार, सुभाष धोटे, प्रतिभा धानोरकर या तिन काँग्रेसच्या उमेदवारांना विजय प्राप्त झाला असून भाजपा आणि काँग्रेसने नाकारलेले अपक्ष उमेदवार किशोर जोरगेवार विक्रमी मतांनी निवडून आले आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यात एकुण तिन जागांपैकी गडचिरोली आणि आरमोरी मतदार संघात भाजपाच्या विद्यमान आमदारांना मतदारांनी पसंती दर्शविली आहे. तर अहंरीच्या राजघराण्याचे वारसदार अंबरशिराव आत्राम यांचा त्यांच्याच घराण्यातील माजी राज्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते धर्मरावबाबू आत्राम यांनी पराभव केला आहे. भाजपाने गडचिरोली आणि आरमोरी मतदारसंघात आपले वर्चस्व कायम ठेवले आहे. पश्चिम वऱ्हाडात भाजप शिवसेना युतीला मतदारांनी कौल दिला असून अकोला वाशिम बुलढाणा जिल्ह्यातील पंधरा मतदारसंघात नाराज जागांवर भाजपा शिवसेना युतीने विजय मिळविला असून दोन जागांवर काँग्रेसचे उमेदवार निवडून आलेले आहेत. यापैकी भाजपाने नऊ जागांवर, शिवसेना 03, काँग्रेस दोन तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला एक जागा मिळाली आहे.

संक्षेप :

भाजपाचा निवडणूकीपूर्वीचा उत्साह अनाढी होता हे या निकालाने सिद्ध केले आहे. रामोरच्या व्यक्तीला गृहित धरल्यामुळे काय होते हे या निकालाने सप्रमाण सांगितले आहे. राज्यातील विधानसभा निवडणूकांचा विदर्भाच्या संदर्भात काहीना अपेक्षित तर बऱ्याच जणांना अनपेक्षित असा निकाल लागला आहे. विशेष म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेसला कधी नव्हे एवढे यश यावेळी मिळाले आहे. पवारांनी केलेले भर पावसातील भाषण आणि त्यांचे परिश्रम राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कामी आली आहे. भाजप सेनेत मोठ्या प्रमाणात झालेली बंडखोरी युतीला नडली त्यामानाने आघाडीला बंडाचा फटका बसला नाही. शरद पवारांनी विदर्भात सहा सभा घेतल्या त्यांना राज्यात मिळालेल्या सहानुभूतीचा फायदा उमेदवारांना होवून विदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसला चांगले यश मिळाले. नरेंद्र मोदी यांच्या अकाल्यातील सभेने भाजपच्या दोन उमेदवारांना तारले. मात्र त्यांच्या सभेने राज्यमंत्री परिणय फुके यांना यश प्राप्त होवू शकले नाही. राहुल गांधी यांनी वणी आणि आर्वी येथे सभा घेतल्या पंचड गर्दी झाली मात्र त्याचे रूपांतर काँग्रेसच्या विजयात झाले नाही. स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दा यावेळी बाजुलाच पडला. बंधित आणि मनसे यांना आपले खाते खोलता आले नाही. केवळ दोन महिला सदर निवडणूकीमध्ये निवडून आल्या आहेत. भाजपाने यावेळी प्रादेशिक विकासाच्या मुद्द्यांना बगल देवून आपल्या पदरी अपयश पाडून घेतले. विदर्भात बंडखोरीमुळे भाजपाच्या पंधरा जागा कमी झाल्या.

संदर्भसूची:

1. संपादकिय लेख : दै. लोकमत, नागपूर
25 ऑक्टोबर 2019 पृ. क्र. 4
2. दै. लोकमत, नागपूर : 25 ऑक्टोबर 2019, मुखपृष्ठ
3. स. ज. लोटे : भारतीय शासन आणि राजकारण
पिंपळपूर आणि पब्लिशर्स प्र. आ. जून 2003
4. दिलीप तिखीले : संघाच्या मुख्यालयात भाजपाला फटका
दै. लोकमत, नागपूर
25 ऑक्टोबर 2019 पृ. क्र. 2
5. दै. लोकमत, नागपूर : 25 ऑक्टोबर 2019 पृ. क्र. 3
6. संपादकिय लेख : दै. लोकसत्ता नागपूर
25 ऑक्टोबर 2019
7. प्रा. पळशीकर : स्वतंत्र भारतातील राजकीय प्रवाह
प्रा. देवळणकर, शैलेंद्र
य.च. मुक्त विद्यापीठ, नाशिक जून 2009
8. डॉ. दाते, डॉ. मोरखंडीकर : राजकीय पक्ष आणि निवडणूक व्यवस्था
प्रा. क्षिरसागर
य.च. मुक्त विद्यापीठ, नाशिक जून 2009

सुचविनात व तो म्हणजे श्रमाची बचत करणाऱ्या आधुनिक यंत्रणेचा विशेष करणे करून अशा यंत्राचा वापर केल्यामुळे बेकारीत वाढ होऊन त्याचा परिणाम तो देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होतो असे त्यांना वाटायचे. गांधीजींच्या आर्थिक विचारांमधील गांधी महत्त्वी व किमान गरजा हे आर्थिक विकासाचे महत्त्वाने सूत्र आहे. यात विशेषतः महत्त्वाचे स्वीकार करून हिंसक मार्गाचा अवलंब न करता भांडवलशाही मुधारणेबाबत केलेल्या सुचनांचाही परामर्श घेणे येथे अगत्याचे ठरते. एकदरीत भारताच्या सर्व समाजातील लोकांनी गांधींच्या तत्वांचा स्वीकार करून ते अंमलात आणल्यास देशाच्या आर्थिक समस्यांची सोडवणूक करता येऊ शकते हे नक्की.

निष्कर्ष :-

गं. गांधींनी स्वतः, काल व संबंधीत परिस्थितीला अनुसरून आपल्या सर्वसमावेशक व सर्वस्पर्शी विचारांची मांडणी केलेली आहे. त्याचा प्रस्तुत विचारांचा सर्वांनी समर्थन केल्याशिवाय याचाही इतहास न करीत नाहीत. मात्र परीपदी होणाऱ्या नीतीमत्तेचा पक्ष, अमानुषतेचे दर्शन, गरीब व श्रीमंत यांच्यात वाढत चाललेली दरी, समाजविघातक कृत्य व त्याला लागलेले हिंसेचे गालबोट इ. बाबी घटना व प्रसंग एक दिशाहीन व विनाशाकडे वाटचाल करणाऱ्या समाजाचे चित्र रेखाटतात. तेव्हा अशा दिशाहीन व भरकटलेल्या समाजाला दिशा दाखवून संतुलित व समतोल विकासाकडे अग्रेसर करण्यासाठी प्रवृत्त करणाऱ्या गांधी विचारांची उपयुक्तता समजून घेणे आज काळाची गरज ठरते.

आज जगात वेगवेगळ्या क्षेत्रात नव-नवे शोध लागून जगातील विविध देशात प्रगती करीता स्पर्धेची चुरस लागलेली दिसते. मात्र ही प्रगती संकट व समस्यांनाही जन्म देतांना दिसते. एकीकडे नव्या तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने व रासायनिक खतांचा वापर करून उत्पादनात वाढ झालेली दिसते तर दुसरीकडे पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष होऊन त्याचा न्यास होत असल्याचे लक्षात येते. एकीकडे प्रत्येक क्षेत्रात आज स्त्रियांची सहभागीता दिसते तर दुसरीकडे तिच्यावर होणाऱ्या अत्याचारातही वाढ झाल्याचे निर्देशनास येते. एकीकडे औद्योगीकरणामुळे विकास होत असतांना दुसरीकडे मात्र बेकारी व दारीदर्यानेही प्रश्न निर्माण झालेले आहे आणि म्हणूनच सद्यास्थितीत गांधींनी प्रस्तुत केलेले विचार व त्या विचारांची प्रासंगिकता हे लक्षवेधक ठरते.

संदर्भ सूची :-

- जोशी श्रीपाद, महात्मा गांधी जीवन आणि शिकवण
- गांधी मो. क. सत्याचे प्रयोग, अनुवाद सिताराम पुरुषोत्तम पटवर्धन, नवजीवन प्रकाशन मंदीर, अहमदाबाद
- फाडिया बी. एल. राजनिती विज्ञान, प्रतियोग्यता साहित्य सिरीज
- देवगावकर श. गो. राजकीय विचारवंत, श्री माईनाथ प्रकाशन, नागपूर
- गांधी मो. क. मंगल प्रभात, अनुवादक अणा पटवर्धन, धरधाम प्रकाशन, धवना



OUR HERITAGE

ISSN: 0474-9030 Vol-68, Special Issue-23

National Conference on "Academic Libraries in E-learning Environment: Role and Prospect"

Organized by: Learning Resource Centre, Jeevan Vikas
Mahavidyalaya, Devgram, Narkhed, Nagpur, Maharashtra
Sponsored by: ICSSR and Held on 29-30 January 2020.



Need For E-Resources Management In Academic Libraries

Dr. Sanjay S. Bhutamwar

Librarian

Sardar Patel Mahavidyalaya,
Ganj Ward, Chandrapur

Abstract

Innovations have always been of interest to libraries both for the potential of increasing the quality of service and for improving the effectiveness of operations. Many Library resources are now available electronically and can be accessed via the web. You can get the information you want when you need it all the time.

Keywords: library automation, information retrieval, e-resources, library operations

Introduction

The development of computer and network technology is changing the education pattern and transforming the teaching and learning process from the traditional physical environment to the digital environment. The library should have a good number of resources for teaching, learning and research work. E-Resources offer creative possibilities for expanding access as well as changing learning, teaching and research work. E-books would never go out of print, and new editions can be easily created.

Library Automation

The main purpose of library automation is to improve the efficiency of the library and to provide optimum user services. To provide E-Resources to users, the automation of the library is most important. The automated library system is always ready to handle large volumes of documents and of providing effective and timely information services to faculty, researchers and students in



OUR HERITAGE

ISSN: 0474-9030 Vol-68, Special Issue-23

National Conference on "Academic Libraries in E-learning Environment: Role and Prospect"

Organized by: Learning Resource Centre, Jeevan Vikas
Mahavidyalaya, Devgram, Narkhed, Nagpur, Maharashtra
Sponsored by: ICSSR and Held on 29-30 January 2020.



achieving their main goals. The present Indian libraries are in the transitional stage from traditional to modern. The Indian Library has moved from palm leaves, manuscripts, etc. to CD-ROMs and digital books. Library Automation useful for:

- Faster communication and information retrieval, research results, innovations are communicated speedily to the end-users, Dissemination of information within less time, Email, data transfer, etc.
- Identification and loans of the print and non-print materials are easily tackled through bar code technologies.
- Library operations such as – circulation, acquisition, serial control, cataloging, documentation, information retrieval resources-sharing, library management, library budget, and finance control.
- Provide networking and liaison with the other libraries which help to the resources sharing among the library and information centers. Most of the integrated library automation systems are now providing a web-enabled online catalog [Web OPAC].

E-Resources

An E-Resource means electronic resources, which are available in electronic/digital form. The e-resources are very useful in academic libraries. This is the most important part related to e-resources. The quality has replaced the quantity of library collection during the present days. The quality has a direct link with the types of library collection as it depends upon the requirement of the users. An e-database is an organized collection of large information, of a particular subject or various subject areas. The information of an e-database can be searched and retrieved electronically. Contents include journal articles, newspaper articles, book reviews, and conference proceedings, etc. e-databases usually updated on a daily, weekly, monthly or quarterly, half-yearly or yearly basis. Full-text databases contain the whole content of an article such as citation information, text, illustrations, diagrams, charts, and tables. Bibliographic databases only contain citation information of an article, such as author name, journal title, publication date, and page numbers.

Types of E-Resources:

2.1 E-Books

The E-book is a book-length publication in digital form, consisting of text, images, or both, readable on computers or other electronic devices, although sometimes defined as "an electronic



OUR HERITAGE

ISSN: 0474-9030 Vol-68, Special Issue-23

National Conference on "Academic Libraries in E-learning Environment: Role and Prospect"

Organized by: Learning Resource Centre, Jeevan Vikas
Mahavidyalaya, Devgram, Narkhed, Nagpur, Maharashtra
Sponsored by: ICSSR and Held on 29-30 January 2020.



version of a printed book"(WIKIPAEDIA, 2008). An electronic book is a text and image-based publication in digital form produced on published by and readable on computers, other digital devices. E-books are usually read on dedicated hardware devices known as e-Readers or e-book devices. E-books are a very useful tool for academic teachers, students, etc. Many users now read the books on the Mobile phone by the use of e-book reader software. E-books are preferred by the users for their features like changeable font size, make citations, links to other relevant sites, searching, sending to other users, etc. E-books can be transferred from library catalog to user's e-book readers for a fixed loan period and after which it is automatically taken back.

2.2 E-Journals

An electronic journal provides research papers review articles, scholarly communication, issued periodically in electronic form by use automation. E-journals may be defined very broadly as any journals, magazine, e-zine, webzine, newsletters or any type of electronic serial publication, which is available over the internet. E-journals are the most useful tool for researchers. E-journals have an impact not only on libraries but on authors and publishers too. Hence, nowadays the majority of the users expect up-to-date and timely information from the library and information centers. Information from journals can easily, quickly, pin-pointedly and remotely be retrieved, provided the journals are available in electronic format. Academic and other special libraries cannot reject e-journals in their collections. Librarian and library staff have to provide access to the published knowledge to their users irrespective of the origin or e-resource.

Another type of online journal, whose full-text is available on the web for viewing and downloading free of charge, called open access articles. Open Access Articles means online access without access charges to individuals and libraries. A large number of important full-text articles are available free of charges on the personal or institutional websites of a few eminent personalities.

2.3 Consortia

Due to economic reason no library is in a position to acquire all such information in print or another form. Due to cost-effectiveness, librarians are coming together in the form of consortia for resource sharing. In India, CSIR Consortia, FORSA, IIM Library Consortia, INDEST Consortium, and UGC-info net e-journal consortium are some of the consortia serving the varies kinds of an institution in the country.



OUR HERITAGE

ISSN: 0474-9030 Vol-68, Special Issue-23

National Conference on "Academic Libraries in E-learning Environment: Role and Prospect"

Organized by: Learning Resource Centre, Jeevan Vikas
Mahavidyalaya, Devgram, Narkhed, Nagpur, Maharashtra
Sponsored by: ICSSR and Held on 29-30 January 2020.



2.4 E-Reference Sources

Now various vendors and publishers are providing various reference sources in electronic form through their databases and web sites such as dictionaries yearbook, encyclopedia' sets. Some of them are dictionaries online (WWW.dictionaries.com, www.dic.leo.org); yearbooks online (www.uja.org); directories online (www.people.yahoo.com). Etc Wikipedia's a new form of reference source which does not have its printed counterparts. Lots of information are available in Wikipedia and the most interesting thing is that new information can be added by the user and the information available can also be altered.

2.5 E-Thesis and Dissertation

E-Thesis and Dissertation is now a very useful tool to collect large data for a specific subject. This is an important service for users or mostly research scholars. It reduces the duplication of research works and assists in the selection of the research area to the users of the libraries. As these can be searched subject wise, it reduces the labor of the reference staff a lot.

1. SELECTION OF E-RESOURCES:

Selection is not a new term to librarian, staff, and users as they have been doing it since long back the libraries started acquiring printed material. However, libraries are now focusing to take e-resources information technology approaching the e-resources rather than printed material as technology developed.

The selection process should be done in relevant to the demands of the users, committee, focus group, user's recommendation, etc. Apart from this, it should take into consideration the following steps:

- 1) To identify library needs
- 2) To identify the content and scope of the e-resources
- 3) To evaluate the quality of that particular resource and search capabilities
- 4) To estimate the cost
- 5) To check either subscription-based or web-based when acquiring
- 6) To evaluate the systems and technical support



OUR HERITAGE

ISSN: 0474-9030 Vol-68, Special Issue-23

National Conference on "Academic Libraries in E-learning Environment: Role and Prospect"

Organized by: Learning Resource Centre, Jeevan Vikas
Mahavidyalaya, Devgram, Narkhed, Nagpur, Maharashtra
Sponsored by: ICSSR and Held on 29-30 January 2020.



- 7) To review licensing agreements
- 8) To evaluate application software and installation, updated sporadically or in the regular schedule, and
- 9) To check the facilities for educational support and training

5. Necessity and significance of library consortia based resource distribution

The word 'consortia' was originated from the Latin in the early 19th century in the sense of partnership. Advanced learner's Dictionary describes consortium as 'a group of people' countries. Companies etc. who are working together on a particular project. Information is a national resource and it is necessary for national development. Consortia can become an excellent way in the process of collection, digitizing organizing and making accessible electronic resources. The trend today is forming library consortia for the sharing of electronic resources. E-publishing has brought a revolution in journal publication; subscription access and journals online have led to a new and still evolving, form of co-operation among libraries and information centers.

6. Conclusion

The Library Information Centre is considered to be the backbone of any research organization as it provides its user the literature and information through electronic sources and services to carry out their academic activity. It took many years for digital libraries to reach the present state but the Librarian's goal of fully integrated online digital gateways. Although a library already has a particular journal in print form, but most often, for the sake of integrity and rendering effective value-added services to the users, the library is compelled to subscribe to the online access of the same journal for the same period. In the Indian scenario, the digitization programs are in their initial stages and much needs to be done to prepare a long term strategy to sustain these efforts and preserve the digital resources for future use.

References:

1. Ramaiah, C. (2013). Electronic resource management. Allied Publication.
2. Prasher R.G. (2003) "Indian Libraries in IT Environment", Medallion Press, Ludhiana, 2003, P.23-32.



OUR HERITAGE

ISSN: 0474-9030 Vol-68, Special Issue-23

National Conference on "Academic Libraries in E-learning Environment: Role and Prospect"

Organized by: Learning Resource Centre, Jeevan Vikas
Mahavidyalaya, Devgram, Narkhed, Nagpur, Maharashtra
Sponsored by: ICSSR and Held on 29-30 January 2020.



3. Kanamadi S.& Kumbar B.D.(2007) Building e-resources collection through consortia at management institutes in Mumbai: A survey" Information Studies, Vol. 13, Issue 3, P.139 to 162.
4. Krishnamurthy M (2007) "Consortia-based resource sharing and accessing e-journals" Information Studies, Volume : 13, Issue : 3, P 171to177.
5. Patkar Vivek,(2010) "Innovations in Library Practices: Prospects and Challenges" Information Studies, Volume : 16, Issue : 2, P 85to102.
6. Aruna chalam S.: India's march towards open access, science and development network. 2004.
7. Prabha Krishnan : Library automation: A prerequisite fire modern library Management in Government, Vol.33 No.3, Oct.-Dec. 2001.
8. Education (pp. 238-239). Kolhapur: ABS Publication. Materials in modern library system. IASLIC Bulletin 2004; 49 (2): P. 89-92.



**Nutan Vidyalaya Sevabhavi Education Society, Umri
Late Babasaheb Deshmukh Gorthekar Art's,
Commerce & Science Mahavidyalaya,
Umri, Dist. Nanded (M.S.)**



**(Affiliated to Swami Ramanand Teerth Marathwada University, Nanded)
(Recognition U/S 12(B), 2 (F) of the UGC Act 1956)**

Website : www.lbdgmu.in

Email: lbdgcollege@rediffmail.com

One day Interdisciplinary National Conference

On

"Rural Development : Issues & Challenges"

21st December 2019

Organized by

Internal Quality Assurance Cell

**Late Babasaheb Deshmukh Gorthekar Art's,
Commerce & Science Mahavidyalaya, Umri .**

Collaboration with

**Swami Ramanand Teerth Marathwada University,
Nanded (M.S)**

Chief Editor

Dr. Tukaram Vaijanathrao Powale

Co – Editor

Dr. Z. R. Pathan,

Dr. G. P. Yedle

Dr. D. D. Kolhekar,

Dr. V. V. Bhoyar

नूतन विद्यालय सेवाभावी शिक्षण संस्था, उमरी तर्फे
कै. बाबासाहेब देशमुख गोरटेकर कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय,
उमरी येथे आयोजित



‘ग्रामीण विकास : समस्या व आव्हाने’
या एकदिवसीय राष्ट्रीय परिषदेसाठी हार्दिक शुभेच्छा

नूतन विद्यालय सेवाभावी शिक्षण संस्था, उमरी
स्थापना : १९४३

:: संस्थापक अध्यक्ष ::

कै. आ. बालाजीराव उर्फ बाबासाहेब देशमुख गोरटेकर

कार्यकारी मंडळ

- अध्यक्ष : मा. श्री. गोविंदराव नारायणराव मुक्तावार (शिळरकर)
उपाध्यक्ष : मा. श्री. डॉ. एम. एम. महिंद्रकर
सचिव : मा. आ. श्री. श्रीनिवासराव बालाजीराव देशमुख गोरटेकर
सहसचिव : श्री. शिवाजीराव मारोतराव पाटील
कोषाध्यक्ष : श्री. गंगाधर संभाजी गोडगे
सदस्य : श्री. राजेश्वर किशनराव वंगलवार
श्री. नरसिंग गणपत चिटमलवार
श्री. शिवाजीराव श्रीधरराव देशमुख
श्री. प्रभाकर दिगांबर पाटील
श्री. धोंडजी माणिका पाटील
श्री. शंकरराव रामराव शिंदे
श्री. माधवराव गणपती सावंत
श्री. दत्तराम पिराजी लुटके
श्री. सदाशिवराव देवराव सावंत
श्री. मालू पिराजी कांबळे



Nutan Vidyalaya Sevabhavi Education Society, Umri



Late Babasaheb Deshmukh Gorthekar Art's,

Commerce & Science Mahavidyalaya, Umri, Dist. Nanded (M.S.)

(Affiliated to Swami Ramanand Teerth Marathwada University, Nanded)

(Recognition U/S 12(B), 2 (F) of the UGC Act 1956)

Website : www.lbdgmu.in

Email: lbdgcollege@rediffmail.com

One day Interdisciplinary National Conference On

"Rural Development : Issues & Challenges"

21st December 2019

Organized by

Internal Quality Assurance Cell

**Late Babasaheb Deshmukh Gorthekar Art's, Commerce &
Science Mahavidyalaya, Umri**

Collaboration with

**Swami Ramanand Teerth Marathwada University,
Nanded (M.S)**

Chief Editor

Dr. Tukaram Vaijanathrao Powale

Co – Editor

Dr. Z. R. Pathan,

Dr. G. P. Yedle,

Dr. D. D. Kolhekar,

Dr. V. V. Bhoyar.

Published by : Aarhat Publication & Aarhat Journal's

Mobile No : 9922444833 / 8355852142

21st December 2019

ISSN : 2278- 5655

Volume – VIII, Special Issue – XXIII

© Nutan Vidyalaya Sevabhavi Education Society, Umri
Late Babasaheb Deshmukh Gorthekar Art's,
Commerce & Science Mahavidyalaya, Umri, Dist. Nanded (M.S.)

Chief Editor : Dr. Tukaram Powale

Co-Editor : Dr. Z. R. Pathan, Dr. D. D. Kolhekar,
Dr. G. P. Yedle, Dr. V. V. Bhoyar.

EDITORS :

Disclaimer :

The views expressed herein are those of the authors. The editors, publishers and printers do not guarantee the correctness of facts, and do not accept any liability with respect to the matter published in the book. However editors and publishers can be informed about any error or omission for the sake of improvement. All rights reserved.

No part of the publication be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted any form or by any means electronic, mechanical, photocopying, recording and or otherwise without the prior written permission of the publisher and authors.

INDEX

Sr. No	Author Name	Paper Name	Page No
1	Dr. Prakash Ratanlal Rodiya	Sustainable Agriculture Development	01
2	Prof. Kirankumar J. Manure And Dr. Sunil M. Sakure	Role Of Women Sarpanches In Conservation Of Natural Resources, And Sustainable Development	08
3	Dr. S. R. Patode	Role Of Agriculture In Rural Development	15
4	Dr. Telke Sudhakar B.	Role Of Libraries In Rural Development	17
5	प्रा. डॉ. दामावले डी. एन.	मानवी हक्क आणि बालकामगार	20
6	Ganesh W. Patil	Emerging Issues In Rural Development Of Maharashtra	25
7	प्रा. डॉ. प्रणया महेंद्र पाटील	ग्रामीण विकासात महिला स्वयं – सहाय्यता गटांची भूमिका	31
8	प्रा. डॉ. चंद्रशेखर गितें	ग्रामीण विकासात कृषी अर्थव्यवस्थेचे योगदान	40
9	डॉ. लता मल्लिकार्जुन वडजे	भारतातील ग्रामीण भागाच्या विकासात वित्त पुरवठ्याची भूमिका	47
10	कल्पना आबाराव सिडाम	गोंड, पखान, जमातीच्या देवी देवतांचा अभ्यास	54
11	संतोष रघुनाथ कांबळे	भाषा, साहित्य आणि ग्रामीण जीवन	56
12	प्रा. डॉ. प्रकाश सदाशिव सूर्यवंशी	साठोत्तरी हिंदी उपन्यासां में चित्रित ग्राम्यजीवन	63
13	सीमा पठाण	पर्यावरण आणि ग्रामीण विकास	67
14	डॉ. एन. जी. भद्रे	ग्रामीण पर्यटन व ग्रामीण विकास	72
15	बुध्देवार सुभाष राजेन्ना	ग्रामीण विकासात शाश्वत शेतीचे महत्व	76
16	K. Saideepti	Self Help Groups And Rural Development	83
17	प्रा. डॉ. चंद्रकांत गजेवाड	ग्रामीण विकासात पायाभूत सुविधांचे महत्त्व	86

18	प्रा. डॉ. पांडुरंग पांचाळ	शाश्वत कृषी विकास एक चिंतन	91
19	Sanjay. M. Dalvi V. N. Kadam R. R. Rakh And And	Isolation And Screening Of Phosphate Solubilizing Bacteria (Psb) For Their Potential Use In Sustainable Agricultural	95
20	R. R. Rakh L. S. Raut S. M. Dalvi And And	For Sustainable Agriculture: Isolation And Screening of <i>Bacillus Spp.</i> For Microbiological Control of <i>Sclerotium Rolfsii</i> Sacc., A Stem Rot Pathogen Of Groundnut	107
21	प्रा. डॉ. प्रमोद सुर्यभान शंभरकर	सामाजिक आव्हाने आणि ग्रामीण विकास	118
22	प्रा. डॉ. बी. एम. कांबळे	ग्रामीण विकास आणि सामाजिक समस्या : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन	125
23	Mr. Mihir Umesh Inamdar	A Critical Analysis Of Domestic Violence In India	130
24	डॉ. महेश प्रल्हादराव गोमासे	पर्यावरण व ग्रामीण विकास	135
25	Dr. C. P. Karkare	Financial Inclusion : Pradhanmantri Janddhan Yojana	140
26	Dr. S. P. Gaikwad	Scope Of Rural Development Through Agrobusiness In India	146
27	डॉ. योगिता मा. पवार (लहानकर)	कृषी आधारित उद्योग आणि ग्रामीण विकास	148
28	डॉ. प्रिया ए.	वैश्वीकरण का समय और अनुपस्थित गाँव	152
29	सुदेश रानी	ग्रामीण पर्यटन : ग्रामीण भारत के समग्र विकास की सम्भावनाएँ	156
30	Ingle S. L.	Impact Of Water Pollutions On Godavari River In Maharashtra State	160
31	मुजावर जैनु हमिद व डॉ. अतुल कुमार पांडेय	हिंदी के आंचलिक उपन्यासों में अभिव्यक्त ग्रामीण जन-जीवन	162
32	श्री करडे महादेव बळीराम	सामाजिक समस्याएँ और ग्रामीण विकास	167
33	श्रीमती भाग्यश्री पांडुरंग पानढवळे	ग्रामीण पर्यटन आणि ग्रामीण विकास	174

34	डॉ. सुनील गुलाबसिंग जाधव	सूखता हुआ तालाब में : — जाति बहिष्कार एवं छूत-अछूत की समस्या ।	181
35	डॉ. मंगल नागोराव मारकड	भारत के ग्रामीण विकास में ग्रामीण वित्त का योगदान	187
36	डॉ. ए. एस. नलवडे	नवीन आर्थिक धोरण : भारताच्या ग्रामीण विकासाचा प्रश्न आणि उपाययोजना	194
37	डॉ. शिवाजी नागोराव भदरगे	ओमप्रकाश वाल्मीकि के कहानियों में श्रमिक ग्रामीण दलित महिलाओं का जीवन	199
38	प्रा. एस. व्ही. शिंदे	ग्रामीण समाज जीवन आणि संगीत	203
39	डॉ. बी. आर. भोसले	भारत की ग्रामीण संस्कृति और मुस्लीम सामाजिक आंदोलन	206
40	प्रा. डॉ. ज्ञानेश्वर गंगाधर गाडे	मैला आँचल — उपन्यास में कृषक जीवन	211

प्रा. डॉ. प्रमोद सुर्यभान शंभरकर
सहयोगी प्रा. राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख,
सरदार पटेल महाविद्यालय, चंद्रपुर

खेड्यांची वा ग्रामीण समाजाची महती प्रतीपादन करतांना मोठ्या अभिमानाने भारत हा खेड्यांचा देश आहे असे म्हटले जाते. इतकेच नव्हे तर एके काळी सोन्याचा धूर निघत असलेल्या भारत देशात खेडी ही स्वयंपूर्ण व स्वावलंबी होती असा इतिहासही सांगितला जातो. मात्र काळाच्या ओघात याच खेड्याकडे दुर्लक्ष होऊन खेडी ही विविध समस्यांचे केंद्रे झालीत. तेथील स्वयंपूर्ण व स्वाश्रयी जीवनाला तडा गेला. तेथील कुटीर व लघू उद्योग मोडकडीस आले. पुर्णता शेती क्षेत्रावर अवलंबून असणारे ग्रामीण जीवन हे कधी परकीय आक्रमणामुळे तर कधी नापीकी वा दुष्काळ पडल्यामुळे परावलंबी झाले. यासोबतच अगदी सुरुवातीपासूनच असणाऱ्या अंधश्रद्धा, जून्या चालीरीती सनातनी प्रथा, रूढी, परंपरा या सारख्या सामाजिक समस्यांनी उग्ररूप धारण केले.

पाश्चात्य शिक्षणाने प्रभावित झालेल्या येथील विशीष्ट वर्गाने तसेच समाज सुधारकांनी ग्रामीण समाजातील विविध समस्यांना वाचा फोडण्याचे कार्य केले. इथल्या अनिष्ट चालीरीती विरुद्ध त्यांनी बंड पुकारला व त्यात त्यांनी बहुतांश प्रमाणात यशही मिळविले. म. गांधींनी तर आपल्या विचार धारेचे केंद्र हे खेड्यालाच ठरविले. खेड्याची झालेली दुर्दशा, ग्रामीण जीवनाला आलेली अघोगती व समस्येचे माहेर घर म्हणून ओळखली जाणारी खेडी ही स्थिती बदलविण्यासाठी गांधींनी ग्रामीण समाजावर अधिका-धिक लक्ष केंद्रीत केले. याच उद्देशांनी त्यांनी ग्रामस्वराज्याची संकल्पना मांडली व ग्राम पुनर्रचनेचे महान कार्य हाती घेतले.

देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही इथल्या सरकारने ग्रामीण जीवनातील विविध समस्या सोडविण्याच्या दृष्टीने व तेथील लोकांना विविध सोयी सवलती उपलब्ध करून त्यांचे जीवनमान उंचावून एकंदरीत ग्रामीण विकासासाठी अगदी सुरुवातीपासूनच प्रयत्न चालविले. यात १९५२ मधील सामुदायिक विकास कार्यक्रमापासून तर केंद्र तथा विविध राज्यातील राज्य सरकारने नेमलेल्या विविध समित्या तसेच अभ्यास गट व त्या अनुषंगांनी झालेली १९९३ मधील ७३ वी घटनादुरुस्ती, यासोबतच मनरेगा, सन २०१०-११ मध्ये सुरू केलेली समृद्ध ग्राम योजना, तसेच आज विशेष उल्लेख करता येईल अशी पंडीत दीनदयाल उपाध्याय कौशल्य विकास योजना तसेच अनेक योजना व कार्यक्रम यांनी ग्रामीण विकासात सिंहाचा वाटा उचलला असतांनाही आपण ग्रामीण विकासाचे सर्वांगीण उद्दीष्ट गाठू शकलेले नाही हे नक्की.

राष्ट्र कोणतेही असो त्यात ग्रामीण समाज उल्लेखनिय कामगिरी बजावत असतो. अन्नधान्ये व इतर कच्चा माल यांचे उत्पादन ग्रामीण भागातच होत असते. या बाबतीतील शहरांची गरज ग्रामीण उत्पादनातूनच भागविली जाते. यासोबतच शहरातील उद्योगधंद्यांना श्रमीक पुरविण्याची जबाबदारीही सहसा ग्रामीण भागच पार पाडतात. राष्ट्राची नैसर्गिक साधनसंपत्तीही बहुतांश प्रमाणात ग्रामीण प्रदेशातच उपलब्ध होते आणि बहुसंख्य लोकांचा निवास वा वस्तीही ग्रामीण प्रदेशातच आढळते. सर्वत्र जगभर शहरांचा विकास होत असतांना जागतिक लोकसंख्येपैकी ग्रामीण भागात राहणाऱ्यांचे प्रमाण १९५० मध्ये ७९ टक्के पेक्षा थोडे अधिकच होते. ते प्रमाण भारतात १९६१ मध्ये ८२ टक्के होते. म्हणजे ८२ टक्के लोक ग्रामीण भागात राहत होते. 'साहजिकच आर्थिक नियोजनाद्वारा राष्ट्रीय विकास साधण्यासाठी ग्रामीण विकास अत्यंत आवश्यक ठरतो. म्हणूनच ग्रामीण समस्यांचे स्वरूप निटपणे समाजावून घेऊन त्या सोडविण्याचे कसोशीने प्रयत्न करावे लागतात.

साधारणपणे ग्रामीण विकासाची दिशा ठरवितांना त्याच्या आर्थिक घटकांवर व मानकावर अधिक लक्ष वेधल्या जाते. यात कृषी विकासाचा संदर्भ सातत्याने जोडण्यात येत असतो. अर्थात या क्षेत्रामधील रोजगाराची उपलब्धता, दारिद्र्य निर्मुलन व लोकांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे या बाबी अपेक्षित असतात. ग्रामीण विकासाच्या संदर्भात आर्थिक दृष्टीकोनातून बरील सर्व बाबीची उपलब्धता होणे हे गरजेचे असले तरी ग्रामीण विकासाच्या संदर्भात सामाजिक परिस्थिती व सामाजीक समस्या आणि एकंदरीतच ग्रामीण विकासाला प्रभावित करणारी किंबहुना त्यात अळथडा बणू पाहणारी सामाजिक आव्हाने यावर प्रकाश टाकणे महत्त्वपूर्ण ठरते. कारण शासकिय तसेच अशासकीय स्तरावरून विविध योजनांच्या माध्यमातून आर्थिक व राजकीय क्षेत्रातील आव्हानांचा मुकाबला करणे वा त्यावर मात करणे काही 'प्रमाणात शक्य असले तरी अगोदरच भारतातील समाजात व विशेष म्हणजे ग्रामीण समाजात आपले मुळ घट्ट रोवणाऱ्या सामाजाजिक आव्हानांच्या संबधात ग्रामीण विकास अधिक प्रमाणात बाधित होत असतो.

भारतातील ग्रामीण समाज व या समाजाच्या विकासाला प्रभावीत करणारी सामाजिक आव्हाने याचा परमर्श पृढील मुद्द्यांच्या आधारे घेता येईल.

➤ अंधश्रद्धा व जुन्या चालीरीती :-

भारतीय ग्रामीण समाज हा विविध अंधश्रद्धेनी ग्रासलेला आहे. त्यात जुन्या चालीरीती फार पूर्वीपासूनच या समाजाचा एक भाग बनलेल्या आहेत. अंधश्रद्धा म्हणजे एखादी गोष्ट आंधळेपणाने स्वीकारणे होय. या अंधश्रद्धेचे प्रमाण ग्रामीण समाजात मोठ्या प्रमाणावर आहे. ग्रामीण समाजातील निरक्षर व्यक्ति वा कुटुंबच नाहीतर सुशिक्षित वर्ग सुद्धा या समस्येने बळी पडत आहेत. अगदी रोजची वर्तमानपत्रे बघीतली तरी त्यातील किमान ४ ते ६ बातम्या ह्या

अंधश्रद्धा वा त्या समस्ये संबधातील असतात. यात जादुटोना, बळी, गुप्तधन या यारख्या कुप्रथांचा समावेश असतो. त्यातच शिक्षणाचे प्रमाण कमी असल्यामुळे अशा समाजाकडून प्रत्येक गोष्ट ही विवेकाच्या कसोटीवर तपासण्याचा प्रयत्न होत नाही. त्यामुळे संबंधीत घटनेत एकटा व्यक्तिच प्रभावित होत नसतो. तर त्याचे संपूर्ण कुटुंब व समाजालाही अपरिमीत हानी पोहचत असते.

जुन्या चालीरीती व रूढी याविषयीसुद्धा तेच सांगता येईल यात कालबाह्य अशा विचारांचे सक्रमण हे एका पीढीकडून दुसऱ्या पीढीकडे सहजरित्या होत असते. लोक हे जुन्या विचारांना चिकटुण वा खीळून बसलेले असतात. अशा लोकांमध्ये कालबाह्य विचार आत्मसात करणारे तसेच रूढी व परंपराना धरून चालणाऱ्या समाजाकडून बदलांची अपेक्षा करणे हे व्यर्थ ठरते. म्हणूनच अशा जुन्या चालीरीती व अंधश्रद्धा ह्या ग्रामीण विकासात प्रमुख आव्हाने ठरतात. या परिस्थितीत सुधाराकांनाही हाल अपेष्टा सहन कराव्या लागतात व बहुतेकदा यात त्यांचा बळीही जातो. याचे जीवंत उदाहरण म्हणजे नरेंद्र दाभोळकर, गोविंद पाणसरे यांची अमानूपपणे करण्यात आलेली हत्या हे होय.

ग्रामीण विकासात या समस्या आजही प्रमुख आव्हाने म्हणून समोर येत आहेत अंधश्रद्धेमुळे गरीब आणि दुबळे लोक हे गरीब. — दुबळेच राहतात. त्यांना त्या असाह्य परिस्थितीतून वर उठायला काही वावच राहिलेला नसतो. यात अनेक कर्मकांड आणि आचार हे असे असतात की, त्यापायी मानसाचा कष्टाने मिळविलेल पैसा, त्याची मेहनत व वेळ यांचा अगाप अपव्यय होत असतो. त्यामध्ये समाजाचेही अपरिमीत असे नुकसान होते व त्यामुळे एकंदरीतच ग्रामीण विकासाचे प्रयत्न असफल ठरतात.

➤ जातीयवाद :-

आज देशाने विज्ञान व तंत्रज्ञान, दळण — वळण उदयोगधंद्याचा विकास व त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात झालेले व होत असलेले शहरीकरण हे एकीकडे विकासाचे सुचक असले तरी मात्र दुसरीकडे ग्रामीण समाजाला लागलेला एक कलक वा किड म्हणून जातीचा प्रामुख्याने विचार करता येईल. या जातीने आजही ग्रामीण समाजात आपले पाय घट्ट रोवलेले आहेत. या जातींना हजारो वर्षांची परंपरा लाभलेली आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात जातीप्रथांच्या प्रभावामुळे निर्माण झालेली बंधने झुगांरून देण्यासाठी अनेक आंदोलने झाली. जात — पात तोडण्याचेही आंदोलन झाले. व्यक्तिच्या सामाजिक जीवनातील आणि प्रामुख्याने सामाजिक संबंधांमधील जातीचा प्रभाव नष्ट करण्याच्या हेतूने अनेक समाजसुधारकांनी प्रयत्न केले. काहीणी या समाजकार्यासाठी आपले संपूर्ण आयुष्य खर्ची घातले. या सर्व प्रयत्नांमधून जाती प्रथेमध्ये काही महत्त्वपूर्ण असे बदल घडून आले असले तरी जातीचे समुच्च उच्चाटन मात्र झालेले नाही.

ग्रामीण समाजात जातीचे प्राबल्य मोठ्या प्रमाणात जाणवते. संविधानानुन मिळालेले मुलभूत अधिकार, शिक्षणाचा विस्तार व प्रसार, विकास कार्यक्रम, समाजसुधारकांचे प्रयत्न यामुळे व्यक्तिच्या सामाजिक जीवनाची रूपरेखा निश्चीत करण्यामधील जातीप्रथांचा प्रभाव कमी होण्यास मदत झाली असली तरी राजकीय समीकरण जुळवतांना जातीला झुकते माप दिले जाते. यातच भर म्हणजे जातीच्या आधारावरच आरक्षणाची मागणी आज जोर धरू लागली आहे. या प्रकारचे वातारण वा निर्माण झालेली स्थिती ही ग्रामीण विकासाच्या दृष्टीने निश्चीतच योग्य ठरत नाही. राजकारणामुळे जातीयवादाला खतपाणी घातले जाते. मतांच्या राजकारणासाठी जाती जातीमध्ये तेढ निर्माण करून त्याचा राजकीय फायदा घेण्याचे काम सध्या तेजीत चालू आहे. यासाठी सर्वात पोषक स्थिती म्हणून ग्रामीण भागाला लक्ष केले जाते.

व्यवसाय स्वातंत्र्याचा अभाव, विशेषाधिकार व अपात्र ठरविणे, श्रेष्ठ कनिष्ठतेच्या तत्वांची सोपान परंपरा, जन्माने निश्चित होणारे स्थान, विवाहावरील निर्बंध ही सर्व जातीची देण असून ग्रामीण भागात यांच्या पालणावर आजही कटाक्ष दिसून येते. यात भर म्हणजेच या सर्वांना खतपाणी मिळत असेल तर ते निश्चितच विकासाला बाधक ठरत, असते. म्हणूनच जात हा घटक ग्रामीण विकासाच्या प्रवासातील एक आव्हान बणू पाहत आहे.

स्त्रिविषयक नकारात्मक दृष्टीकोण :-

आज नागरीकरणामुळे स्त्रीचा कुटुंबातील दर्जा उंचावण्यास मदत झाली आहे. नागरी कुटुंबात कुटुंब प्रमुखाच्या एकाधिकारशाहीचा न्हास होत आहे. कुटुंबातील कामाच्या बाबतीत लिंगभेदावर आधारलेले कार्य विभाजन राहतात टिकू शकत नाही. नोकरी वा इतर कामधंद्यामुळे घराबाहेर असणाऱ्या पुरुषास कुटुंबाच्या दैनंदिन व्यवहाराकडे लक्ष देणे शक्य नसते. त्यामुळे घरातील व बाहेरील इतर कामे करण्याची जबाबदारी स्त्रीवर येऊन पडत असते. त्यामुळे स्त्रीयांचे स्थान उचावण्यास ही स्थिती पोषक ठरत असातांना मात्र ग्रामीण भागात याच्या विपरीत असलेली स्थिती पाहायला मिळते.

ग्रामीण समाजात आजही स्त्रीयांना गौण स्थान दिले जाते. शिक्षणाचा प्रसार व प्रचार झाले आहेत. ग्रामुळे स्त्रीयांच्या स्थितीत बदल घडून येत असला तरी त्या बदलापासून ग्रामीण भागातील ग्रामसमूदाय हा वंचितच राहीलेला दिसून येते. चुल व मुल या परिघाच्या बाहेर स्त्रीयांनी कुल ठेवलेला असला तरी कुटुंबातील महत्वपूर्ण निर्णय आजही पुरुष मंडळीच घेत असतात. सोबतच जातीच्या प्राबल्याचा आधार मिळत असल्यामुळे सामाजिक स्तरीकरणाची गतीही काहीणी दावलेली दिसून येते. त्यामुळे ग्रामीण भागातील स्त्रीयांना अनेकाधिक संकटांना तोंड द्यावे प्रथेमध्ये कमी येत नाही.

आज स्त्रीयांच्या न्याय हक्कविषयक अनेक संघटना, महिला आयोग कायद्यातील सुदी इ. चे पाठबळ असले तरी ग्रामीण स्त्रीयांत या विषयी पाहीजे त्या प्रमाणात जागृकता

झालेली दिसत नाही. समान कामासाठी आजही ग्रामीण भागात स्त्री-पुरुषांना असमान मोबदला दिला जातो. राजकीय क्षेत्रातील आरक्षणामुळे स्त्रियांचा सार्वजनिक क्षेत्रातील सहभाग वाढत असला तरी मात्र पडद्यामागुन कुणीतरी वेगळाच भूमिका साकारत असतो. अर्थात विशिष्ट पदावर स्त्री असली तरी त्यासंबंधातील निर्णय मात्र पुरुष मंडळीच घेत असतात. स्त्रिविषयक असणाऱ्या या नकारात्मकतेचा प्रत्यय आपल्याला ग्रामीण भागात सहज घेता येतो. वास्तविकपणे स्त्रिया ह्या जागतीक लोकसंख्येचा अर्धा भाग आहेत. स्त्रियांचा सार्वजनिक जीवनातील सहभाग वाढला की त्यातून सांस्कृतिक, आर्थिक समृद्धी अधिक वाढणार हे कोणीही नाकारू शकत नाही.

➤ बेरोजगारी :-

ग्रामीण विकासातील एक प्रमुख आणि महत्त्वपूर्ण आव्हान म्हणून बेरोजगारीचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल. ग्रामीण भागातील लोकांना रोजगाराची उपलब्धता करून देणारे क्षेत्र म्हणून शेती क्षेत्राकडे पाहिले जाते. मात्र या शेतीवर वर्षातील फक्त ४ ते ६ महिनेच रोजगाराची उपलब्धता होत असते. उर्वरित महिन्यात रोजगारासाठी तेथील लोकांना शहरांकडे धाव घ्यावी लागते अन्यथा खाली राहावे लागते. त्यातच शेती क्षेत्रात आज विविध तंत्रज्ञानाचा वापर होऊ लागल्यामुळे मनुष्यबळाची मागणी कमी होऊ लागलेली आहे. मनरेगा सारख्या सरकारी योजनांच्या माध्यमातून बेरोजगारी या समस्येवर मात करण्याचा प्रयत्न होत आहे मात्र तोही विविध कारणामुळे शाश्वत उपाय ठरत नाही. त्यामुळे बेरोजगारी या समस्येने आज ग्रामीण भागात एक विक्राळ रूप धारण केलेले दिसते.

शहरी बेरोजगारीसह ग्रामीण भागातील बेरोजगारी ही देशातील गंभीर समस्यांपैकी एक म्हणून संबोधली जाते. कारण यामुळे संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होतो. वैयक्तिक आणि त्याच्या कुटुंबाचे नुकसान होण्याव्यतिरीक्त त्याचा परिणाम कमी खरेदी वा गुंतवणुकीवर होऊन वस्तु व सेवांचा वापर कमी होऊन त्यामुळे वस्तुच्या उत्पादनाचा कमी वापर होऊन, कमी उत्पादनामुळे देशांच्या महसुलात कमी योगदान होते आणि याचा परिणाम शेवटी देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होत असतो.

आज तर बेरोजगारी या समस्येने देशात गंभीर रूप धारण केलेले आहे. विविध विभागातील मागीललेल्या माहितीच्या आधारे हे स्पष्ट झाले आहे. की, ४७ वर्षातील हा सर्वात मोठा बेरोजगारीचा वाढलेला दर आहे. याचा सर्वात मोठा फटका शहरातील उदयोगधंदे व तेथील काम करणाऱ्या कामगार वर्गावर झाला असला तरी हा कामगार वर्ग मुख्यत्वे ग्रामीण क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करणारा आहे. असा वर्ग जेव्हा परत आपल्या ग्रामीण भागाकडे वळतो. तेव्हा तेथील कुटुंब व्यवस्थेवर मोठ्या प्रमाणात ताण येत असतो व परीणामी त्यांच्या दारिद्र्यात वाढ होते. ही स्थिती दूर करण्यासाठी ग्रामीण भागातील या बेरोजगारीच्या समस्येवर

वदला स्वयंरोजगार, अल्पदराने कर्जाची सुवीधा शेती क्षेत्रामध्ये सिंचनाच्या सोयी या सारख्या वाढत दिव्घकालीन उपायांचा अमल करणे गरजेचे आहे. ग्रामीण बेरोजगारी दुर झाल्यावरच शहरांचा व विशिष्ट पर्यायाने देशाचा विकास साधता येईल हे नक्की.

विषयक ➤ पर्यावरणाचे संरक्षण :-

येतो. पृथ्वीवरील सर्व संजीवासाठी पर्यावरणाचे महत्व अवर्णनीय आहे. विशेषतः मानवी जीवन दीर्घायुषी, सुखकर, आनंदमय आणि सुरळित होण्यासाठी पर्यावरणीय संतुलनाची नितांत गरज आहे. आजच्या विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या अवकाश युगामध्ये प्रचंड प्रमाणात औद्योगिक, तांत्रिक विकास हाऊन पर्यावरणाच्या संतुलनाला धक्का पोहचला आहे. स्पर्धेच्या आणि उत्पादन वाढीच्या कसरतीमध्ये पर्यावरणाच्या अनेक समस्यांनी आकाळ विकाळ स्वरूप धारण केले आहे. अशा परिस्थितीत सजीवसृष्टी टिकवून ठेवण्यासाठी पर्यावरणाचे संरक्षण करणे अगत्याचे होऊन गार क्षेत्र बसते.

महिनेच शहरी भागाच्या तूलनेने ग्रामीण भागात पर्यावरणाच्या न्हासाचे प्रमाण कमी असले तरी शहरांकडे या प्रमाणाकडे निश्चीतच दुर्लक्ष करता येणार नाही. ग्रामीण भागात आजही इंधन, घरबांधणी, लकडी वस्तूची निर्मिती इ. अशा विविध कामांसाठी मोठ्याप्रमाणात वृक्षतोड केली जाते. याचा सारख्या सर्व परिणाम पर्यावरणावर होत असतो. यासोबतच शेतीसाठी उपयोगात आणल्या जाणाऱ्या जे मात्र पाण्यामध्ये शेतपिकारील औषधे, किटकनाशके, तणनाशके इत्यादी मिसळतात. ते तसेच जे आज जमिनीत पाडारत जाऊन खोलवर पाण्यापर्यंत पोहचतात. त्यामुळे भुगर्भातील पाणीसाठा सुध्दा प्रदुषित होऊन त्याचा प्रभाव पर्यावरणावर पडत असतो.

कोई एक दिवसेंदिवस लोकसंख्या वाढत असून नैसर्गिक साधन संपत्तीचा न्हास होत आहे. आणि त्यामुळे Global Warming सारखे विषय मूळ धरू पाहत आहेत. पर्यावरणाचे संवर्धन, जतन व संरक्षण करून समृद्ध व संपन्न गावाची निर्मिती करणे ही काळाची गरज आहे. आपल्या न, कमी गुलभूत गरजांची पूर्तता ही पर्यावरणातून होत असते. हे आपल्याला माहीत असुनसुध्दा पर्यावरण देशाच्या संवर्धनाकरीता आपल्याकडुन कोणतेच प्रयत्न होतांना दिसत नाहीत. उलट मानवाच्या स्वार्था वृत्तीमुळेच पर्यावरणाचे संतुलन मोठ्या प्रमाणावर बिघडत चालले असून त्याबाबत वेळीच विविध जागृकता न झाल्यास येणाऱ्या काळात गंभीर समस्यांना सामोरे जावे लागेल यामध्ये कोणतेही सर्वात दुमत नाही. म्हणुनच शासनाने पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने केलेल्या अनेक प्रयत्नांपैकी एक गंधदे व प्रयत्न म्हणजे सन २०१० - ११ मध्ये सुरू केली पर्यावरण संतुलीत समृद्ध ग्राम योजना या ग्रामीण कार्यक्रमात लोकांनी सहभाग नोंदविला पाहिजे. नव्हे तर पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी वैयक्तीक वळतो. सारावरून पूढाकार घेतला पाहिजे. कारण पर्यावरण संतुलन हे ग्रामविकासाचे मानक आहे.

रिद्रयात ➤ निष्कर्ष :-

मस्येवर शिक्षण, आरोग्य, रोजगार मनोरंजन इ. अशा व्यक्तिच्या विविध गरजांची पूर्तता मुख्यत्वे

शहरात होत असल्याने शहरीकरणाची प्रक्रिया दिवसेंदिवस गतीमान होत असतांना देशातील अधिकाधिक संख्येने जनता वास करीत असलेल्या ग्रामीण भागाकडे मात्र नेहमीच शासनाकडून व एकंदरीत सर्वच स्तरातून दुर्लक्ष होतांना दिसते. त्यामुळे ग्रामीण समाजातील आव्हाने ही कमी होण्याऐवजी त्यात दिवसागणीक भर पडत आहे. शासन स्तरावर विविध योजनांची कार्यवाही केली जाते. पण योजनांची रीतसर अंमलबजावणी करण्यात यंत्रणा कुठेतरी कमी पडत असतात. म्हणूनच ग्रामीण समाजातील विकासाचे प्रश्न हे अनुत्तरीतच राहतात.

वास्तविकतः ग्रामीण समाज हा देशाचा महत्वपूर्ण असा अंग आहे. या अंगाकडे तेवढ्याच सक्षमतेने लक्ष पुरविणे गरजेचे आहे. त्यामुळे तेथील व्यक्तीचे दरडोई उत्पन्न वाढविण्याच्या प्रयत्नाबरोबरच सामाजिक, सांस्कृतिक व राजकीय स्थिती सुधारण्याचेही यशस्वी प्रयत्न व्हावयास पाहिजे. यासोबतच कोणत्याही प्रकारचे सामाजिक आव्हान पेलण्याचे सामर्थ्य ग्रामीण समाजातील प्रत्येक व्यक्तित्व निर्माण करता आले तर २१ व्या शतकातील भारताचे जागतीक महासत्ता बनण्याचे स्वप्न साकार होण्याच्या दृष्टीने करण्यात येत असलेल्या अनेक प्रयत्नांपैकी हा एक दिर्घकालीन व शाश्वत प्रयत्न ठरू शकतो.

संदर्भ:-

पर्यावरण, डॉ. सौ. गौरी राणे व प्रा. ए. पी चौधरी. हिमालया बुक्स प्रा. ली.

<https://manaatale.wordpress.com>

<https://mr.wikipedia.org>

<https://maharashtratimes.com>



**Nutan Vidyalaya Sevabhavi Education Society, Umri
Late Babasaheb Deshmukh Gorthekar Art's,
Commerce & Science Mahavidyalaya,
Umri, Dist. Nanded (M.S.)**



**(Affiliated to Swami Ramanand Teerth Marathwada University, Nanded)
(Recognition U/S 12(B), 2 (F) of the UGC Act 1956)**

Website : www.lbdgmu.in

Email: lbdgcollege@rediffmail.com

One day Interdisciplinary National Conference

On

"Rural Development : Issues & Challenges"

21st December 2019

Organized by

Internal Quality Assurance Cell

**Late Babasaheb Deshmukh Gorthekar Art's,
Commerce & Science Mahavidyalaya, Umri .**

Collaboration with

**Swami Ramanand Teerth Marathwada University,
Nanded (M.S)**

Chief Editor

Dr. Tukaram Vaijanathrao Powale

Co – Editor

Dr. Z. R. Pathan,

Dr. G. P. Yedle

Dr. D. D. Kolhekar,

Dr. V. V. Bhoyar

नूतन विद्यालय सेवाभावी शिक्षण संस्था, उमरी तर्फे
कै. बाबासाहेब देशमुख गोरटेकर कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय,
उमरी येथे आयोजित



‘ग्रामीण विकास : समस्या व आव्हाने’
या एकदिवसीय राष्ट्रीय परिषदेसाठी हार्दिक शुभेच्छा

नूतन विद्यालय सेवाभावी शिक्षण संस्था, उमरी
स्थापना : १९४३

:: संस्थापक अध्यक्ष ::

कै. आ. बालाजीराव उर्फ बाबासाहेब देशमुख गोरटेकर

कार्यकारी मंडळ

- अध्यक्ष : मा. श्री. गोविंदराव नारायणराव मुक्तावार (शिळरकर)
उपाध्यक्ष : मा. श्री. डॉ. एम. एम. महिंद्रकर
सचिव : मा. आ. श्री. श्रीनिवासराव बालाजीराव देशमुख गोरटेकर
सहसचिव : श्री. शिवाजीराव मारोतराव पाटील
कोषाध्यक्ष : श्री. गंगाधर संभाजी गोडगे
सदस्य : श्री. राजेश्वर किशनराव वंगलवार
श्री. नरसिंग गणपत चिटमलवार
श्री. शिवाजीराव श्रीधरराव देशमुख
श्री. प्रभाकर दिगांबर पाटील
श्री. धोंडजी माणिका पाटील
श्री. शंकरराव रामराव शिंदे
श्री. माधवराव गणपती सावंत
श्री. दत्तराम पिराजी लुटके
श्री. सदाशिवराव देवराव सावंत
श्री. मालू पिराजी कांबळे



Nutan Vidyalaya Sevabhavi Education Society, Umri



Late Babasaheb Deshmukh Gorthekar Art's,

Commerce & Science Mahavidyalaya, Umri, Dist. Nanded (M.S.)

(Affiliated to Swami Ramanand Teerth Marathwada University, Nanded)

(Recognition U/S 12(B), 2 (F) of the UGC Act 1956)

Website : www.lbdgmu.in

Email: lbdgcollege@rediffmail.com

One day Interdisciplinary National Conference On

"Rural Development : Issues & Challenges"

21st December 2019

Organized by

Internal Quality Assurance Cell

**Late Babasaheb Deshmukh Gorthekar Art's, Commerce &
Science Mahavidyalaya, Umri**

Collaboration with

**Swami Ramanand Teerth Marathwada University,
Nanded (M.S)**

Chief Editor

Dr. Tukaram Vaijanathrao Powale

Co – Editor

Dr. Z. R. Pathan,

Dr. G. P. Yedle,

Dr. D. D. Kolhekar,

Dr. V. V. Bhoyar.

Published by : Aarhat Publication & Aarhat Journal's

Mobile No : 9922444833 / 8355852142

21st December 2019

ISSN : 2278- 5655

Volume – VIII, Special Issue – XXIII

© Nutan Vidyalaya Sevabhavi Education Society, Umri
Late Babasaheb Deshmukh Gorthekar Art's,
Commerce & Science Mahavidyalaya, Umri, Dist. Nanded (M.S.)

Chief Editor : Dr. Tukaram Powale

Co-Editor : Dr. Z. R. Pathan, Dr. D. D. Kolhekar,
Dr. G. P. Yedle, Dr. V. V. Bhoyar.

EDITORS :

Disclaimer :

The views expressed herein are those of the authors. The editors, publishers and printers do not guarantee the correctness of facts, and do not accept any liability with respect to the matter published in the book. However editors and publishers can be informed about any error or omission for the sake of improvement. All rights reserved.

No part of the publication be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted any form or by any means electronic, mechanical, photocopying, recording and or otherwise without the prior written permission of the publisher and authors.

INDEX

Sr. No	Author Name	Paper Name	Page No
1	Dr. Prakash Ratanlal Rodiya	Sustainable Agriculture Development	01
2	Prof. Kirankumar J. Manure And Dr. Sunil M. Sakure	Role Of Women Sarpanches In Conservation Of Natural Resources, And Sustainable Development	08
3	Dr. S. R. Patode	Role Of Agriculture In Rural Development	15
4	Dr. Telke Sudhakar B.	Role Of Libraries In Rural Development	17
5	प्रा. डॉ. दामावले डी. एन.	मानवी हक्क आणि बालकामगार	20
6	Ganesh W. Patil	Emerging Issues In Rural Development Of Maharashtra	25
7	प्रा. डॉ. प्रणया महेंद्र पाटील	ग्रामीण विकासात महिला स्वयं – सहाय्यता गटांची भूमिका	31
8	प्रा. डॉ. चंद्रशेखर गितें	ग्रामीण विकासात कृषी अर्थव्यवस्थेचे योगदान	40
9	डॉ. लता मल्लिकार्जुन वडजे	भारतातील ग्रामीण भागाच्या विकासात वित्त पुरवठ्याची भूमिका	47
10	कल्पना आबाराव सिडाम	गोंड, पस्थान, जमातीच्या देवी देवतांचा अभ्यास	54
11	संतोष रघुनाथ कांबळे	भाषा, साहित्य आणि ग्रामीण जीवन	56
12	प्रा. डॉ. प्रकाश सदाशिव सूर्यवंशी	साठोत्तरी हिंदी उपन्यासां में चित्रित ग्राम्यजीवन	63
13	सीमा पठाण	पर्यावरण आणि ग्रामीण विकास	67
14	डॉ. एन. जी. भद्रे	ग्रामीण पर्यटन व ग्रामीण विकास	72
15	बुध्देवार सुभाष राजेन्ना	ग्रामीण विकासात शाश्वत शेतीचे महत्व	76
16	K. Saideepti	Self Help Groups And Rural Development	83
17	प्रा. डॉ. चंद्रकांत गजेवाड	ग्रामीण विकासात पायाभूत सुविधांचे महत्त्व	86

18	प्रा. डॉ. पांडुरंग पांचाळ	शाश्वत कृषी विकास एक चिंतन	91
19	Sanjay. M. Dalvi V. N. Kadam R. R. Rakh And And	Isolation And Screening Of Phosphate Solubilizing Bacteria (Psb) For Their Potential Use In Sustainable Agricultural	95
20	R. R. Rakh L. S. Raut S. M. Dalvi And And	For Sustainable Agriculture: Isolation And Screening of <i>Bacillus Spp.</i> For Microbiological Control of <i>Sclerotium Rolfsii</i> Sacc., A Stem Rot Pathogen Of Groundnut	107
21	प्रा. डॉ. प्रमोद सुर्यभान शंभरकर	सामाजिक आव्हाने आणि ग्रामीण विकास	118
22	प्रा. डॉ. बी. एम. कांबळे	ग्रामीण विकास आणि सामाजिक समस्या : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन	125
23	Mr. Mihir Umesh Inamdar	A Critical Analysis Of Domestic Violence In India	130
24	डॉ. महेश प्रल्हादराव गोमासे	पर्यावरण व ग्रामीण विकास	135
25	Dr. C. P. Karkare	Financial Inclusion : Pradhanmantri Janddhan Yojana	140
26	Dr. S. P. Gaikwad	Scope Of Rural Development Through Agrobusiness In India	146
27	डॉ. योगिता मा. पवार (लहानकर)	कृषी आधारित उद्योग आणि ग्रामीण विकास	148
28	डॉ. प्रिया ए.	वैश्वीकरण का समय और अनुपस्थित गाँव	152
29	सुदेश रानी	ग्रामीण पर्यटन : ग्रामीण भारत के समग्र विकास की सम्भावनाएँ	156
30	Ingle S. L.	Impact Of Water Pollutions On Godavari River In Maharashtra State	160
31	मुजावर जैनु हमिद व डॉ. अतुल कुमार पांडेय	हिंदी के आंचलिक उपन्यासों में अभिव्यक्त ग्रामीण जन-जीवन	162
32	श्री करडे महादेव बळीराम	सामाजिक समस्याएँ और ग्रामीण विकास	167
33	श्रीमती भाग्यश्री पांडुरंग पानढवळे	ग्रामीण पर्यटन आणि ग्रामीण विकास	174

34	डॉ. सुनील गुलाबसिंग जाधव	सूखता हुआ तालाब में : – जाति बहिष्कार एवं छूत-अछूत की समस्या ।	181
35	डॉ. मंगल नागोराव मारकड	भारत के ग्रामीण विकास में ग्रामीण वित्त का योगदान	187
36	डॉ. ए. एस. नलवडे	नवीन आर्थिक धोरण : भारताच्या ग्रामीण विकासाचा प्रश्न आणि उपाययोजना	194
37	डॉ. शिवाजी नागोराव भदरगे	ओमप्रकाश वाल्मीकि के कहानियों में श्रमिक ग्रामीण दलित महिलाओं का जीवन	199
38	प्रा. एस. व्ही. शिंदे	ग्रामीण समाज जीवन आणि संगीत	203
39	डॉ. बी. आर. भोसले	भारत की ग्रामीण संस्कृति और मुस्लीम सामाजिक आंदोलन	206
40	प्रा. डॉ. ज्ञानेश्वर गंगाधर गाडे	मैला आँचल – उपन्यास में कृषक जीवन	211

प्रा. डॉ. प्रमोद सुर्यभान शंभरकर
सहयोगी प्रा. राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख,
सरदार पटेल महाविद्यालय, चंद्रपुर

खेड्यांची वा ग्रामीण समाजाची महती प्रतीपादन करतांना मोठ्या अभिमानाने भारत हा खेड्यांचा देश आहे असे म्हटले जाते. इतकेच नव्हे तर एके काळी सोन्याचा धूर निघत असलेल्या भारत देशात खेडी ही स्वयंपूर्ण व स्वावलंबी होती असा इतिहासही सांगितला जातो. मात्र काळाच्या ओघात याच खेड्याकडे दुर्लक्ष होऊन खेडी ही विविध समस्यांचे केंद्रे झालीत. तेथील स्वयंपूर्ण व स्वाश्रयी जीवनाला तडा गेला. तेथील कुटीर व लघू उद्योग मोडकडीस आले. पुर्णता शेती क्षेत्रावर अवलंबून असणारे ग्रामीण जीवन हे कधी परकीय आक्रमणामुळे तर कधी नापीकी वा दुष्काळ पडल्यामुळे परावलंबी झाले. यासोबतच अगदी सुरुवातीपासूनच असणाऱ्या अंधश्रद्धा, जून्या चालीरीती सनातनी प्रथा, रूढी, परंपरा या सारख्या सामाजिक समस्यांनी उग्ररूप धारण केले.

पाश्चात्य शिक्षणाने प्रभावित झालेल्या येथील विशीष्ट वर्गाने तसेच समाज सुधारकांनी ग्रामीण समाजातील विविध समस्यांना वाचा फोडण्याचे कार्य केले. इथल्या अनिष्ट चालीरीती विरुद्ध त्यांनी बंड पुकारला व त्यात त्यांनी बहुतांश प्रमाणात यशही मिळविले. म. गांधींनी तर आपल्या विचार धारेचे केंद्र हे खेड्यालाच ठरविले. खेड्याची झालेली दुर्दशा, ग्रामीण जीवनाला आलेली अघोगती व समस्येचे माहेर घर म्हणून ओळखली जाणारी खेडी ही स्थिती बदलविण्यासाठी गांधींनी ग्रामीण समाजावर अधिका-धिक लक्ष केंद्रीत केले. याच उद्देशांनी त्यांनी ग्रामस्वराज्याची संकल्पना मांडली व ग्राम पुनर्रचनेचे महान कार्य हाती घेतले.

देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही इथल्या सरकारने ग्रामीण जीवनातील विविध समस्या सोडविण्याच्या दृष्टीने व तेथील लोकांना विविध सोयी सवलती उपलब्ध करून त्यांचे जीवनमान उंचावून एकंदरीत ग्रामीण विकासासाठी अगदी सुरुवातीपासूनच प्रयत्न चालविले. यात १९५२ मधील सामुदायीक विकास कार्यक्रमापासून तर केंद्र तथा विविध राज्यातील राज्य सरकारने नेमलेल्या विविध समित्या तसेच अभ्यास गट व त्या अनुषंगांनी झालेली १९९३ मधील ७३ वी घटनादुरुस्ती, यासोबतच मनरेगा, सन २०१०-११ मध्ये सुरू केलेली समृद्ध ग्राम योजना, तसेच आज विशेष उल्लेख करता येईल अशी पंडीत दीनदयाल उपाध्याय कौशल्य विकास योजना तसेच अनेक योजना व कार्यक्रम यांनी ग्रामीण विकासात सिंहाचा वाटा उचलला असतांनाही आपण ग्रामीण विकासाचे सर्वांगीण उद्दीष्ट गाठू शकलेले नाही हे नक्की.

राष्ट्र कोणतेही असो त्यात ग्रामीण समाज उल्लेखनिय कामगिरी बजावत असतो. अन्नधान्ये व इतर कच्चा माल यांचे उत्पादन ग्रामीण भागातच होत असते. या बाबतीतील शहरांची गरज ग्रामीण उत्पादनातूनच भागविली जाते. यासोबतच शहरातील उद्योगधंद्यांना श्रमीक पुरविण्याची जबाबदारीही सहसा ग्रामीण भागच पार पाडतात. राष्ट्राची नैसर्गिक साधनसंपत्तीही बहुतांश प्रमाणात ग्रामीण प्रदेशातच उपलब्ध होते आणि बहुसंख्य लोकांचा निवास वा वस्तीही ग्रामीण प्रदेशातच आढळते. सर्वत्र जगभर शहरांचा विकास होत असतांना जागतिक लोकसंख्येपैकी ग्रामीण भागात राहणाऱ्यांचे प्रमाण १९५० मध्ये ७९ टक्के पेक्षा थोडे अधिकच होते. ते प्रमाण भारतात १९६१ मध्ये ८२ टक्के होते. म्हणजे ८२ टक्के लोक ग्रामीण भागात राहत होते. 'साहजिकच आर्थिक नियोजनाद्वारा राष्ट्रीय विकास साधण्यासाठी ग्रामीण विकास अत्यंत आवश्यक ठरतो. म्हणूनच ग्रामीण समस्यांचे स्वरूप निटपणे समाजावून घेऊन त्या सोडविण्याचे कसोशीने प्रयत्न करावे लागतात.

साधारणपणे ग्रामीण विकासाची दिशा ठरवितांना त्याच्या आर्थिक घटकांवर व मानकावर अधिक लक्ष वेधल्या जाते. यात कृषी विकासाचा संदर्भ सातत्याने जोडण्यात येत असतो. अर्थात या क्षेत्रामधील रोजगाराची उपलब्धता, दारिद्र्य निर्मुलन व लोकांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे या बाबी अपेक्षित असतात. ग्रामीण विकासाच्या संदर्भात आर्थिक दृष्टीकोनातून बरील सर्व बाबीची उपलब्धता होणे हे गरजेचे असले तरी ग्रामीण विकासाच्या संदर्भात सामाजिक परिस्थिती व सामाजीक समस्या आणि एकंदरीतच ग्रामीण विकासाला प्रभावित करणारी किंबहुना त्यात अळथडा बणू पाहणारी सामाजिक आव्हाने यावर प्रकाश टाकणे महत्त्वपूर्ण ठरते. कारण शासकिय तसेच अशासकीय स्तरावरून विविध योजनांच्या माध्यमातून आर्थिक व राजकीय क्षेत्रातील आव्हानांचा मुकाबला करणे वा त्यावर मात करणे काही 'प्रमाणात शक्य असले तरी अगोदरच भारतातील समाजात व विशेष म्हणजे ग्रामीण समाजात आपले मुळ घट्ट रोवणाऱ्या सामाजाजिक आव्हानांच्या संबधात ग्रामीण विकास अधिक प्रमाणात बाधित होत असतो.

भारतातील ग्रामीण समाज व या समाजाच्या विकासाला प्रभावीत करणारी सामाजिक आव्हाने याचा परमर्श पृढील मुद्द्यांच्या आधारे घेता येईल.

➤ अंधश्रद्धा व जुन्या चालीरीती :-

भारतीय ग्रामीण समाज हा विविध अंधश्रद्धेनी ग्रासलेला आहे. त्यात जुन्या चालीरीती फार पूर्वीपासूनच या समाजाचा एक भाग बनलेल्या आहेत. अंधश्रद्धा म्हणजे एखादी गोष्ट आंधळेपणाने स्वीकारणे होय. या अंधश्रद्धेचे प्रमाण ग्रामीण समाजात मोठ्या प्रमाणावर आहे. ग्रामीण समाजातील निरक्षर व्यक्ति वा कुटुंबच नाहीतर सुशिक्षित वर्ग सुद्धा या समस्येने बळी पडत आहेत. अगदी रोजची वर्तमानपत्रे बघीतली तरी त्यातील किमान ४ ते ६ बातम्या ह्या

अंधश्रद्धा वा त्या समस्ये संबधातील असतात. यात जादुटोना, बळी, गुप्तधन या यारख्या कुप्रथांचा समावेश असतो. त्यातच शिक्षणाचे प्रमाण कमी असल्यामुळे अशा समाजाकडून प्रत्येक गोष्ट ही विवेकाच्या कसोटीवर तपासण्याचा प्रयत्न होत नाही. त्यामुळे संबंधीत घटनेत एकटा व्यक्तिच प्रभावित होत नसतो. तर त्याचे संपूर्ण कुटुंब व समाजालाही अपरिमीत हानी पोहचत असते.

जुन्या चालीरीती व रूढी याविषयीसुद्धा तेच सांगता येईल यात कालबाह्य अशा विचारांचे सक्रमण हे एका पीढीकडून दुसऱ्या पीढीकडे सहजरित्या होत असते. लोक हे जुन्या विचारांना चिकटुण वा खीळून बसलेले असतात. अशा लोकांमध्ये कालबाह्य विचार आत्मसात करणारे तसेच रूढी व परंपरांना धरून चालणाऱ्या समाजाकडून बदलांची अपेक्षा करणे हे व्यर्थ ठरते. म्हणूनच अशा जुन्या चालीरीती व अंधश्रद्धा ह्या ग्रामीण विकासात प्रमुख आव्हाने ठरतात. या परिस्थितीत सुधाराकांनाही हाल अपेष्टा सहन कराव्या लागतात व बहुतेकदा यात त्यांचा बळीही जातो. याचे जीवंत उदाहरण म्हणजे नरेंद्र दाभोळकर, गोविंद पाणसरे यांची अमानूपपणे करण्यात आलेली हत्या हे होय.

ग्रामीण विकासात या समस्या आजही प्रमुख आव्हाने म्हणून समोर येत आहेत अंधश्रद्धेमुळे गरीब आणि दुबळे लोक हे गरीब. — दुबळेच राहतात. त्यांना त्या असाह्य परिस्थितीतून वर उठायला काही वावच राहिलेला नसतो. यात अनेक कर्मकांड आणि आचार हे असे असतात की, त्यापायी मानसाचा कष्टाने मिळविलेल पैसा, त्याची मेहनत व वेळ यांचा अगाप अपव्यय होत असतो. त्यामध्ये समाजाचेही अपरिमीत असे नुकसान होते व त्यामुळे एकंदरीतच ग्रामीण विकासाचे प्रयत्न असफल ठरतात.

➤ जातीयवाद :-

आज देशाने विज्ञान व तंत्रज्ञान, दळण — वळण उदयोगधंद्याचा विकास व त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात झालेले व होत असलेले शहरीकरण हे एकीकडे विकासाचे सुचक असले तरी मात्र दुसरीकडे ग्रामीण समाजाला लागलेला एक कलक वा किड म्हणून जातीचा प्रामुख्याने विचार करता येईल. या जातीने आजही ग्रामीण समाजात आपले पाय घट्ट रोवलेले आहेत. या जातींना हजारो वर्षांची परंपरा लाभलेली आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात जातीप्रथांच्या प्रभावामुळे निर्माण झालेली बंधने झुगांरून देण्यासाठी अनेक आंदोलने झाली. जात — पात तोडण्याचेही आंदोलन झाले. व्यक्तिच्या सामाजिक जीवनातील आणि प्रामुख्याने सामाजिक संबंधांमधील जातीचा प्रभाव नष्ट करण्याच्या हेतूने अनेक समाजसुधारकांनी प्रयत्न केले. काहीणी या समाजकार्यासाठी आपले संपूर्ण आयुष्य खर्ची घातले. या सर्व प्रयत्नांमधून जाती प्रथेमध्ये काही महत्त्वपूर्ण असे बदल घडून आले असले तरी जातीचे समुच्च उच्चाटन मात्र झालेले नाही.

ग्रामीण समाजात जातीचे प्राबल्य मोठ्या प्रमाणात जाणवते. संविधानातून मिळालेले मुलभूत अधिकार, शिक्षणाचा विस्तार व प्रसार, विकास कार्यक्रम, समाजसुधारकांचे प्रयत्न यामुळे व्यक्तीच्या सामाजिक जीवनाची रूपरेखा निश्चीत करण्यामधील जातीप्रथांचा प्रभाव कमी होण्यास मदत झाली असली तरी राजकीय समीकरण जुळवतांना जातीला झुकते माप दिले जाते. यातच भर म्हणजे जातीच्या आधारावरच आरक्षणाची मागणी आज जोर धरू लागली आहे. या प्रकारचे वातारण वा निर्माण झालेली स्थिती ही ग्रामीण विकासाच्या दृष्टीने निश्चीतच योग्य ठरत नाही. राजकारणामुळे जातीयवादाला खतपाणी घातले जाते. मतांच्या राजकारणासाठी जाती जातीमध्ये तेढ निर्माण करून त्याचा राजकीय फायदा घेण्याचे काम सध्या तेजीत चालू आहे. यासाठी सर्वात पोषक स्थिती म्हणून ग्रामीण भागाला लक्ष केले जाते.

व्यवसाय स्वातंत्र्याचा अभाव, विशेषाधिकार व अपात्र ठरविणे, श्रेष्ठ कनिष्ठतेच्या तत्वांची सोपान परंपरा, जन्माने निश्चित होणारे स्थान, विवाहावरील निर्बंध ही सर्व जातीची देण असून ग्रामीण भागात यांच्या पालणावर आजही कटाक्ष दिसून येते. यात भर म्हणजेच या सर्वांना खतपाणी मिळत असेल तर ते निश्चितच विकासाला बाधक ठरत, असते. म्हणूनच जात हा घटक ग्रामीण विकासाच्या प्रवासातील एक आव्हान बणू पाहत आहे.

स्त्रिविषयक नकारात्मक दृष्टीकोण :-

आज नागरीकरणामुळे स्त्रीचा कुटुंबातील दर्जा उंचावण्यास मदत झाली आहे. नागरी कुटुंबात कुटुंब प्रमुखाच्या एकाधिकारशाहीचा न्हास होत आहे. कुटुंबातील कामाच्या बाबतीत लिंगभेदावर आधारलेले कार्य विभाजन राहतात टिकू शकत नाही. नोकरी वा इतर कामधंद्यामुळे घराबाहेर असणाऱ्या पुरुषास कुटुंबाच्या दैनंदिन व्यवहाराकडे लक्ष देणे शक्य नसते. त्यामुळे घरातील व बाहेरील इतर कामे करण्याची जबाबदारी स्त्रीवर येऊन पडत असते. त्यामुळे स्त्रीयांचे स्थान उंचावण्यास ही स्थिती पोषक ठरत असातांना मात्र ग्रामीण भागात याच्या विपरीत असलेली स्थिती पाहायला मिळते.

ग्रामीण समाजात आजही स्त्रीयांना गौण स्थान दिले जाते. शिक्षणाचा प्रसार व प्रचार झाले आहेत. ग्रामांमध्ये स्त्रीयांच्या स्थितीत बदल घडून येत असला तरी त्या बदलापासून ग्रामीण भागातील ग्रामांमध्ये मोठा समूदाय हा वंचितच राहीलेला दिसून येते. चुल व मुल या परिघाच्या बाहेर स्त्रीयांनी कुल ठेवलेला असला तरी कुटुंबातील महत्वपूर्ण निर्णय आजही पुरुष मंडळीच घेत असतात. सोबतच जातीच्या प्राबल्याचा आधार मिळत असल्यामुळे सामाजिक स्तरीकरणाची गतीही काहीणी दावलेली दिसून येते. त्यामुळे ग्रामीण भागातील स्त्रीयांना अनेकाधिक संकटांना तोंड द्यावे प्रथेमध्ये कमी येत नाही.

आज स्त्रीयांच्या न्याय हक्कविषयक अनेक संघटना, महिला आयोग कायद्यातील सुदी इ. चे पाठबळ असले तरी ग्रामीण स्त्रीयांत या विषयी पाहीजे त्या प्रमाणात जागृकता

झालेली दिसत नाही. समान कामासाठी आजही ग्रामीण भागात स्त्री-पुरुषांना असमान मोबदला दिला जातो. राजकीय क्षेत्रातील आरक्षणामुळे स्त्रियांचा सार्वजनिक क्षेत्रातील सहभाग वाढत असला तरी मात्र पडद्यामागुन कुणीतरी वेगळाच भूमिका साकारत असतो. अर्थात विशिष्ट पदावर स्त्री असली तरी त्यासंबंधातील निर्णय मात्र पुरुष मंडळीच घेत असतात. स्त्रिविषयक असणाऱ्या या नकारात्मकतेचा प्रत्यय आपल्याला ग्रामीण भागात सहज घेता येतो. वास्तविकपणे स्त्रिया ह्या जागतीक लोकसंख्येचा अर्धा भाग आहेत. स्त्रियांचा सार्वजनिक जीवनातील सहभाग वाढला की त्यातून सांस्कृतिक, आर्थिक समृद्धी अधिक वाढणार हे कोणीही नाकारू शकत नाही.

➤ बेरोजगारी :-

ग्रामीण विकासातील एक प्रमुख आणि महत्त्वपूर्ण आव्हान म्हणून बेरोजगारीचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल. ग्रामीण भागातील लोकांना रोजगाराची उपलब्धता करून देणारे क्षेत्र म्हणून शेती क्षेत्राकडे पाहिले जाते. मात्र या शेतीवर वर्षातील फक्त ४ ते ६ महिनेच रोजगाराची उपलब्धता होत असते. उर्वरित महिन्यात रोजगारासाठी तेथील लोकांना शहरांकडे धाव घ्यावी लागते अन्यथा खाली राहावे लागते. त्यातच शेती क्षेत्रात आज विविध तंत्रज्ञानाचा वापर होऊ लागल्यामुळे मनुष्यबळाची मागणी कमी होऊ लागलेली आहे. मनरेगा सारख्या सरकारी योजनांच्या माध्यमातून बेरोजगारी या समस्येवर मात करण्याचा प्रयत्न होत आहे मात्र तोही विविध कारणामुळे शाश्वत उपाय ठरत नाही. त्यामुळे बेरोजगारी या समस्येने आज ग्रामीण भागात एक विक्राळ रूप धारण केलेले दिसते.

शहरी बेरोजगारीसह ग्रामीण भागातील बेरोजगारी ही देशातील गंभीर समस्यांपैकी एक म्हणून संबोधली जाते. कारण यामुळे संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होतो. वैयक्तिक आणि त्याच्या कुटुंबाचे नुकसान होण्याव्यतिरीक्त त्याचा परिणाम कमी खरेदी वा गुंतवणुकीवर होऊन वस्तु व सेवांचा वापर कमी होऊन त्यामुळे वस्तुच्या उत्पादनाचा कमी वापर होऊन, कमी उत्पादनामुळे देशांच्या महसुलात कमी योगदान होते आणि याचा परिणाम शेवटी देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होत असतो.

आज तर बेरोजगारी या समस्येने देशात गंभीर रूप धारण केलेले आहे. विविध विभागातील मागीललेल्या माहितीच्या आधारे हे स्पष्ट झाले आहे. की, ४७ वर्षातील हा सर्वात मोठा बेरोजगारीचा वाढलेला दर आहे. याचा सर्वात मोठा फटका शहरातील उदयोगधंदे व तेथील काम करणाऱ्या कामगार वर्गावर झाला असला तरी हा कामगार वर्ग मुख्यत्वे ग्रामीण क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करणारा आहे. असा वर्ग जेव्हा परत आपल्या ग्रामीण भागाकडे वळतो. तेव्हा तेथील कुटुंब व्यवस्थेवर मोठ्या प्रमाणात ताण येत असतो व परीणामी त्यांच्या दारिद्र्यात वाढ होते. ही स्थिती दूर करण्यासाठी ग्रामीण भागातील या बेरोजगारीच्या समस्येवर

वदला स्वयंरोजगार, अल्पदराने कर्जाची सुवीधा शेती क्षेत्रामध्ये सिंचनाच्या सोयी या सारख्या वाढत दिव्घकालीन उपायांचा अमल करणे गरजेचे आहे. ग्रामीण बेरोजगारी दुर झाल्यावरच शहरांचा व विशिष्ट पर्यायाने देशाचा विकास साधता येईल हे नक्की.

विषयक ➤ पर्यावरणाचे संरक्षण :-

येतो. पृथ्वीवरील सर्व संजीवासाठी पर्यावरणाचे महत्व अवर्णनीय आहे. विशेषतः मानवी जीवन दीर्घायुषी, सुखकर, आनंदमय आणि सुरळित होण्यासाठी पर्यावरणीय संतुलनाची नितांत गरज आहे. आजच्या विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या अवकाश युगामध्ये प्रचंड प्रमाणात औद्योगिक, तांत्रिक विकास हाऊन पर्यावरणाच्या संतुलनाला धक्का पोहचला आहे. स्पर्धेच्या आणि उत्पादन वाढीच्या कसरतीमध्ये पर्यावरणाच्या अनेक समस्यांनी आकाळ विकाळ स्वरूप धारण केले आहे. अशा परिस्थितीत सजीवसृष्टी टिकवून ठेवण्यासाठी पर्यावरणाचे संरक्षण करणे अगत्याचे होऊन गार क्षेत्र बसते.

महिनेच शहरी भागाच्या तूलनेने ग्रामीण भागात पर्यावरणाच्या न्हासाचे प्रमाण कमी असले तरी शहरांकडे या प्रमाणाकडे निश्चीतच दुर्लक्ष करता येणार नाही. ग्रामीण भागात आजही इंधन, घरबांधणी, आज्ञानाचा लाकडी वस्तूची निर्मिती इ. अशा विविध कामांसाठी मोठ्याप्रमाणात वृक्षतोड केली जाते. याचा सारख्या सर्व परिणाम पर्यावरणावर होत असतो. यासोबतच शेतीसाठी उपयोगात आणल्या जाणाऱ्या जे मात्र पाण्यामध्ये शेतपिकारील औषधे, किटकनाशके, तणनाशके इत्यादी मिसळतात. ते तसेच ते आज जमिनीत पाडरत जाऊन खोलवर पाण्यापर्यंत पोहचतात. त्यामुळे भुगर्भातील पाणीसाठा सुध्दा प्रदुषित होऊन त्याचा प्रभाव पर्यावरणावर पडत असतो.

कोई एक दिवसेंदिवस लोकसंख्या वाढत असून नैसर्गिक साधन संपत्तीचा न्हास होत आहे. आणि त्यामुळे Global Warming सारखे विषय मूळ धरू पाहत आहेत. पर्यावरणाचे संवर्धन, जतन व वर नेऊन संरक्षण करून समृद्ध व संपन्न गावाची निर्मिती करणे ही काळाची गरज आहे. आपल्या न, कमी मुलभूत गरजांची पूर्तता ही पर्यावरणातून होत असते. हे आपल्याला माहीत असुनसुध्दा पर्यावरण देशाच्या संवर्धनाकरीता आपल्याकडुन कोणतेच प्रयत्न होतांना दिसत नाहीत. उलट मानवाच्या स्वार्था वृत्तीमुळेच पर्यावरणाचे संतुलन मोठ्या प्रमाणावर बिघडत चालले असून त्याबाबत वेळीच विविध जागृकता न झाल्यास येणाऱ्या काळात गंभीर समस्यांना सामोरे जावे लागेल यामध्ये कोणतेही सर्वात दुमत नाही. म्हणुनच शासनाने पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने केलेल्या अनेक प्रयत्नांपैकी एक गंधदे व प्रयत्न म्हणजे सन २०१० - ११ मध्ये सुरू केली पर्यावरण संतुलीत समृद्ध ग्राम योजना या ग्रामीण कार्यक्रमात लोकांनी सहभाग नोंदविला पाहिजे. नव्हे तर पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी वैयक्तीक वळतो. सारावरून पूढाकार घेतला पाहिजे. कारण पर्यावरण संतुलन हे ग्रामविकासाचे मानक आहे.

रिद्रयात ➤ निष्कर्ष :-

मस्येवर शिक्षण, आरोग्य, रोजगार मनोरंजन इ. अशा व्यक्तिच्या विविध गरजांची पूर्तता मुख्यत्वे

शहरात होत असल्याने शहरीकरणाची प्रक्रिया दिवसेंदिवस गतीमान होत असतांना देशातील अधिकाधिक संख्येने जनता वास करीत असलेल्या ग्रामीण भागाकडे मात्र नेहमीच शासनाकडून व एकंदरीत सर्वच स्तरातून दुर्लक्ष होतांना दिसते. त्यामुळे ग्रामीण समाजातील आव्हाने ही कमी होण्याऐवजी त्यात दिवसागणीक भर पडत आहे. शासन स्तरावर विविध योजनांची कार्यवाही केली जाते. पण योजनांची रीतसर अंमलबजावणी करण्यात यंत्रणा कुठेतरी कमी पडत असतात. म्हणूनच ग्रामीण समाजातील विकासाचे प्रश्न हे अनुत्तरीतच राहतात.

वास्तविकतः ग्रामीण समाज हा देशाचा महत्वपूर्ण असा अंग आहे. या अंगाकडे तेवढ्याच सक्षमतेने लक्ष पुरविणे गरजेचे आहे. त्यामुळे तेथील व्यक्तीचे दरडोई उत्पन्न वाढविण्याच्या प्रयत्नाबरोबरच सामाजिक, सांस्कृतिक व राजकीय स्थिती सुधारण्याचेही यशस्वी प्रयत्न व्हावयास पाहिजे. यासोबतच कोणत्याही प्रकारचे सामाजिक आव्हान पेलण्याचे सामर्थ्य ग्रामीण समाजातील प्रत्येक व्यक्तित्व निर्माण करता आले तर २१ व्या शतकातील भारताचे जागतीक महासत्ता बनण्याचे स्वप्न साकार होण्याच्या दृष्टीने करण्यात येत असलेल्या अनेक प्रयत्नांपैकी हा एक दिर्घकालीन व शाश्वत प्रयत्न ठरू शकतो.

संदर्भ:-

पर्यावरण, डॉ. सौ. गौरी राणे व प्रा. ए. पी चौधरी. हिमालया बुक्स प्रा. ली.

<https://manaatale.wordpress.com>

<https://mr.wikipedia.org>

<https://maharashtratimes.com>

Impact Factor – 6.261

ISSN-2348-7143

INTERNATIONAL RESEARCH FELLOWS ASSOCIATION'S

RESEARCH JOURNEY

Multidisciplinary International E-research Journal

PEER REFEREED & INDEXED JOURNAL

December -2019

SPECIAL ISSUE - CCV

भारतीय अर्थव्यवस्था : स्थिती व दिशा

Indian Economy : Condition & Direction

Guest Editor :

Dr. Subodh kumar Singh

Prof.Ravindra B.Shende

Chief Editor

Dr.Dhanraj T.Dhangar

The Journal is indexed in:

Scientific Journal Impact Factor (SJIF)

Cosmos Impact Factor (CIF)

Global Impact Factor (GIF)

Universal Impact Factor (UIF)

International Impact Factor Services (IIFS)

Indian Citation Index (ICI)

Dictionary of Research Journal Index (DRJI)



RESEARCH JOURNEY

Multidisciplinary International E-research Journal

PEER REFEREED & INDEXED JOURNAL

December -2019

SPECIAL ISSUE - CCV

भारतीय अर्थव्यवस्था : स्थिती व दिशा

Indian Economy : Condition & Direction

Guest Editor :

Dr. Subodhkumar Singh

(Principal)

Prof. Ravindra B. Shende

HOD, Dept of Economics

Lokmanya Mahavidyalaya, Warora,

Dist- Chandrapur (MS) 442907

Chief Editor :

Dr. Dhanraj T. Dhangar,

SWATIDHAN INTERNATIONAL PUBLICATIONS

For Details Visit To : www.researchjourney.net

© All rights reserved with the authors & publisher

Price : Rs. 225/-

116	Goals of Five Trillion US\$ Indian Economy Dr. Raju Ghanshyam Shrirame	434
117	Education 4.0 for Industrial Revolution 4.0 Aparna Samudra	439
118	Goods and Service Tax (India): Impacts on Startups Dr. L. Dhanamanjuri Devi	442
119	Recent Trends in Indian Banking Sector Dr. Rajesh P. Kamble	445
120	Economic Growth And Its Impact Of Service's Sector In India : A Study Dr. Mahendrakumar D. Katre	447
121	Goods and Service Tax Dr. Swarnalata Warke	451
122	Topic : Industry 4.0 in India Dr. Madhuri Chansarkar	451
123	Green Marketing& its Impact on Society: Emerging Challenges & Opportunities Prof. Mahendra Sonawane	458
124	Thoughts On Poverty By Nobel Winner Abhijit BanerjeeIn Indian Context Rupeshkumar Raut / Dr. Sharyu Potnurwar	463
125	Role of Reserve Bank of India in Indian Economy Prof. Nitesh Jogi	468
126	Rural Development: Representative of India's Economic Development Dr.Mrs. Manisha Vinay Aole	472
127	Industry 4.0: the future concepts and new visions of factory of the future development Prof. Hitesh b. Bhoyar	477
128	Indian Economy and Transition towards Goods and Service Tax Dr. Gajanan B. Patil	481
129	Financial views of Indian legends Dr. B.R. Ambedkar Dr. Rekha m Badodekar	487
130	Rural Development in India Dr. Nitin B. Kawadkar	490
131	Issue and Problems in Rural Development Programmes in India. C.K.Jiwane	494
132	In Indian Economy : A case of internet merchants retain promises and commitments of e-commerce Customers in Chandrapur City Dr. Hareesh T. Gajbhiye	499
133	A study of Marketing Management of Indian Agri-Business: A Case of awareness among farmers about substitute fertilizers in Chandrapur District Dr. Laxman T. Kamdi	503
134	Industrial Revaluation 4.0 and Challenges of India. Deepali Pathrabe	507
135	Role of Women in Sustainable Development Sonal Agrawal	511
136	Dilemma and Tensions that arises from social entrepreneurship in resolving a complexity of society Dr. Ravi Vyas / and Rekha Kadam	514



Thoughts On Poverty By Nobel Winner Abhijit Banerjee In Indian Context

Rupeshkumar Raut

*Assistant District Planning Officer, District Planning
Committee, Chandrapur, Maharashtra, India*

Dr. Sharyu Potnurwar

*Assistant Professor and HoD (Economics), Sardar Patel
Mahavidyalaya, Chandrapur, Maharashtra, India*

Introduction

Abhijit Vinayak Banerjee was educated at Calcutta University, Jawaharlal Nehru University and Harvard University, where he received his doctorate in 1988. He is currently an international professor at the Ford Foundation in Economics at the Massachusetts Institute of Technology. In 2003 he founded the Abdul-Latif Jameel Poverty Alleviation Laboratory (J-PAL), along with Esther Duflo and Sindhil Mullenathan, and still remains one of the laboratory's directors.

In 2009 J-PAL won the "Frontier of Knowledge" award for the BBVA Foundation in the Development Cooperation category. He received numerous awards, including the inaugural Infosys Prize in 2009, and was an honorary advisor to many organizations, including the World Bank and the Government of India. In 2019, he gave an annual lecture to the 34th Indian Export and Import Bank on the redesign of social policy. In 2019, he won the Nobel Prize in Economics, along with Esther Duflo and Michael Kremer, for their work in alleviating poverty in the world.

According to Banerjee, poverty is synonymous with hunger. This link between poverty and hunger was established in the first United Nations Development Goal (MDG), which is "poverty and hunger reduction". For him, poverty lines in many countries were originally set to capture the idea of poverty on the basis of hunger - the budget needed to purchase a certain number of calories, as well as some other indispensable purchases (such as housing).

He believed that the economics of poverty mistook the poor economy: because the poor possessed so little, it is assumed that there was nothing interesting about their economic existence. Unfortunately, this misunderstanding severely undermines global poverty: simple problems generate simple solutions. The area of anti-poverty policy is full of immediate effects of miracles, which have proven to be less than a miracle.

Objectives Of The Study

1. To know the ideas of Banerjee Poverty in the Indian context.
2. Identify the various issues related to poverty in the Indian context.
3. To find future prospects for poverty reduction.

Research Methodology

This study is based on the secondary data available in different books, reports and magazines.

Thoughts on Poverty by Abhijit Banerjee

1. Understand development and alleviate poverty

According to Banerjee, despite the tremendous progress of the past few decades, global poverty remains in all its various dimensions - a broad and rooted problem. An example cited that day; more than 700 million people live on very low incomes. Every year, five million children under the age of five die from diseases that could have been prevented or often treated by a handful of proven interventions. Today, a large majority of children in low- and middle-income countries attend primary

school, but many leave school and lack proficiency in reading, writing, and mathematics. How to effectively reduce global poverty remains one of humanity's most pressing questions. It is also one of the biggest questions facing economic discipline since its inception. So, what are the best ways to define strategies to help the less affluent?

Pioneering the experimental research approach to providing such answers, the 2019 award winners - Abhijit Banerjee, Esther Duflo and Michael Kramer - transformed development economics. As a result, we now have a large number of concrete outcomes around specific mechanisms behind poverty and specific interventions to mitigate this. For example, with regard to school education, strong evidence now indicates that hiring contract teachers is generally a cost-effective way to improve student learning, while the effect of reducing class size is mixed, at best. With regard to health, it has been shown that the investments of the poor in preventive care are very sensitive to the prices of health products or services, which gives a strong case for generous subsidies for these investments. Regarding credit, the growing evidence indicates that microfinance programs do not have the development implications that many believed when introducing them widely.

2. The experimental approach to global poverty alleviation

In a series of contributions, Banerjee and Duflo explained the intellectual state of the microeconomic approach to help understand the various aspects of the broader (macroeconomic) development problem (Banerjee and Duflo 2005, 2007, 2011). Among these, the paper published by Banerjee and Duflo in 2005 is a key conceptual part that links microeconomic development issues with low per capita income in developing countries. The starting point for this work is an important empirical observation: low- and middle-income countries have large variations in rates of return for the same factors of production and a large disparity in the extent to which profitable investment opportunities are exploited. The extent of this mis-distribution may be severe enough to help explain the large gaps in total productivity between low- and high-income countries highlighted in the empirical growth literature.

Intuitively, when resources are optimally allocated, the economy will operate to the limits of production possibilities. When resources are misallocated, the economy will operate within these limits: production and productivity will be less than possible. Banerjee and Duflo also argued that market and government flaws documented in development literature - whether government failures, credit restrictions, insurance failures, external factors, family dynamics, or behavioral issues - could help explain misallocation.

The first step to understanding why some countries are poor is to identify important sources of inefficiency and policies to address them. The Weak Economy: Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty (Banerjee & Duflo 2011) takes this argument one step further. Based on the findings of a large group of small studies on the causes of poverty, Banerjee and Duflo learned lessons from a science-based approach to improving poor people's health, education and income.

3. Evidence for combating poverty in developing countries

Banerjee traces the intellectual history of the experimental approach to development economics, focusing on a range of thematic areas: education, health, behavioral biases, gender and politics, and credit.

3A. Education

Banerjee believed that just providing more resources had a limited impact on the quality of the school. The number of textbooks for each student did not improve the average test scores, but did not improve the results of the more able students' exams. The giving of school diagrams had no effect on student learning. Health interventions reduced two absences from school, but did not improve test results. In theory, a stimulus program could lead teachers to either increase efforts to stimulate long-term learning, or alternatively, to teach for the test. The last effect dominated. The teachers increased

their efforts in preparing for the test, which led to raising the test scores in the exams related to incentives, but left the test scores in the unrelated exams unaffected.

The findings from the first field trials in Kenya provided a starting point for an early-randomized randomized trial related to education in India, which started in 2000 (Banerjee, Cole, Duflo and Linden 2007). Upon reviewing Kenya's findings, Banerjee, Duflo and his co-partners concluded that students seemed to have learned nothing from additional days at school. Spending on textbooks does not seem to foster learning, although schools in Kenya lacked many basic inputs. Moreover, in the Indian context Banerjee and Duflo intended to study, it seemed that many children were learning nothing: in the results of field tests in Vadodara, fewer than one in five third-graders were able to correctly answer mathematics test questions in the first grade in the curriculum. In response to these findings, Banerjee, Duflo and the study co-authors have argued that efforts to get more children into school must be complemented by reforms to improve school quality. Additional inputs may only work when specific, unmet needs are met.

By working with a large NGO in public schools in India, Banerjee and Duflo studied the impact of two interventions targeting learning by weaker students. One was a compensatory educational program hired by professional cadres to work with underperforming third and fourth grade students outside of the regular semester. The other program was a computer-supported educational program where fourth-grade kids played games with math puzzles on a shared computer for two hours a week. Unlike previous work on general additions to resources, Banerjee, Duflo, and their co-authors found significant positive medium-term effects on student learning for both interventions, after one year and two years.

The clear learning rates of many students in low and middle income countries have several roots, including the aforementioned mismatch between academic student preparation and target teacher levels. A number of studies conducted in the early 2000s (e.g. Chowdhury, Hammer, Kremer, Muralihaman and Rogers 2006, Banerjee, Dayton and Duflo 2004) highlighted an additional possibility: many teachers in low-income countries do not actually teach when they are supposed. In other words, teacher absenteeism rates are very high. In a series of papers in the early 2000s, Duflo and Banerjee, along with several co-authors, began a systematic exploration of how to address teacher absenteeism. Duflo, Hanna, and Ryan started a field experiment in 2003 that examined high-strength incentives associated with attendance (Duflo, Hanna, and Ryan 2012).

By working with a non-governmental organization that runs individual teacher schools in rural India, they randomly choose some schools where teachers receive an additional bonus daily, as verified by school cameras at the beginning and end of the school day. They found that the absence of the teacher decreased by half in the treatment schools relative to the control schools. Moreover, student learning improved.

3B. the health

Modern public health technologies, such as vaccines, antibiotics, antimalarial drugs, and effective preventive methods, such as mosquito nets and drinking water treatment, have improved health to historically unprecedented levels even in low-income countries. However, the risk of dying a child before the age of five is still about 15 times higher in low-income countries than in high-income countries. Coverage of a range of low-cost preventive health products is still patchy in the developing world.

Health systems in developing countries are often very dysfunctional. A recent estimate indicates that the majority of deaths in low and middle income countries are due to poor quality care. Understanding the reason for the poor quality of health services and the policies that could be improved has been a very active research field in development economics. The early absentee studies discussed above provided significant impetus to this agenda, and much of the early work focused on the channel of effort.



High rates of absenteeism, as well as the provision of poor public services in general, were motivations for a pilot study by Banerjee and Duflo and her co-authors on ways to improve immunization coverage in rural India (Banerjee, Duflo, Glennerster and Kothari 2010). In the study area, only 2 per cent of children aged one to two years received the recommended package of basic vaccinations. In this study, researchers discussed several reasons for low absorption rates, including poor provision of public services. For example, in the year before the intervention, they documented that nearly half of the health workers in charge of immunization were absent from their health centers and could not be found anywhere in their villages.

3C. Behavioral biases

Together with Duflo and Banerjee's descriptive work on the economic life of the poor based on household surveys conducted in 13 countries (Banerjee and Duflo 2007), Kenyan experiments conducted by Duflo, Kremer and Robinson (2011) greatly influenced subsequent research on cognitive and psychological decision. Made by the poor. This work was conceptually novel. The designs and results came out in the study through a series of successive experiments. New rounds of experiments began in response to the results of previous experiments, with the design of each treatment guided by theory. Such an iterative educational process, using experimental methods, context nodes, and fixed populations, is usually associated with laboratory experiments. Unlike most laboratory experiments in economics, field experiments included professionals in the real world.

3D. Sex and politics

To verify the impact of the so-called women's reservations, Duflo and Chattopadhyay surveyed a sample of villages in West Bengal and Rajasthan, where the first had a long history of village elections as well as more comprehensive decentralization powers devoted to village councils. In both states, a specific set of rules ensured that chairs were intended for women in a random group of village councils. By exploiting these rules and data from their own polls, Duflo and Chattopadhyay can estimate the effects of having randomly chosen leaders. They found that leaders apparently made decisions that better matched women's preferences. In West Bengal, village women were more concerned with drinking water and roads, while village men were more concerned with education. Indeed, female leaders in West Bengal have invested more than male leaders in drinking water and roads, at the expense of education. Conversely, in Rajasthan, where women are more interested in men than water but less interested in roads, Gram Panchayats for female leaders set similar priorities in their investments, spending more money on water than roads.

3E. credit

Misallocation of capital and other inputs to the total production function can reflect credit constraints of some companies. This mechanism was at the heart of Banerjee and Duflo's work that illustrated the link between countless distortions in low-income economies and the large difference in productivity and income identified in the experimental growth literature (Banerjee and Duflo 2005). A number of influential contributions from Banerjee, Duflo, and their co-authors have investigated the existence of credit restrictions, their causes, and consequences. In 2002, Banerjee and Duflo first proposed an idea that provided convincing evidence about binding credit restrictions by studying a targeted lending program in India (Banerjee and Duflo 2014). The intervention essentially ordered banks to lend to a certain group of companies. Using an analysis of differences in differences, Banerjee and Duflo (2014) found that credit expansion significantly increased sales and profits for targeted companies. They concluded that this is a demonstration of the credit restrictions of large companies. Had these firms not been constrained, the targeted lending program might have changed their portfolios - which allowed them, for example, to pay off expensive debts - but would not change their real behavior



4. Lending to the poor

According to Banerjee, very few poor families get loans from an appropriate lending institution such as a commercial bank or cooperative. In our survey in Udaipur, in rural India, about two-thirds of the poor got a loan. 23 percent were from close, 18 percent from a lender, 37 percent from a store owner, and only 6.4 percent came from an official source. The low bank credit ratio is not due to the lack of physical access to banks, because there is a similar pattern in urban Hyderabad, where homes that live on less than \$ 2 a day are mainly borrowed from lenders (52 percent), friends or neighbors (24 Percent), and family members (13 percent). Only 5 percent of their loans are with commercial banks. In all the countries that we have in our 18 dataset, we have less than 5 percent of the rural poor who have a loan from a bank, and less than 10 percent of the urban poor. Credit from informal sources tends to be costly. In the Udaipur survey, people who live on less than 99 cents a day pay an average of 3.84 percent per month (equivalent to an annual rate of 57 percent) for credit they receive from informal sources.

To eradicate poverty, from the 1960s to the late 1980s, many developing countries had Government-sponsored credit programs, usually at subsidized interest rates, are targeted at the rural poor. For example, in India starting in 1977, for every branch the bank opens in Medina, the bank had to open four additional branches in rural areas that did not have a bank. Moreover, banks have been directed to lend 40 percent of their investment portfolios to the "priority sector": small companies, agriculture, cooperatives, and the like.

Conclusion

Abhijit Banerjis " Weak Economics " is a book about the extremely rich economy that comes out of an understanding of the economic life of the poor. In the end, it is about what the lives of the poor tell us and their choices about how to fight poverty in the world. This helps us understand why the poor often end up with health care that harms them more than they benefit; why can children of the poor go to school year after year and not learn anything; why the poor do not want health insurance. It reveals why the magic lead that happened yesterday ended up like today's failed ideas. His ideas in this book also tell a lot about where hope lies: why symbolic benefits may have more than just symbolic effects; how to improve market insurance; why less may be more in education; why good jobs are important to growth. Above all, it explains why hope is vital and knowledge critical, and why we have to keep trying even when challenges are enormous. Success is not always as far away as it seems.

In less than two decades, the experimental microeconomic approach devised by Banerjee, Dufflo and Kremer changed how development economists conduct their research. Research conducted using their experimental method revealed a wide range of new, substantive results and maintains an improvement in our ability to reduce poverty in the world.

References:

- [1] Weakness of the Economy, Abhijit Banerjee and Esther Duflo, Public Affairs, New York, 2011
- [2] <https://www.indiatoday.in/india/story/nobel-prize-winner-abhijit-banerjee->
- [3] <https://www.business-standard.com/article/economy-policy/in-economics>
- [4] https://en.wikipedia.org/wiki/Abhijit_Banerjee
- [5] <https://www.nobelprize.org/uploads/2019/10/advanced-economicsciencesprize2019.pdf>
- [6] <https://www.poverty-action.org/people/abhijit-banerjee>



23	भारतीय लोकसंख्येचा विकासक्रम	प्रा. डॉ. रवि एस. सोरोते	99
24	महात्मा गांधीचे आर्थिक विचार	प्रा. डॉ. ममता आर. साहु	106
25	वस्तु व सेवा कर : कार्य, फायदे व त्यासमोरील समस्या	प्रा. डॉ. विजय के. बनसोड	108
26	उदारीकरण, खाजगीकरण व जागतिकीकरण आणि भारतीय अर्थव्यवस्था	प्रा. विलास कांबळे	110
27	भारतीय महापुरुषांचे आर्थिक विचार	प्रा. वैशाली योगराज भेले	113
28	ग्रामीण विकास-एक अर्थनीती	प्रा. प्रशांत जगदीश वाल्देव	117
29	भारतीय अर्थव्यवस्थेतील आव्हाने (बेकारीच्या संदर्भात)	डॉ. लगवती रामदास टेंभुर्णे	120
30	वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्थेत रोजगारीचा प्रश्न	डॉ. मृणालिनी नरेन्द्र तापस	123
31	डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे भारतीय शेती विषयक विचार	प्रा.एल्.एस्. सिताफुले	128
32	वर्तमान आर्थिक मंदी व भारतीय अर्थव्यवस्था: एक विश्लेषण	डॉ. सुनिल शिंदे	132
33	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे भारताविषयक आर्थिक विचार	डॉ. स्वाती शिवदास शंभरकर	136
34	वर्तमानस्थितीत लोकशाहीपुढील आव्हाने व उपाय	डॉ. प्रमोद शंभरकर	139
35	पर्यावरणीय तत्वावर आधारित अर्थव्यवस्थेची पुनर्रचना करणे ही आधुनिक काळाची एक गरज	प्रा. डॉ. सिध्दार्थ झा : नागदिवे	142
36	छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आर्थिक धोरण	प्रा.स्वप्निल एस. बोबडे	145
37	भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की भूमिका	चंदा आनंद बोरेकर / डॉ. करमसिंग राजपूत	149
38	राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आणि महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आर्थिक विचारांची समर्पकता	प्रा.नलिनी विठ्ठल पाचर्णे	153
39	निवडक भारतीय महापुरुषांचे आर्थिक विचार	कु. उज्वला गिरीधर नागोसे	157
40	ग्रामीण विकास —एक अर्थनीती	प्रा. नरेंद्र के. पाटील	161
41	भारतीय महापुरुषांचे आर्थिक विचार.	प्रा.डॉ. विनोद झामा मोरे	165
42	भारतीय शेतीतील आव्हाने आणि इस्पायल कृषी तंत्रज्ञान	प्रा. डॉ.संजय मारोतराव महाजन	174
43	भारतीय अर्थव्यवस्थेत वस्तु व सेवा कराचा प्रवास	सहा. प्रा. मडावी ए. डी.	178
44	विनोबांचे ग्रामिण अर्थव्यवस्था, ग्रामोद्योग व श्रमप्रतिष्ठेविषयी विचार	प्रा.डॉ.दीपक लोणकर	182
45	अर्थतज्ञ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे आर्थिक विचार	प्रा. राहुल मोरेश्वर लभाने	184
46	केंद्रीय बँकेची स्वायत्तता व बँकाच्या विलीनिकरणाची समस्या	प्रा. रविंद्र श्रीराम कोरे	188



47	राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांचे आर्थिक विचार	प्रा.डॉ.मनिषकुमार काशिनाथ कापरकर	191
48	अल्पभूधारक शेतकरी व नायार्डची स्वयंसहायता गट योजना - एक आर्थिक अध्ययन	प्रा. गजानन एस. जाणे	196
49	वस्तू व सेवा करप्रणालीचे फायदे व तोटे	प्रा.डॉ.राजेश्री अ.जाधव	202
50	भारतातील दारिद्र्याचे कारणे व उपाय - योजना	प्रा. संतोष चंपतराव गोहोकार	205
51	भारतीय अर्थव्यवस्थेतील मंदीसदृश स्थिती व नाविन्यतेला चालना	डॉ.अनिल गायकवाड	207





वर्तमानस्थीतीत लोकशाहीपुढील आव्हाने व उपाय डॉ.प्रमोद शंभरकर सरदार पटेल महाविद्यालय,चंद्रपूर

प्रस्तावना

लोकशाही ही आजचा युगधर्म बनला आहे. लोकशाही राजवटीचा विचार एक नैतिक विचार म्हणून आजच्या मानवी समाजाने स्वीकारला आहे. लोकशाही विचाराचे मुळ प्राचीन काळातील विचारवंतांच्या सर्जनशील शक्तीमध्ये सापडतात. लोकशाही विचार सुमारे २५०० वर्षांपूर्वी ग्रीस मध्ये प्रथम उदयाला आला. २५०० वर्षांपूर्वीची ग्रीस मधील लोकशाही व आधुनिक लोकशाही यांमध्ये लोकशाहीचा तत्व विचार जरी समान असला तरी या लोकशाहीच्या स्वरूपांमध्ये फरकही पुष्कळ आहे. ग्रीक लोकशाही प्रत्यक्ष लोकशाही होती. आजची लोकशाही अप्रत्यक्ष लोकशाही वा सांसदीय लोकशाही आहे. औद्योगिक कातीनंतर मुख्यतः आजच्या प्रतिनिधीक वा सांसदीय लोकशाहीचा उदय झाला. आजची आपली लोकशाही समतेवर उभारली आहे. आधुनिक लोकशाहीत प्रत्येक व्यक्तीचे जीवन प्रतिष्ठित मानली जाते. सर्वच व्यक्ती जन्मतः मारुण्याच असतात अशाच लोकशाहीची धारणा आहे.

गुहांक

व्यक्तिस्वातंत्र्य, आर्थिक व सामाजिक विकास कार्यक्रम, विकास योजना व प्रशासनिक संरचना;

अर्थ : लोकशाही म्हणजे सहजीवनाने राहण्याची एक पध्ती. लोकांनी लोकशाही हिताकरीता लोककरीता चालविलेली राज्य म्हणजे लोकशाही.भारतामध्ये लोकशाही रामान प्रणाली व.याच काळापासुन अस्तित्वात आहे. लोकशाही व्यवस्था अधिक कार्यक्षम बनविणे आवश्यक आहे.

उद्देश

१. भारतीय लोकशाही चांगल्या पध्तीने अमलबजावणी करणे.
२. लोकशाहीत चांगल्या मार्गांचा अवलंब करणे.

आव्हाने

न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि सभुता यांचा लाभ सर्व नागरिकांना व्हायला हवा याचीच वेचेनी तरुणात आहे. चांडगाई आणि दहपराहीने ही वेचेनी मणुष्यात येणार नाही हे अपयश पदरातनपडण्याचे आव्हान आहे. देशाभर सर्वत्र परराष्ट्रत्वा बहुरम्य गरीब दुबळ्यांची स्थिती वर्षानुवर्षे वाढतच आहे. यावर राजकीय आणि आर्थिक धोरण बदलण्याचे खरे आव्हान आहे.

राखीव जागांचा पैघ

शिक्षण नौक.या यामध्ये राखीव जागा मरुलती याची तरतुद करून पेण्यासाठी बाबासाहेबांनी महत्त्व दिले.पुर्वी मणुष्या या पध्तीने जो कोटा मिळाला तो ६० ते ७० आधुनामुन आहे.जर असुपरयता मनातुन गेलेली असेल तरी या मरुलतीचा पुनर्विचार करण्याची गरजआहे. अशी युवकांची मतप्रणाली आहे. राखीव जागा कोटा यावर मुख्यतत्वे करून आधारलेला पुर्वामुश्य या कमेटीचा विशेष विकास व सहाय्य योजनासाठी वापर करण्यावर आधारलेला समाजकारण,राजकारण,अर्थकारण,यामुळे पुर्वामुश्य मटल समाविष्ट विधीन जातीय व्यक्ती आपली जातपात विसरून जातीय अस्मितीया त्याग करून एकत्र आली नाही. शिक्षण नौक.या चाक.या निवडणुका यारून उपस्थित झालेल्या स्पर्धामुळे जातीय बैठक अधिक आग्रही व पक्की झालेली आहे. दुबळ्या साधन विहित जातीना खरी मुक्तता मिळू शकली नाही. समाजाच्या सर्व वर्गांमध्ये जातीजातीमध्ये एक नैतिक सहमती निर्माण करण्याची गरज आहे.एका मर्यादीत अर्थाने भारतीय राज्यपटना हा १९५० च्या सुमारास अस्तित्वात असलेल्या अशा नैतिक सहमहतीचा अविष्कार होता.

व्यक्तिस्वातंत्र्य व्यक्तिस्वातंत्र्य म्हणजे केवळ शासनाच्या हस्तधेपापासुन मुक्तता असा सक्तुचित अर्थ नाही. तर व्यक्तीची सामाजिक व आर्थिक शोषणापासुन मुक्तता असा घेतला जातो. त्यामुळे प्रचलित सामाजिक व्यवस्था जर असे शोषण होण्यास पोषक असेल तर ती बदलणे हेही शासनाचे व समाजाचे कर्तव्य आहे. हा ही विचार व्हावयास हवा को केवळ आर्थिक प्रश्न मुरल्याने माणुस सुखी होत नाही. अन्न,वस्त्र,निवास हे जसे महत्वाचे आहे तसेच व्यक्तीने स्वातंत्र्यही महत्वाचे आहे.भाषण स्वातंत्र्य, सभा समेलनाचे स्वातंत्र्य, संपटना स्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य त्याचा प्रसार करण्याचे स्वातंत्र्य, व्यक्तीच्या जिवनाला पुर्णत्व आणतात. व्यक्तीला दारिद्र्यापासुन व अज्ञानापासुन मुक्त केल्याशिवाय माणसाला वरील स्वातंत्र्य उपभोगता येणार नाही



वैचारिक बैठकीचा अभाव नव्या समाजाची घडण करायची तर माणुस घडविणे हे सगळ्यात कठीण आणि महत्वाचे लोकशाही आणि समाजवाद तसेच धर्मातील राष्ट्र ही उद्दिष्टीये जर खऱ्या अर्थाने साध्य व्हायला हवी असतील तर या उद्दिष्ट्याना अभिप्रेत असलेली मुख्य समाजात रुजवावी लागतात केवळ लोकशाही किंवा समाजवादी संस्थांमार्फत घ्यावे लागतील ही ध्येये साध्य होत नाही. हा भारतापुरता तरी अनुभव आलेला आहे. आपल्या पंचवार्षिक योजनेतून या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात आला. परंतु आज समाजातील आर्थिक विपत्ती वाढलेली दिसते. सरजामशाही संस्था जरी नष्ट झाल्या तरी आर्थिक विपत्ती बेसुमार वाढली काही मुठभर लोकांच्या हातात बेसुमार पैसा आहे. बहुसंख्य जनता दारिद्र्यरेषेखाली आहे आजचे धिब्र आहे. काळ्या पैशाचे वर्चस्व बेसुमार वाढले आहे. सामाजिक बाबतीतही पुनरुज्जीवनाची विचारांना आज प्रतिष्ठा येऊ पहात आहे. धर्म यांचे वर्चस्व समाजजिवनात वाढत आहे. दलितवादाचे अत्याचार यांचेही प्रमाण वाढते आहे. या सर्वांचे कारण आर्थिक व सामाजिक परिवर्तनाला फार मोठ्या सामाजिक प्रबोधनाची गरज आहे. लोकशिक्षणामार्फत प्रबोधन होते. शासनाच्या मार्फत सर्व होणार स्वप्नाला मशगुल झालेल्या समाजात असे लोकशिक्षण मागे पडते, अशा ३० वर्षांचा अनुभव आहे. विधानसभा राजकीय पक्ष हे सर्वच हे लोकशाही प्रक्रिया एक कर्मकांड म्हणूनच राखत आहे. त्या प्रक्रियेमागे जो वैचारिक बैठक असायला हवी तिचा अभाव आहे.

आर्थिक व सामाजिक विकास कार्यक्रम आपल्या आर्थिक विकासाच्या कार्यक्रमांमध्ये पुढील १० वर्षां मध्ये सर्वात जास्त प्राधान्य शेतीला मिळाले पाहिजे. कारण आपल्या एकुल राष्ट्रीय उत्पन्नापैकी जवळजवळ ५४ टक्के उत्पन्न शेतीमधून येते. आपले राष्ट्रीय उत्पन्न वाढवायचे असेल तर आपल्याला शेतीवर अधिक लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. सामाजिक लोकशाही आर्थिक लोकशाही रुजविण्यासाठी राष्ट्रीय उत्पन्न वाढवित असताना त्यांची योग्य प्रकारे विभाजन करणे अशी दुहेरी काम करावयाचे आहे. राष्ट्रीय उत्पन्न वाढवायचे असेल तर शेती सारख्या अर्थव्यवस्थेवर भर दिला पाहिजे कारण ५० टक्के उत्पन्न केवळ या एका अर्थव्यवस्थेतून देशाला मिळत आहे. ७० टक्के लोक या अर्थव्यवस्थेवर गुजराण करीत आहे. गरीबी बेरोजगारी शेतकऱ्याच्या कर्जबाजारीपणा कमी होण्यापेक्षा वाढतच आहे.

बहुसंख्य शेतमजूर, लहान शेतकरी, भुमीहिन लोक, रोजंदारी मजूर व सालदार आदि दुर्बल घटक यापासून वंचित राहिले. त्यांच्या विकासासाठी शेती व्यतिरिक्त तिच्याशी निगडित शेतीला पुरक व पोषक उरतील अश्या इतरही अन्य मार्गांनी जनतेसाठी किफायतशीर व उत्पादक रोजगारी ग्रामीणभागातच निर्माण करून ती सर्व अपेक्षित लाभाध्यापर्यंत कशी पोहोचेल यावर गंभीरपणे विचार केला तरच देशाच्या कृषी व कृषीवर आधारित उद्योगातून होऊन ग्रामीण विकासात त्याचे मोलाचे योगदान मिळू शकेल.

कृषी उद्योग विकास:

शेती विकासाकडे जेवढे लक्ष दिले गेले तेवढे कृषी उद्योगाच्या विकासाकडे दिले गेलेले नाही. साखर उद्योग सोडले तर अन्य कृषी उद्योग वाढीसाठी सहेतुक व अर्थपूर्ण प्रयत्न झालेले दिसत नाहीत. कृषी उद्योगाच्या आपले आर्थिक उत्पन्न वाढवून राहनिमान उंचावू शकतो. कृषी उत्पादन कच्च्या माल यावर लवकरात लवकर प्रक्रिया होणे गरजेचे असेते. कारण ते नाशवंत असते. त्यासाठी यांत्रिकीकरणालाही प्रोत्साहन दिले पाहिजे. कृषी आधारित उद्योग शुष्म पद्धतीचे नियोजन आणि सातत्यपूर्ण संशोधनावर आधारित तंत्रज्ञान आवश्यक असून असे तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी उत्तम नियोजन आवश्यक आहे. कच्च्या मालाची साठवण आणि वाहतुकीची सुविधा गुणवत्तापूर्ण ठेवणे महत्वाचे आहे. प्रक्रिया करतांना स्वयंचलित यंत्रणा उभारण्यास उद्योग क्षमतेत वृद्धी होऊ शकेल. भविष्यातील फळ प्रक्रिया उद्योगातील प्रचंड संधी पाहता राज्यात फळाची उत्पादकता वाढविण्यावर भर देण्यासाठी शेतकऱ्यांनी नवतंत्रज्ञानाचा उपयोग केला पाहिजे.

औद्योगिक विकास शेती विकासावर अवलंबून:-

देशातील औद्योगिक विकासासाठी देखिल शेतीचा विकास झाला पाहिजे. शेतकरी व शेतमजूर यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारली तर त्यांची माल विकत घेण्याची ताकत वाढेल ही जास्त जेवढी वाढेल तितका पुरवठा वाढविण्यासाठी उत्पादन वाढेल. शेतीच्या विकासाबरोबर औद्योगिक विकासावर भर दिला पाहिजे. उद्योगधंद्याचे व्यवस्थापन योग्य पद्धतीने औद्योगिक विकास साधता येईल. कमी भांडवलता भरपूर मनुष्यबळाचा वापर मनुष्य संपत्तीचा उपयोग करणारी यंत्रणामुग्री आम्ही शोधून काढली पाहिजे. आमच्या सर्व औद्योगिक प्रगतीच्या कल्पना तयार झाल्या पाहिजे. आमच्या संशोधकांना व नेतृत्वाला हे मोठे आव्हान आहे असे समजून आम्हाला या प्रश्नांचे उत्तर शोधले पाहिजे.

विकास योजना व प्रशासकिय यंत्रणा:

लाचलुचपत दिरंगाई लोकविमुखता या सारखे दोष वाढत गेले तर नागरिकांतील असंतोष वाढत जातो व वैफल्याच्या भावनेतून लोकशाही अडचणीत येते. सामान्य माणसाचा लोकशाहीवरिल विश्वास विचलित होईल. लोकशाहीच्या सुरक्षिततेसाठी व संवर्धनासाठी येथिल कारभार यंत्रणेच्या सर्वच अंगाची सुधारणा करण्याऐवजी सामान्य माणसाच्या जीवनाशी जास्तीत जास्त संबंध येणाऱ्या अशा ३-४ खात्यांची सुधारणा करण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित केले



पाहिजे. शिवाय कारभार यंत्रणेच्या सुधारणेला सुरवात करून म्हणजे सचिवापासुन करावी लागेल. आपल्याला त्वरीत व अल्पकाळात उपयोगी पडणाऱ्या व मध्यम लहान स्वरूपाच्या धरण योजनांवरच भर दिला पाहिजे.

लोकसंख्या नियंत्रण: -

भारतातील वाढती लोकसंख्या हा केवळ येथील आर्थिक विकासाचाच नव्हे तर लोकशाहीला देखील धोका आहे. गेल्या काही पंचवार्षिक योजनांमुळे शेती व उद्योगधंदे या क्षेत्रात प्रगती करून उत्पन्न वाढविले याचा फार मोठा वाटा वाढत्या लोकसंख्येने खाऊन टाकला. शेतीचे उत्पन्न दरवर्षी साडेतीन टक्क्यांनी वाढते आहे व लोकसंख्या अडीच टक्क्यांनी वाढत आहे. सध्या भारतात दरवर्षी एक कोटी वीस लाख लोकसंख्या वाढते. लोकसंख्या वाढीच्या या दराने आपण आर्थिक विकास कसा लवकर साधू शकू. लोकसंख्येचा प्रश्न आपल्या आर्थिक विकासाशी दुसऱ्या एका महत्वाच्या बाबतीत संबंध आहे. सर्वच विकसनशिल- राष्ट्रांमध्ये आर्थिक विकास भांडवल निर्मातीवर अवलंबून आहे. भारतात भांडवलाचा अभाव आहे. लोकसंख्येचा प्रश्न सुटला नाही तर पुढील काही वर्षात आर्थिक विकासाचा नव्हे तर लोकशाहीला धोका निर्माण होईल.

अन्नधान्याची आयात वाढली पाहिजे:-

भारत हा कृषीप्रधान देश आहे. भारतातील साठ टक्के लोक ग्रामीण भागात शेती करतात. तरी देखील अन्नधान्यासाठी आज परदेशावर अवलंबून आहोत. राष्ट्रीय अस्मितेलाही बाब शोभणारी नाही. भरपूर शेतीलायक जमिन, मनुष्यबळ, हवामान असूनदेखिल अन्नधान्याच्या बाबत दुसऱ्या देशाकडे मागणी करावी लागते. ही बाब कृषी व्यवस्थापनातील उणिवांमुळेच घडत आहे. अन्नधान्यासाठी दरवर्षी भारताचे कित्येक कोटी रुपये परदेशी जात आहे. परकिय चलनाच्या दृष्टीने एवढी मोठी रक्कम वाचविणे आवश्यक आहे. भविष्यात एखादे युद्ध भडकले तर युद्ध काळात अन्नधान्यासाठी परकीय राष्ट्रांवर अवलंबून राहणे अधिक अडचणीचे होऊन बसेल. अशा वेळी देशात अशांतता व गोंधळ निर्माण होण्याचा संभव आहे. या दृष्टिने शेतीच्या प्रश्नाकडे आपल्याला पुढील पाच दहा वर्षात अधिक लक्ष पुरविले पाहिजे.

निकष :

या पुढील काळात देशातील वेगवेगळ्या आर्थिक, राजकीय, समस्या सोडवीत असतांना आपण सैध्यांतिक भूमिका पेशा व्यवहारिक, वास्तववादी बनली पाहिजे. उत्पादन क्षेत्रात पारंपारिक जुने तत्व सोडून मागणी येईल. त्याप्रमाणे मागणीचा विचार करून पुरवठा ठरविला असे मार्केटिंगचे तंत्र वापरले पाहिजे. दुसऱ्या महायुद्धापूर्वी साम्यवादी जग व लोकशाही जग यांच्यामध्ये अनुल्लेखनीय अंतर वाढत होते. ते आता क्षपाट्याने कमी होत असून दोन्ही व्यवस्था एकमेकांच्या जवळ आल्या आहेत. अशा या काळात कोणत्याही तत्व प्रणालीचा पोधीनिष्ठ सैध्यांतिक आग्रह न धरता व्यवहारिक भूमिकेवरून आपल्या प्रश्नांचा विचार केला पाहिजे. व्यक्ति स्वातंत्र्य, समता वा मूलभूत मुल्यांबाबत आपल्याला तडजोड करता येणार नाही. कारण ही शाश्वत मुल्ये आहे. परंतु निरनिराळ्या सामाजिक, आर्थिक, राजकीय प्रश्नांचा विचार करतांना गुंतागुंत निर्माण न करता सोडवू शकू. त्यातूनच उद्याची विकसित लोकशाहीचे भवितव्य घडवू शकू.

संदर्भ सूची:

१. मा. प. मंगुडकर, 'भारतीय लोकशाही: काही विचार'
२. प्रा. पि. ल. एरंडे, 'लोकशाही अपेक्षा आणि वास्तव'
३. डॉ. श्री. प्र. कुलकर्णी, डॉ. शुभा साठे(संपादक), 'भारतीय राजकारण दशा आणि दिशा'
४. भोळे भास्कर लक्ष्मण, 'भारतीय गणराज्याचे शासन आणि राजकारण'
५. डॉ. पी. डी. देवरे, भारतीय लोकशाही
६. दैनिक लोकमत
७. दैनिक सकाळ
८. दैनिक महाराष्ट्र टाईम्स